M.P./BHOPAL/642/2018-20

- कमलनाथ का विकल्प कौन?
- फिर उठी अलग राज्य की मांग

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

मंत्रियों की रेटिंग

वर्ष 19, अंक-6 16 से 31 दिसंबर 2020 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

R.N.I. NO. HIN/2002/8718

किसानों के असली मर्ज भी तलाशिए

Anu Sales Corporation
We Deal in Pathology &
Medical Equipments
Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
M. : 9329556524, 9329556530,
E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

मप्र भाजपा

9 | सिंधिया का रूतबा बढ़ा

मप्र में अपना लोहा मनवा चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से ज्यादा बड़ा रुतबा भाजपा में जमा लिया है। जहां भाजपा में शामिल होते ही सिंधिया ने अपने समर्थक एक दर्जन नेताओं को पूर्व विधायक होते हुए भी शिवराज...

राजपथ

10-11 | मंत्रियों की रेटिंग

दूध का जला जिस तरह छांछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए...

चौसर

13 | सज गया अखाड़ा

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव का अखाड़ा सज गया है। राजनीतिक पार्टियों के पहलवान दंड पेलने लगे हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा नहीं की है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी माह नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा करना चाहता है...

स्मार्ट सिटी

15 | हड़बड़ी में प्लान

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में प्रदेश में अव्वल और देश में दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन भोपाल स्मार्ट सिटी के प्लान में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। जिससे यह साबित हो रहा है कि अधिकारियों ने हड़बड़ी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। इसकी वजह है सरकार की नीति और नीयत में अंतर। इसी का परिणाम है कि आजादी के 73 साल बाद भी देश का किसान खुशहाल नहीं हो पाया है। सरकार ने किसानों में खुशहाली लाने के लिए जिस नए कृषि कानून को लागू किया है, उसे किसान कॉरपोरेट हितैषी मान रहे हैं। इस कानून के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार की एक नहीं सुन रहे हैं।

12

14

35

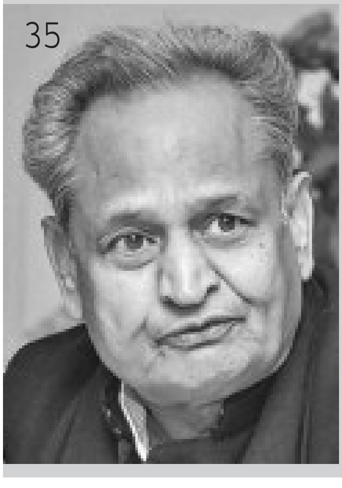

45

सियासत

32-33 | सांसद निधि पर नकेल जरूरी

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सांसद क्षेत्र विकास निधि के तहत होने वाले कार्यों को दो साल के लिए बंद कर दिया है, परंतु आने वाले समय में उसको इस मामले में कोई दो टूक निर्णय करना पड़ेगा। यानी इसे दोबारा शुरू किया जाए या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए।

महाराष्ट्र

36 | संगठित हो रही भाजपा

महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 2019 में हुए चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा के कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं को पूरा भरोसा था कि उनकी पार्टी 288 सदस्यीय सदन में 135-140 सीटें जीतने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। नतीजों ने सारी...

बिहार

38 | भंवर में नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार के शपथग्रहण के बाद कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, कैबिनेट की पहली बैठक अब तक नहीं हुई है। नीतीश को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना भी अभी बाकी है, जिसमें वह जदयू और भाजपा...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

महामारी से घातक महादलाली

किसी शायर ने लिखा है...

डूबी है मेरी उंगलियां मेरे ही खून में,
ये कांच के टुकड़ों पर भरोसे की सजा है...

इसी तरह लोग भरोसा करके कोरोना महामारी के इस दौर में प्लाज्मा की महादलाली के शिकार हो रहे हैं। दरअसल, कोरोना महामारी की आपदा कई लोगों के लिए कमाई का अवसर बन गई है। खासकर वे संस्थान जहां लोग भरोसे के साथ जाते हैं। इन्हीं में शामिल हैं अस्पताल और ब्लड बैंक। अस्पतालों में कोरोना महामारी के नाम पर लोगों से तो खूब वसूली हो ही रही है, अब प्लाज्मा की भी महादलाली होने लगी है। महामारी में यह घातक महादलाली लोगों की जान से खिलवाड़ है। माना देश-दुनिया में कोरोना महामारी ने करोड़ों लोगों को चपेट में लिया, लेकिन जान अधिकांश उन्हीं की ली जो गंभीर बीमार थे या फिर उम्र के अंतिम पड़ाव में थे। अधिकांश मरीज कुछ दिन के उपचार और एहतियात से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट गए। महामारी ने कमर जरूर तोड़ी, पर महादलाली तो मरीजों की जान ही ले रही है। हाल ही में कोरोना मरीज की मौत के मामले में प्लाज्मा को लेकर निजी अस्पताल से लेकर सरकारी व निजी लैब तक के बीच महादलाली के तार बिछे नजर आए हैं। नमक का पानी मिलाकर मिलावटी प्लाज्मा बनाने वाला अजयशंकर त्यागी हो या पांच लाख की घूस लेने वाला सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा, ये तो मुखौटा मात्र हैं। क्या सरकारी, क्या निजी हर विभाग-दफ्तर में महादलाली जारी है। अब बोले कौन, क्योंकि नोट के पत्तों का पान तो मुंह में सभी दबाए बैठे हैं। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से दतिया निवासी कोरोना संक्रमित मरीज मनोज कुमार गुप्ता की मौत से उठे सवालों ने कोविड अस्पतालों और संक्रमितों के इलाज के पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। गिरोह के सरगना अजयशंकर त्यागी सहित चार लोगों के हिरासत में आने के बाद भी प्रशासन को यह नहीं पता चल सका है कि घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से कितने मरीजों की जान गई। जबकि त्यागी ने पुलिस की पूछताछ में 150 यूनिट प्लाज्मा कोरोना मरीजों को देना कुबूल किया है। ये प्लाज्मा उसने खुद ही तैयार किए थे। गंभीर बात ये है कि प्लाज्मा कांड उजागर होने के पांच दिन बाद भी प्रशासन ने कोविड अस्पतालों से प्लाज्मा थैरेपी का रिकॉर्ड तक नहीं मांगा है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि अब हम रिकॉर्ड लेंगे और मौतों की जानकारी हासिल करेंगे। कोरोना संक्रमित ग्वालियर ही नहीं अंचल के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती हुए। इनमें कई मरीजों को प्लाज्मा थैरेपी दी गई। ये तो महज वे मामले हैं जो सामने आए हैं। प्रदेश सहित देशभर में ऐसे न जाने कितने प्रकरण होंगे जो मानव की लिप्सा को दर्शाते हैं। दरअसल, आपदाकाल में भी मनुष्य अपनी कमाई का कोई जरिया नहीं छोड़ रहा है। यह खतरनाक संकेत है। मप्र में कोरोना महामारी के नाम पर लोगों के साथ किस तरह ठगी की गई इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार को इनपुट मिले हैं कि प्लाज्मा के साथ ही अब प्रदेश में नकली कोरोना वैक्सीन की भी बिक्री की जा सकती है। इस इनपुट के बाद सरकार ने सजगता बढ़ा दी है। लेकिन केवल सरकार की सजगता से ही काम नहीं चलने वाला है। आमजन को भी जागरूक होना होगा। वरना आपदा-विपदा में भी महादलाली का खेल चलता रहेगा।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 6, पृष्ठ-48, 16 से 31 दिसंबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2018-20

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता**:- इंद्रकुमार, **जयपुर**:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़**:- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21 नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksharnews.com

हल निकालना जरूरी

कोरोना ने बच्चों को घर पर ही रहने को मजबूर कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रायः देखने में आता है कि लड़के तो स्मार्ट फोन देकर पढ़ने को बिठा दिए जाते हैं और लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है। लड़किया पढ़ाई के समय में भी घरेलू काम करती हैं।

● **रमा भारद्वाज,** ग्वालियर (म.प्र.)

अर्थव्यवस्था का संबल

कोविड–19 की चुनौतियों से घिरी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। प्रसिद्ध वैश्विक ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत में चक्रीय आर्थिक सुधार ऊंचाई पर है परिणामस्वरूप वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.9 प्रतिशत होगी।

● **अनवर शेख,** इंदौर (म.प्र.)

सुशासन की ओर कदम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन के लिए जहां मंत्रियों के कामकाज को आकलन करने के लिए रेटिंग प्रणाली शुरू की है, वहीं अफसरों से कहा है कि अब हर माह एजेंडा दिया जाएगा, जिस पर काम करना होगा।

● **पंकज राठौर,** सीहोर (म.प्र.)

हैरत में डालता नये तेवरों का विरोध

हालिया किसान आंदोलन इस एक बात के लिए लम्बे अरसे तक याद किया जायेगा कि उसने किसानों से जुड़े कई परम्परागत मिथों, रूढ़ियों और छवियों को एक झटके में तोड़ डाला है। इस कदर कि बत्तीस साल पहले अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली के बोट क्लब में भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जमा हुए हुक्का गुड़गुड़ाते किसान भी गुजरे जमाने की चीज लगने लगे हैं।इससे राजधानी में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा यह कि विभिन्न राज्यों से आन्दोलन के लिए वहां पहुंचे किसान सूटेड–बूटेड क्यों हैं, उन्होंने मैली–कुचैली धोती क्यों नहीं पहन रखी? उनके हाथ में लाठी और कंधे पर गठरी क्यों नहीं है? वे इतने आत्मविश्वास से भरे हुए क्यों हैं और सहूलियतों के बजाय अधिकार मांगते क्यों फिर रहे हैं?

● **अभिराम कौशिक,** नई दिल्ली

सुशासन की ओर कदम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन के लिए जहां मंत्रियों के कामकाज को आकलन करने के लिए रेटिंग प्रणाली शुरू की है, वहीं अफसरों से कहा है कि अब हर माह एजेंडा दिया जाएगा, जिस पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फोकस एजेंडे पर काम करना है। रूटीन गवर्नेंस प्रभावित न हो, रोजमर्रा के काम ना रुकें। लोग परेशान ना हों। मुख्यमंत्री का यह कदम सुशासन की दिशा में एक कदम है।

● **सागर भैरव,** उज्जैन (म.प्र.)

तिब्बत में खतरनाक चीनी मंसूबों का बांध

दक्षिण–पश्चिम तिब्बत में बहने वाली यरलुंग त्सांगपो नदी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, दक्षिणी तिब्बत की कोंगपो घाटियों से गुजरते हुए यह दरिया अपने किनारों की उर्वरता से आबादी को जिंदगी प्रदान करता है। भारत–बांग्लादेश में दाखिल होने पर यह 'ब्रह्मपुत्र' के नाम से जानी जाती है। यहां भी यह करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की रोजी–रोटी का सहारा है। लेकिन इस ताकतवर नदी के बहाव को अब तिब्बत में बनने जा रहे विशाल बांध से खतरा हो गया है। इस किस्म की परियोजना से नुकसान होना अवश्यंभावी है।

● **सिद्धांत चक्रवर्ती,** कोलकाता (प. बंगाल)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भूले-बिसरे दोस्त आने लगे याद

नीतीश बाबू को भाजपा पर बिल्कुल भी भरोसा बाकी नहीं बचा है। उन्हें आशंका है कि कुछ समय बाद भाजपा उन्हें हटाकर अपने मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास जरूर करेगी। ऐसे में अब वे जदयू को मजबूती देने में जुट गए हैं। 26-27 दिसंबर को उन्होंने जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती देने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। साथ ही उन सभी जनाधार वाले नेताओं की घर वापसी का प्रयास भी सुशासन बाबू ने शुरू कर दिया है जो कभी लालू यादव के खिलाफ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों में तीसरे नंबर पर आने के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने वे सभी राजनीतिक मित्र याद आने लगे हैं जिन्हें लगातार मिल रही सफलता के दौर में बिहारी बाबू ने नाराज कर डाला था। ऐसे सभी नेताओं को अब जदयू में वापस लाने की मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू कर डाली है। खबर पटना के राजनीतिक गलियारों में गर्म है कि सुशासन बाबू अब इस कोशिश में लग गए हैं कि अपनी पार्टी के संगठन को फिर से मजबूत बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने पार्टी से मुंह मोड़ चुके नेताओं को फिर से वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि उनकी यह कवायद किस मुकाम पर पहुंचती है।

टूटने लगी है नींद

भाजपा के हाथों 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद उप्र के दो बड़े राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह अस्त-पस्त हो कुंभकर्णी नींद सो गया था। पिछले 4 सालों में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा की सर्वेसर्वा मायावती राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की सरकार को किसी भी फ्रंट पर घेरने में नाकाम तो रही हीं, प्रयास करती भी नजर नहीं आईं। इन चार बरसों के दौरान विपक्ष के पास एक के बाद एक ऐसे अवसर आए जिनके सहारे योगी सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक घेरा जा सकता था। लेकिन सोशल मीडिया में बयानबाजी करने के सिवा इन दोनों ही दलों के नेता कुछ ठोस एक्शन लेने में पूरी तरह विफल रहे। चाहे नागरिकता कानून में संशोधन का मुद्दा हो या फिर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, विपक्ष की भूमिका में इन दोनों दलों से कहीं अधिक सक्रिय प्रियंका गांधी वाड्रा के चलते कांग्रेस की रही है। सपा-बसपा की दुर्गति को हाथरस में दलित लड़की के बलात्कार कांड से समझा जा सकता है। लेकिन अब जैसे-जैसे आगामी विधानसभा चुनाव का साल नजदीक आते जा रहा है दोनों पार्टियों के मुखिया की नींद टूटने लगी है।

अब खुद मोर्चे पर राहुल-सोनिया

कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार, सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त पार्टी और परिवार के बीच सेतु का काम करने वाले अहमद पटेल की आकस्मिक मृत्यु से हत्प्रभ कांग्रेस आलाकमान अब खुद फ्रंट-फुट पर बैटिंग करने का मन बनाता नजर आ रहा है। अहमद पटेल लंबे अर्से से कांग्रेस के पुराने चावलों और युवा नेताओं के बीच आपसी तालमेल बैठाए रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इतना ही नहीं विपक्षी दलों के नेताओं और गांधी परिवार के मध्य भी वे एक मजबूत सूत्रधार थे। उनके निधन के बाद अब खबर है कि गांधी परिवार ने पार्टी नेताओं और विपक्षी दलों के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संवाद करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम्यूनिस्ट दलों के नेता सीताराम येचूरी और डी राजा से सीधे सोनिया गांधी ने बातचीत कर किसान आंदोलन के दौरान 8 दिसंबर को बुलाए गए 'भारत बंद' को विपक्षी दलों द्वारा समर्थन दिए जाने के लिए तैयार किया। सोनिया की पहल का ही नतीजा रहा कि 24 विपक्षी दलों ने इस बंद के पक्ष में अपील जारी कर डाली। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव व हेमंत सोरेन जैसे युवा विपक्षी नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि राहुल-सोनिया का यह प्रयास कितना सफल होता है।

कांग्रेस से मोहभंग

कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जनाधार और सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता में रहने वाली पार्टी हुआ करती थी। 90 के दशक से पार्टी का सिकुड़ना जो शुरू हुआ, वह अभी तक रुका नहीं है। कांग्रेस के इस पतनकाल में उसका साथ छोड़ने वालों में फिल्मी दुनिया की वे नायिकाएं भी शामिल हैं जिन्हें पार्टी ने राजनीति में आने का अवसर दिया था। तमिल की सुपरस्टार खुशबू सुंदर को कांग्रेस ने न केवल राजनीतिक मंच दिया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी सौंपा लेकिन कुछ माह पूर्व खुशबू ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद नंबर आया बॉलीवुड की अभिनेत्री उर्मिला मातोड़कर का। कांग्रेस इस सदमें से उबरी भी नहीं थी कि तेलुगु फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री विजयाशांति ने भी कांग्रेस से किनारा कर भाजपा का दामन थाम पार्टी नेतृत्व की बैचेनी बढ़ा डाली है। खबर है कि कभी राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रही कन्नड़ फिल्मों की नायिका दिव्या स्पंदना का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चला है।

दुविधा में रावत

उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी के दिग्गज नेताओं हरीश रावत, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश में पट नहीं रही है। खबर है कि पार्टी आलाकमान से अपनी सीधी पहुंच के चलते अब हरीश रावत भी प्रीतम-हृदयेश द्वय को पहली शिकस्त सल्ट उपचुनाव में देने वाले हैं। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु से रिक्त हुई सीट से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रंजीत रावत इस सीट से अपने बेटे को लड़ाने के इच्छुक हैं। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हरीश रावत आखिरी समय में विक्रम के नाम पर सहमत भी हो सकते हैं। रावत की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि यदि भाजपा स्व. सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को टिकट देती है तो निश्चित ही सहानुभूति की लहर के चलते भाजपा सीट जीत ले जाएगी। ऐसे में उपचुनाव में विक्रम रावत को परास्त करा पूर्व मुख्यमंत्री 2022 के चुनावों में उनकी और उनके बेटे की दावेदारी को पूरी तरह से चौपट कर सकते हैं।

आगे पाठ पीछे सपाट

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इन दिनों मप्र में यह कहावत चरितार्थ भी हो रही है। दरअसल, प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए सरकार के मुखिया ने कमर कस ली है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वे माफिया और गुंडों के खिलाफ अभियान चलाएं, ताकि प्रदेश में अमन-चैन का राज कायम हो सके। सरकार के मुखिया के निर्देश के बाद अफसर आनन-फानन में अभियान को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। प्रदेशभर में ताबड़तोड़ अभियान चलाकर माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी के मकान तो किसी की दुकान तोड़ी जा रही है। गुंडों और माफिया के खिलाफ सरकार का कदम सराहनीय है। लेकिन अफसर अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, वह सवालों के घेरे में है। क्योंकि इस अभियान के तहत एक आदमी की करनी का फल पूरी परिवार को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अभी तक सुख-चैन की जिंदगी जी रहे कई परिवार छत विहीन हो गए हैं। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इस बात की चर्चा है कि हमारे धर्म-ग्रंथों में लिखा है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। इसलिए सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिए थे ताकि माफिया और गुंडों पर गिरने वाली गाज का असर उनके परिवार या नाते-रिश्तेदारों के भविष्य पर न पड़े।

अस्पताल से परेशान

कोरोना संक्रमण के इस दौर में अस्पताल और डॉक्टर जनता के लिए बड़ा संबल बनकर सामने आए हैं। लेकिन कई ऐसे संस्थान और डॉक्टर हैं जो आपदा में भी केवल कमाई में ही व्यस्त हैं। राजधानी में ऐसा ही एक अस्पताल ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का चहेता बना हुआ है, जिसने कोरोना संक्रमण के नाम पर जमकर कमाई की है। आलम यह है कि इस अस्पताल में आने वाला मरीज यहां की व्यवस्था से परेशान है, लेकिन उनकी आवाज बिलकुल नहीं सुनी जा रही है। दरअसल, इस अस्पताल को नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण प्राप्त है। अत: जब सैय्या भए कोतवाल तो डर काहेका की तर्ज पर अस्पताल प्रबंधन भी मनमानी करता रहता है। जानकारी के अनुसार यह अस्पताल ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंचा है। आलम यह है कि इस अस्पताल में केवल नेताओं और नौकरशाहों की ही चलती है। किसी नौकरशाह के नाते-रिश्तेदार को नौकरी चाहिए या फिर इलाज यह अस्पताल इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। यही कारण है कि अस्पताल से भले ही आम जनता परेशान हो लेकिन नेता और नौकरशाह यहां की सेवाओं से हमेशा खुश रहते हैं।

अटक गई प्रशासनिक सर्जरी

उपचुनाव के बाद से ही प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है प्रशासनिक सर्जरी का संयोग नहीं बन पा रहा है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि नए साल में ही तबादलों का दौर शुरू होगा। गौरतलब है कि उपचुनाव के बाद संभावना जताई जा रही थी कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए विधायकों ने चुनाव परिणाम आने के साथ ही लॉबिंग शुरू कर दी थी। ऐसे में अफसरों ने भी मंत्रियों और भावी मंत्रियों की परिक्रमा शुरू कर दी थी ताकि उन्हें उनके मनमाफिक विभाग मिल सकें। विधायकों और अफसरों की सक्रियता को देखकर लगने लगा था कि प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी होगी। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। वहीं कोई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी नहीं हो सकी है। ऐसे में अफसर इस धैर्य के साथ बैठे हैं कि अब अगले साल ही प्रशासनिक सर्जरी हो पाएगी। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सरकार वर्तमान में कोई बड़ी सर्जरी करने के मूड में नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि नए साल में कई अफसरों का प्रमोशन होना है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि अफसरों के प्रमोशन के बाद ही प्रशासनिक सर्जरी की जाए, ताकि बदलाव की फिर कोई गुंजाइश न रह जाए। अब देखना यह है कि आखिरकार सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को कब हरी झंडी देती है।

परिवहन को लेकर पेंच

मप्र में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे तो एक बात यह तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के कद प्रभावित होंगे। सूत्रों की मानें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल और वर्तमान भाजपा सरकार में दमदार मंत्री रह चुके एक माननीय का कद तो निश्चित रूप से कम किया जाएगा। दरअसल, उक्त माननीय का पूरा फोकस परिवहन विभाग पर है। वह चाहते हैं कि मुझे किसी भी स्थिति में परिवहन विभाग तो मिले ही। लेकिन संघ इसके खिलाफ है। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों संघ की एक बैठक में इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई कि परिवहन विभाग से आने वाला हिसाब 2-3 महीने से गायब है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि इस विभाग में पदस्थ रहे पूर्व मंत्रीजी उक्त हिसाब को स्वयं ही जीम गए। इसलिए संघ ने पार्टी को साफ-साफ शब्दों में हिदायत दी है कि उक्त विधायक को किसी भी कीमत पर परिवहन विभाग न दिया जाए।

पूर्व विधायकों ने बढ़ाई चिंता

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। महापौर और पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी चरम पर है। भाजपा ने वर्तमान विधायकों को टिकट न देने का फॉर्मूला बनाया है। पार्टी का यह फॉर्मूला पूर्व विधायकों को काफी पसंद आया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई पूर्व विधायक महापौर बनने के लिए दावेदारी ठोकने लगे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महापौर का पद अनारक्षित होने से दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। पूर्व विधायकों के टिकट मांगने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि उपचुनाव में पार्टी ने जिस तरह अपने पूर्व विधायकों को दरकिनार कर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दे दिया उससे पार्टी में पहले से ही विद्रोह की आग सुलग रही है। अब अगर ऐसे में पार्टी पूर्व विधायकों को टिकट से वंचित करती है तो उसके परिणाम चिंतनीय हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसको देखते हुए पार्टी के रणनीतिकार टिकट वितरण की कोई ऐसी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

भाजपा को कोई दूसरा काम नहीं है। कभी गृहमंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं तो कभी नड्डा-फड्डा-चड्ढा-भड्डा और अपने कार्यकर्ताओं से नौटंकी करवाते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से अपने ऊपर हमला करवाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है।

● **ममता बनर्जी**

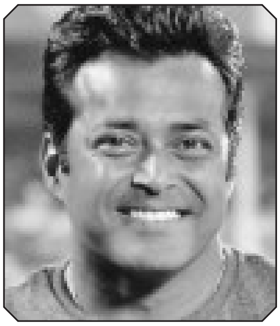

मेरे लिए ये बेहद जरूरी है कि भारत का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। इसलिए मैंने 30 साल तक खेलना जारी रखा। मेरे पास पहले ही 7 ओलंपिक खेलने का रिकॉर्ड है और अगर मैं 8 ओलंपिक खेलता हूं, तो मुझे विश्वास है कि भारत का नाम ओलंपिक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा कि किसी भारतीय ने 8 ओलंपिक खेले हैं।

● **लिएंडर पेस**

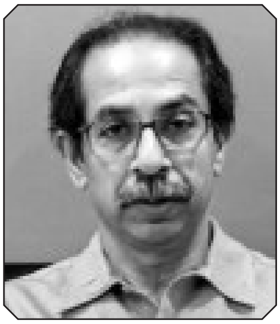

महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और गांवों में कुछ इलाकों के नाम जाति-आधारित हैं। जाति विभाजन पर आधारित नाम हमारे प्रगतिशील राज्य के अनुकूल नहीं हैं। यही सोचकर सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे सभी नामों को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे समाज में समानता का भाव आएगा।

● **उद्धव ठाकरे**

चीन एशिया के लिए सैन्य और आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा खतरा है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन एशियाई देशों के लिए आर्थिक और सैन्य रूप से सबसे बड़ा खतरा है। उसने इस क्षेत्र के 14 देशों के साथ समझौते किए हैं, लेकिन इससे संवेदनशील मामले हल नहीं होंगे।

● **बिलवर रोस**

डिप्रेशन महसूस करने की अवस्था है। मैं खुद से नफरत करने लगी थी और मुझे अपनी अच्छी सेहत पसंद नहीं थी। मुझे अच्छी होने के लिए तैयार किया गया। मुझे अच्छा होने के लिए मजबूर किया गया। आपको अपने अंदर के दानवों से टकराना होगा। आप बाहर नहीं देख सकते। आपको खुद को समय और ऊर्जा देना होगा। आपके दिमाग के केमिकल्स में उतार-चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से आप खराब महसूस करते हैं। हालात आपको ऐसा महसूस कराते हैं। छोड़ देना ठीक है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि जब आप झुकते हैं तो आपके पास उठने की क्षमता होती है। आप ठीक हो सकते हैं। अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी होती है।

● **शमा सिकंदर**

वाक्युद्ध

पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते जनाधार से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी घबराई हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं पर सुनियोजित तरीके से हमले करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसके समर्थन में है। वरना एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए।

● **कैलाश विजयवर्गीय**

भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का अभियान चला रखा है। जिस तरह भाजपा जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अस्थिर कर रही है, उससे जनता ही उसका विरोध कर रही है। जनता के आक्रोश को राजनीतिक द्वेष बताना भाजपा की फितरत हो गई है। वैसे किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता पर हमला अनुचित है।

● **रणदीप सुरजेवाला**

सिंधिया का रुतबा बढ़ा

राजनीतिक नियुक्तियों में संगठन की चलेगी

मप्र में हाल में हुए उपचुनाव से पहले यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि यदि चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो आगे राज्य में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी भाजपा की धुरी रहेंगे। मप्र की सियासत की दिशा भी इन्हीं दोनों दिग्गजों के अनुसार तय होगी, किंतु चुनाव के बाद स्थिति बिल्कुल उलट लग रही है। सत्ता और पार्टी दोनों की चाबी संगठन ने अपने हाथ में ले रखी है। राजनीतिक नियुक्तियों में जिस तरह शिवराज और सिंधिया की जोड़ी पर भाजपा संगठन हावी है उससे स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में कमान इन दोनों नेताओं के हाथ में नहीं रहेगी। संगठन में भी सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और हाल में भाजपा की ओर से प्रदेश प्रभारी बनाए गए मुरलीधर राव की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री भले ही बना दिया हो किंतु उनको वह स्वतंत्रता नहीं दी जो पिछले कार्यकाल में मिली हुई थी। उनको तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाना था लेकिन उनसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा पार्टी के पास कोई दूसरा नहीं था। चुनाव जीतने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया और अब चुनाव जीत गए है। इसके आगे शिवराज और सिंधिया दोनों की भूमिका सीमित रहने के आसार दिख रहे है। शिवराज सिंह को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाहर सब केवल पार्टी संगठन तय करेगा।

मप्र में अपना लोहा मनवा चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से ज्यादा बड़ा रुतबा भाजपा में जमा लिया है। जहां भाजपा में शामिल होते ही सिंधिया ने अपने समर्थक एक दर्जन नेताओं को पूर्व विधायक होते हुए भी शिवराज सरकार में मंत्री बनवाया था, वहीं अब अपने समर्थकों को उच्च पदों पर बैठाकर सिंधिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी राह आसान करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उपचुनाव में हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं इमरती देवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना तय है।

बता दें, इमरती देवी को इस्तीफा दिए लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका है लेकिन अब सियासी गलियारों में उनके पुनर्वास की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारों की मानें तो इमरती को ज्योतिरादित्य सिंधिया हर हाल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाने पर अड़ गए हैं। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी माना जाता है और भाजपा सिंधिया को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में माना जा रहा है कि इमरती देवी को महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना लगभग तय है।

अगर ऐसा होता है तो उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री स्तर का होगा और उनका राजनीतिक कद भी बरकरार रहेगा। इसका सीधा फायदा उपचुनाव में शिकस्त खा चुकी इमरती देवी को होगा। मंत्री दर्जा प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं है कि इसका फायदा केवल इमरती देवी को ही होगा, बल्कि भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य को भी होगा। सिंधिया अपने समर्थकों को पद दिलाकर स्वयं की भाजपा में सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी राह आसान हो सके।

गौरतलब है कि उपचुनाव में मिली हार के तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंसाना और कृषि राज्य मंत्री गिर्राज दंडोतिया ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर, हार के बावजूद इमरती देवी ने इस्तीफा नहीं दिया था जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद इमरती देवी ने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि उनका मंत्री रहना या न रहना सरकार और सिंधिया पर निर्भर करता है लेकिन ये भी सच है कि क्षेत्र का विकास उनके ही माध्यम से होगा। इसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि हर हाल में सिंधिया द्वारा बैकडोर से ही सही लेकिन इमरती देवी का पुनर्वास कराया जाएगा।

वहीं सिंधिया और उनके समर्थकों को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति घोषित होने का भी बेसब्री से इंतजार है। सिंधिया समर्थकों की खाली हुई तीन सीटों को उनके ही समर्थकों से भरा जाना तो निश्चित है ही, शेष रहे 8 समर्थकों को भी कहीं न कहीं एडजस्ट करने की भी कोशिश रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया 4-5 समर्थकों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में उम्मीद से ज्यादा मिली सफलता के चलते सिंधिया की किसी भी बात को ठुकराया जाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पार्टी आलाकमान के लिए भी मुश्किल होगा। उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही टीम की घोषणा करेंगे।

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा के सीनियर नेताओं को पद देकर संतुष्ट करना चाहते हैं, ताकि आगे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना या संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद पर भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इसकी वजह बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव हैं। बिहार के सकारात्मक नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सिंधिया को मंत्रियों की सूची में शामिल किया जाएगा।

बहरहाल मप्र में इमरती देवी को महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि महाराज सिंधिया का जलवा बरकरार है और वे अब अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 'टाइगर अभी जिंदा है।'

● **सिद्धार्थ पांडे**

अपनी चौथी पारी में शासन और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमर कस ली है। उन्होंने अफसरों पर नकेल तो कसी ही है, साथ ही मंत्रियों को भी अपनी रेटिंग बनाने की जिम्मेदारी देकर उन्हें सक्रिय कर दिया है। बेहतर रेटिंग के लिए अब मंत्री मुख्यमंत्री की तरह रात-दिन काम में लगे हुए हैं। यह मप्र के लिए सुखद संकेत है।

मंत्रियों की रेटिंग

दूध का जला जिस तरह छांछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को जनता की कसौटी पर कसने की तैयारी कर दी है। उन्होंने मंत्रियों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। सरकार अब हर माह मंत्रियों के कार्यों का आंकलन करेगी। मंत्रियों में काम के प्रति प्रतिस्पर्धा लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है। हर महीने विभाग के कामकाज को लेकर रेटिंग जारी की जाएगी। खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है।

दरअसल, शिवराज सिंह चौहान की कोशिश यह है कि 2023 में 2018 वाली स्थिति न बने। इसलिए उन्होंने शासन और प्रशासन को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी के तहत उन्होंने मंत्रियों और उनके विभागों की रेटिंग करवाने की व्यवस्था शुरू की है। मुख्यमंत्री की रेटिंग प्रणाली ने मंत्रियों को टेंशन में डाल दिया है। उन्हें रेटिंग की चिंता सताने लगी है। इसकी वजह यह है कि मंत्रियों को अपने बेस्ट रेटिंग के लिए मुख्यमंत्री की तरह कोल्हू का बैल (रात दिन काम करने वाला) बनना पड़ेगा। जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है।

मुख्यमंत्री मप्र में सुशासन के सहारे 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन के साथ ही शासन को भी चुस्त और दुरुस्त होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों को अधिक से अधिक समय जनता के बीच रहने और अपने विभागों के माध्यम से विकास कार्य कराने का निर्देश दिया है। मंत्री उनके निर्देश का पूरी तन्मयता से पालन करें इसके लिए उन्होंने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है। लेकिन इस प्रणाली ने मंत्रियों को चिंता में डाल दिया है। वजह यह है कि मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी रेटिंग अन्य मंत्रियों से बेहतर हो। गौरतलब है कि हर

मंत्रीजी का काम अच्छा नहीं तो जाएगी कुर्सी

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अनूठा तरीका ढूंढ़ा है। विस्तार में मंत्रियों की संख्या न बढ़ाकर मंत्री ही बदले जाएंगे। जिन मंत्रियों का कामकाज अच्छा नहीं होगा, उनकी कुर्सी जा सकती है। काम के आंकलन के लिए फील्ड टेस्ट और विभागीय परीक्षा मानक हैं। कामकाज की रेटिंग का फॉर्मूला खुद मुख्यमंत्री ने ही तय किया है। दरअसल, मंत्रियों की निष्क्रियता की शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही हैं। शिकायतें रहीं मंत्री मंत्रालय में कम समय देते हैं और फील्ड में भी केवल आयोजनों तक ही सीमित हैं। अतः अब मंत्रियों से कहा गया है कि फील्ड में वे यह भी देखें कि सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मंत्री अपने विभाग के मैदानी कार्यों की भी मॉनीटरिंग करें। इसलिए उन्होंने मंत्रियों की रेटिंग का निर्णय लिया है। मंत्रियों की रेटिंग और विभागीय समीक्षाएं सरकारी ढर्रा सुधारने की एक कड़ी है। अफसरशाही पर मंत्रियों की पकड़ कम मजबूत। अफसर अपने ही तरीके से काम न करें, इसलिए भी यह पहल की गई है। रेटिंग से यह पता चलेगा कि मंत्रियों की विभागों में कितनी पकड़ है और वे अपने विभाग में कितना समय दे रहे हैं।

सोमवार को मंत्री अपने विभाग के अफसरों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंत्री मासिक रिपोर्ट कार्ड में अफसरों से उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे। विभागीय योजनाओं के साथ-साथ केंद्र की योजनाएं कहां तक पहुंची है, इस पर भी संबंधित विभाग के मंत्री नजर रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के पास हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन पहुंचती है। इसी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे।

मंत्रियों के रेटिंग तय करने लिए मंत्री हर महीने मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में सभी कामों का जिक्र होगा। मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री सभी विभागों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे। उसी के आधार पर रेटिंग तय की जाएगी कि किस विभाग ने अच्छा काम किया है। अच्छा करने वाले लोगों को वाहवाही भी मिलेगी। इस रेटिंग प्रणाली में मंत्रियों के सामने असली चुनौती यह होगी, अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय के अंदर पूरा करवाएं। साथ ही जन सरोकार से जुड़ी जो योजनाएं हैं वह सही तरीके से लागू हो। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ लाभुकों तक असानी से पहुंचे, मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए उन्हें ग्राउंड लेवल पर भी मॉनीटरिंग करनी होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी

मंत्रियों को सलाह इनोवेटिव आइडियाज पर करें काम

मंत्रियों में काम के प्रति प्रतिस्पर्धा लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था के साथ ही उनसे दो टूक कहा है कि उन्हें नए-नए आइडिया पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें। मंत्री की लीडरशिप में सभी विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें और उनपर अमल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सोमवार को मंत्री विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। मंत्री तीन बातों का ध्यान रखें। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर काम शुरू हो गया है। सभी मंत्री इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में विभागीय निर्माणकार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मप्र को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करें। केंद्र सरकार के संपर्क में रहें, जरूरत हो तो दिल्ली भी जाएं।

चौथी पारी में रेटिंग प्रणाली लाने के पीछे वजह यह है कि वह चाहते हैं कि उन्हीं की तरह मंत्री भी मंत्रालय से लेकर जनता के बीच सक्रिय रहें। भाजपा के एक पदाधिकारी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मप्र में रेटिंग प्रणाली विकास की गति को रफ्तार देने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही इससे धन की बचत भी होगी। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि किसी पुल का निर्माण होना है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। समय निर्धारित किया गया है कि इसे छह महीने में पूरा कर लेना है। विभागीय शिथिलता की वजह से यह काम छह महीने में पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बजट बढ़ जाता है। इससे आर्थिक नुकसान के साथ ही लोगों की असुविधा भी बढ़ती है।

संघ के एक स्वयंसेवक कहते हैं कि शिवराज की रेटिंग प्रणाली से विकास को तो गति मिलेगी ही, साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगी। वह कहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह रही है 13 मंत्रियों की हार। वह कहते हैं कि शिवराज की तीसरी पारी में मंत्रियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर कुल 32 मंत्री थे। जिनमें से 27 ने चुनाव लड़ा था। 14 अपनी सीट बचाने में सफल रहे। भाजपा के लिए सदमे की बात यह हुई थी कि उसके 13 मंत्री तक अपनी सीट नहीं बचा सके हैं। अगर ये मंत्री अपनी सीट जीत जाते तो विधानसभा का नजारा अलग ही होता। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती थी। यहां जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि भाजपा ने टिकट आवंटन के समय फूंक-फूंक कर कदम रखे थे और अपने 5 मंत्रियों के टिकट भी काटने का साहस दिखाया था। जिससे लग रहा था कि टिकट उन्हें ही दिया गया है जिनमें जीतने की क्षमता है। लेकिन, 13 मंत्री तो हारे ही, साथ ही जो जीते भी हैं उनमें कई संघर्ष करके जीत पाए हैं। इसलिए शिवराज चाहते हैं कि 2023 में ऐसी स्थिति न बने इसलिए वे अभी से अपने मंत्रियों को सक्रिय रखना चाहते हैं।

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अपने मंत्रियों और आला अफसरों को लेकर 13 साल की अपनी तीन पारियों में सामान्यत: नरम रवैया अख्तियार करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई पारी में नए अंदाज में हैं। वह अब कामकाज में कोताही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, खासकर जनता से सीधे तौर पर जुड़े मामलों में। कई मौकों पर तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव के बजाय मंत्री को ही तलब कर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। नतीजा यह मिल रहा है कि अब विभाग प्रमुखों के साथ ही मंत्री भी अलर्ट रहने लगे हैं और मुख्यमंत्री का बुलावा उनके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। चुटकियों में कड़े फैसले, व्यवस्था की पड़ताल करने सीधे सड़क से सरकारी दफ्तरों का दौरा, वहीं अशांति की कोशिशों पर सीधे कार्रवाई। ये पहचान पिछले कुछ दिनों में बनी है मप्र की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग ही अंदाज में देखे जा रहे हैं, खासकर उपचुनाव के परिणाम के बाद से। शिवराज ने लव जिहाद पर लगाम के लिए कानून से लेकर गौ-कैबिनेट तक के निर्णय लेकर अपनी कार्यशैली के नए अंदाज का अहसास करा दिया है। दरअसल, ये संकेत हैं कि प्रदेश की सियासत में उसी शिवराज दौर की वापसी हो रही है, जिसे उनके लगातार तीन कार्यकाल में प्रदेश पहले भी देखा जा चुका है। पिछले तीन कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अफसरों को मंत्रालय की बैठकों से लेकर सार्वजनिक मंचों तक पर हड़काते रहते थे। लेकिन अफसरों की चाल कभी नहीं बदली।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक खासियत यह है कि वे जनता की मानसिकता के अनुसार काम करते हैं। ऐसे में जब भी उनके सामने जनता से संबंधित शिकायतें पहुंचती हैं तो वे तत्काल नए निर्देश जारी कर देते हैं। उन निर्देशों का क्रियान्वयन हुआ या नहीं, इसकी कभी जांच पड़ताल नहीं की गई। लेकिन इस बार वे कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। न केवल वे निर्देश दे रहे हैं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। इससे अफसरों में पहले की अपेक्षा अधिक भय नजर आ रहा है।

उपचुनाव के बाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशासनिक कसावट में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर और आईजी-पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करने के बाद तय किया है कि वे विभागों में कसावट लाने के लिए स्वयं समीक्षा करेंगे। एक दिसंबर से यह सिलसिला शुरू होकर करीब ढाई माह चलेगा। इसमें विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को **एक, दो और तीन साल** की कार्ययोजना बतानी होगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित मामलों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। मंत्रियों के लिए अब अपनी रेटिंग बनाना बड़ी चुनौती बन गया है।

● कुमार राजेन्द्र

एक्शन में शिवराज

आमतौर पर विनम्र और सौम्य दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता के अपने चौथे कार्यकाल में ये भी दिखा दिया है कि वे कितने सख्त स्वभाव के हैं। उनके स्वभाव का ये पहलू खासकर उस विधानसभा उपचुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद सामने आया है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा ने 19 सीटें और कांग्रेस ने महज 9 सीटें जीतीं। चौहान वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्मनिरपेक्ष पथ पर अपने ही तरीके से चलते हैं, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री हिंदुत्व की लाइन पर उस तरह से चल रहे हैं, जैसा वे पहले कभी नहीं चले। उनके भाषणों में अब बदलाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर उमरिया जिले में आयोजित रैली में दिया गया भाषण, जहां उन्होंने कहा- मैं मप्र की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। इसके तुरंत बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020) का ड्राफ्ट तैयार करवा लिया, जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने और उनकी मदद करने वालों को 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया। बाद में 5 साल की जगह 10 साल की जेल का प्रावधान कर दिया। चौहान इस बिल को विधानसभा के आने वाले शीतकालीन सत्र में रखेंगे।

जब भी कभी कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, खासकर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामलों में 'मामा' शिवराज दोषियों और आरोपियों पर हमेशा सख्त रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भोपाल में एक अखबार के मालिक और चर्चित व्यक्ति प्यारे मियां को भी शिवराज की सख्ती का सामना करना पड़ गया। प्यारे मियां की सारी अवैध संपत्तियां नष्ट कर दी गईं। इनके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई शहरों में मुख्यमंत्री की तरफ से स्थानीय प्रशासन को खुली छूट देकर अपराधियों की अवैध संपत्तियां नष्ट कर दी गईं। सरकार के ऐसे रवैये से जहां एक तरफ गुंडों और बदमाशों में अफरा-तफरी मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिंह चौहान ने माफिया को अल्टीमेटम दिया है। जिसके साथ ही सरकार और प्रशासन की मंशा साफ जाहिर हो गई है। माफिया को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी तरह के भू-माफिया अपना बोरिया-बिस्तर लेकर भाग जाएं, क्योंकि शिवराज सरकार प्रदेश के माफिया, गुंडों, बदमाश, दादा, पहलवान सहित सभी तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सज्जन लोगों के लिए सरकार फूल की तरह कोमल है लेकिन बदमाशों के लिए बज्र की तरह कठोर है। ऐसे में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े माफियाओं को सरकार नहीं छोड़ेंगी।

मप्र की जमीन पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे ड्रग माफियाओं को उखाड़ फेंकने के लिए शिवराज ने गत दिनों वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्देश जारी किए। इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के 800 हुक्का लाउंज को बंद करने के आदेश दिए। राज्य में 15 से 22 दिसंबर तक ड्रग माफियाओं के **खिलाफ** कैंपेन चलाया जाएगा। ये कैंपेन तब चलाया जा रहा है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रदेश के साथ उन 15 शहरों की लिस्ट शेयर की, जो ड्रग हब बनने के मुहाने पर खड़े हैं। इन शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर भी शामिल हैं। पुलिस ने सख्ती से भोपाल और इंदौर में ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और पिछले हफ्ते ही बड़ी मात्रा में नशे से जुड़ी सामग्रियां जब्त कीं। हाल ही में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में चौहान ने सख्ती से कहा था कि जनता से जुड़े और ट्रांसफर केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे, टेबल के नीचे होने वाली डील से नहीं होंगे। कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चली 7 घंटे की मीटिंग में उन्होंने कई कलेक्टरों को निर्देशों का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने नीमच के पुलिस अधीक्षक और कटनी के कलेक्टर को वहां से हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उन आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, जो तय मापदंडों पर परफॉर्म नहीं कर रहे। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री जिलों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन जिलों में जहां भाजपा विधानसभा उपचुनाव हार गई।

अक्सर रेत माफियाओं के समर्थन का आरोप झेलने वाले शिवराज ने अवैध रेत उत्खनन करने वाले 647 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 2 करोड़ की रेत चोरी पकड़ी। इसके अलावा चिट-फंड कंपनियों के खिलाफ 184 केस दर्ज किए गए और निवेशकों को 17.60 करोड़ रुपए वापस दिलवाए गए। अक्टूबर तक 1711 केस साइबर अपराधियों के खिलाफ दर्ज किए गए। उनसे 1.97 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। वहीं भू-माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। 234 केस में से 200 के खिलाफ एक्शन लिया गया। इस कार्रवाई से अकेले नवंबर माह में ही सरकार की 285 करोड़ की 315 हैक्टेयर की जमीन को फ्री कराया गया। इसी तरह राशन माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मंत्रियों और अफसरशाही को सख्त संदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन के लिए जहां मंत्रियों के कामकाज को आंकलन करने के लिए रेटिंग प्रणाली शुरू की है, वहीं अफसरों से कहा है कि अब हर माह एजेंडा दिया जाएगा, जिस पर काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा है- सुशासन का मतलब स्पष्ट तौर पर समझ लें कि बिना लेन-देन के समय पर जनता का काम करना है। शासन की सुविधाओं का लाभ हर हाल में लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फोकस एजेंडे पर काम करना है। रूटीन गवर्नेंस प्रभावित न हो, रोजमर्रा के काम ना रुकें। लोग परेशान ना हों। प्रदेश की जनता की सेवा करने की तड़प जैसी मेरे दिल में है, वही आपको भी होना चाहिए। यदि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं तो आप भी दें। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। जो अच्छा करेगा, उसे सराहा जाएगा। लेकिन जिस ने गलती की, उसे हटाने में देर नहीं होगी।

सज गया अखाड़ा

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव का अखाड़ा सज गया है। राजनीतिक पार्टियों के पहलवान दंड पेलने लगे हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा नहीं की है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी माह नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा करना चाहता है, ताकि मौजूदा मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव करवाए जा सकें। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम नजर आ रहे हैं।

भोपाल सहित प्रदेश के 16 बड़े शहरों और 300 से ज्यादा नगरीय निकायों के चुनाव होना हैं, क्योंकि पहले कोरोना संक्रमण, कर्फ्यू-लॉकडाउन, उसके बाद उपचुनावों के चलते तारीखें आगे बढ़ती रहीं। सभी नगरीय निकायों में चुनी हुई परिषदों का कार्यकाल 8-10 महीने पहले ही समाप्त हो चुका है, जिनमें इंदौर नगर निगम भी शामिल है। इसमें महापौर सहित सभी 85 पार्षदों का कार्यकाल 18 फरवरी 2020 तक ही था और उसके बाद से प्रशासक काल चल रहा है और फरवरी 2021 में पूरा एक साल हो जाएगा। उपचुनावों में भाजपा को जो शानदार सफलता मिली, उसके चलते वह नगरीय निकायों के चुनाव तुरंत ही करवाने को उत्साहित थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते रहे कि नगरीय निकायों के चुनाव दिसंबर अंत में घोषित कर दिए जाएं और जनवरी में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सके। लिहाजा भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस ने भी निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दीं।

प्रदेश में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है और मतदाता सूची तैयार है। वहीं पिछले दिनों भोपाल में महापौर का आरक्षण भी संपन्न हो गया। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा और उसका कार्यक्रम जारी कर देगा, जिसके चलते मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर ही सीधे महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव करवाए जा सकेंगे, लेकिन अगर अभी इस माह घोषणा नहीं होती है तो फिर 3 से 4 महीने निगम चुनाव आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि तब 1 जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाना पड़ेगा और इसमें कम से कम डेढ़ से दो माह का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि पुनरीक्षण के कार्यक्रम को घोषित करने, दावे-आपत्तियों को स्वीकार करने, घर-घर सर्वे करवाने और फिर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाना है। लिहाजा जानकारों का कहना है कि दिसंबर माह के अंत तक अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो फिर मार्च-अप्रैल तक चुनाव टल सकते हैं।

नेताओं की पत्नियां भी दावेदार

भोपाल में 2009 में सामान्य महिला सीट होने के बाद भी भाजपा ने ओबीसी चेहरा कृष्णा गौर को मैदान में उतारा। वो जीत गईं। इस बार ओबीसी महिला सीट है। लिहाजा खुद कृष्णा गौर ने दावेदारी रखने की तैयारी की है। जबकि भाजपा में नए चेहरे को आगे लाने की आवाज तेज होने के भी संकेत हैं। ऐसा होता है तो मालती राय, श्यामा पाटीदार, सीमा यादव, चंद्रमुखी यादव, कमलेश यादव, वंदना जाचक, तुलसा वर्मा, उमपा राय के साथ कभी महापौर पद के दावेदार रहे कुछ नेताओं की पत्नियां भी सामने आकर दावेदारी कर सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खेमे की चलती है तो पूर्व महापौर विभा पटेल बड़ा चेहरा होंगी। प्रत्यक्ष प्रणाली लागू होने के बाद पहली महापौर वही चुनी गई थीं। यदि विभा के अलावा नामों की तलाश हुई तो संतोष कंसाना या शबिस्ता जकी दो नाम चर्चा में हो सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि भोपाल में कांग्रेस के तीन विधायकों आरिफ अकील, पीसी शर्मा और आरिफ मसूद की राय भी अहम होगी, क्योंकि चुनाव में इनकी सक्रियता मायने रखेगी। दिग्विजय सिंह के करीबियों की मानें तो सुरेश पचौरी की सहमति के बिना चुनाव मुश्किल होगा।

इधर मतदाता सूची में गड़बड़ी से लेकर उसे नए सिरे से बनाने की मांग भी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा है। दूसरी तरफ महापौर से लेकर पार्षदों के लिए दोनों ही दलों के नेता-कार्यकर्ता तैयार हैं। सभी बढ़-चढ़कर अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं। कई नेता तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वार्डों में खुद को पार्षद पद का योग्य उम्मीदवार बताकर प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया। वहीं अपने नेताओं-आकाओं के चक्कर भी काट रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव की घोषणा सरकार कब करवाती है।

राजधानी में नगर निगम की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होने के साथ ही सियासी हलचल बढ़ने लगी है। भाजपा में इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि महापौर और पार्षदों के टिकट देते समय दिल्ली का फॉर्मूला अपनाया जाए। वहां सभी को बदल दिया गया था। भाजपा नेतृत्व के सामने मुश्किल होगी कि वह युवा और नए चेहरों को कैसे सामने लाए, क्योंकि निकाय चुनाव में अभी तक विधायकों के हिसाब से ही टिकट बंटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में परिस्थितियां दूसरी हैं। यहां कुछ पुराने चेहरों के साथ कांग्रेस नए चेहरों को लाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह खेमा राजधानी में सियासी जमीन मजबूत कर सकता है। फिलहाल भाजपा से पूर्व महापौर व विधायक कृष्णा गौर तो कांग्रेस से पूर्व महापौर विभा पटेल का नाम आगे है। कृष्णा गौर भोपाल की गोविंदपुरा सीट से विधायक हैं। यह सीट बरसों से स्व. बाबूलाल गौर के पास रही। बाद में बहू कृष्णा विधायक चुनी गईं।

पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में इस सीट से कई दावेदार सामने आ गए थे, जिसमें स्थानीय से लेकर प्रदेश के दिग्गज नेता भी थे। टिकट अंततः कृष्णा को मिला। यही सियासी खेल महापौर के चुनाव में खेला जा सकता है। कृष्णा गौर को महापौर का टिकट दिया जाता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गोविंदपुरा सीट में नया चेहरा लाएगी। हालांकि इस संभावना से अलग भी विचार होगा, क्योंकि केंद्रीय भाजपा ने साफ कर दिया है कि नए व युवा कार्यकर्ता को तवज्जो मिले। ऐसे में दिल्ली निकाय चुनाव के उस फॉर्मूले पर भाजपा जा सकती है, जहां सभी चेहरे बदल दिए गए थे।

● विकास दुबे

विकास की राह में बाधाएं

विकास के कुछ ऐसे अनिवार्य पक्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित हैं। ऐसा ही एक पक्ष है विभिन्न समुदायों की एकता। विकास की कोई भी योजना या कार्यक्रम हो, प्रायः सामुदायिक भागीदारी से उसे कार्यान्वित करने की बात जरूर की जाती है, लेकिन जिन समुदायों की भागीदारी प्राप्त करने की चेष्टा है, उनमें आपसी एकता और एकजुटता, आपस में बराबरी के स्तर पर मिल-जुलकर सहयोग करने की स्थिति है या नहीं, इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ आदिवासी गांवों या अन्य विशिष्ट स्थितियों वाले गांवों को छोड़ दें, तो अधिकांश गांवों में जातिगत भेदभाव की विकराल समस्या है। चुनावों के समय जातिगत के साथ पंचायत और व्यापक राजनीति के मुद्दे मिलकर ऐसे भेदभाव और गुटबाजी को और घातक बना देते हैं और कई जगहों पर यह स्थितियां आक्रामक व हिंसक रूप धारण कर लेती हैं। अनेक गांवों में एक या कुछ अधिक धनी व्यक्तियों जैसे सामंतों, ठेकेदारों, अपराधियों आदि का दबदबा होता है और सरकारी तंत्र और प्रमुख राजनीतिक दलों के संबंध गांव के इन शक्तिशाली व असरदार व्यक्तियों से अधिक नजदीकी के होते हैं। ऐसे में सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है।

इस स्थिति में यह सवाल उठना लाजिमी है कि गांव समुदाय व सामुदायिक भागीदारी से ठीक-ठीक अभिप्राय क्या है। यदि सामुदायिक भागीदारी प्राप्त करने की कार्यवाही यहां तक सीमित है कि बस गांव के गिने-चुने सामंती प्रवृत्ति के परिवारों या अन्य धनी परिवारों से सहयोग ले लिया जाए, तो यह सामुदायिक भागीदारी का सीमित ही नहीं, बल्कि विकृत रूप माना जाएगा क्योंकि जिन गरीब लोगों के नाम पर विकास का एजेंडा प्रचारित होता है, वे निर्धन परिवार इन असरदार व धनी व्यक्तियों का शोषण सहने को मजबूर हैं।

सामुदायिक भागीदारी की इस संकीर्ण समझ के कारण ही प्रायः सही अर्थों में सामुदायिक भागीदारी आगे बढ़ ही नहीं पाती है और यही हमारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की विफलता का एक प्रमुख कारण है। उन गांवों में स्थिति समुदाय की भागीदारी की दृष्टि से कहीं बेहतर है जहां लगभग सभी परिवार छोटे व मध्यम किसान हैं। और यदि उनका जातीय आधार भी एक-सा है तो समुदाय के स्तर पर एकता स्थापित करना और पूरे समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना अधिक सरल हो जाता है। पर कभी-कभी इन गांवों में भी पारिवारिक झगड़ों व गुटबाजी के कारण यह संभावना कम हो जाती है। अधिकांश गांवों में अनेक जातियां एकसाथ रहती हैं। कहीं जातीय स्तर पर टकराव होता है तो कहीं भेदभाव। आर्थिक व सामाजिक विषमता कई स्तरों पर मौजूद होती है और गांवों के न्यायसंगत विकास में प्रायः यही सबसे बड़ी बाधा है। इस विषमता को कम किए बिना गांव समुदाय की न्यायसंगत पहचान नहीं बन सकती है और न ही न्याय-आधारित सामुदायिक भागीदारी विकास कार्यक्रमों में प्राप्त हो सकती है।

इसलिए यदि सामुदायिक एकता व एकता आधारित भागीदारी को सही व न्यायसंगत अर्थों में प्राप्त करना है तो सभी स्तरों पर विषमता को मिटाना जरूरी है। विषमता नहीं होगी या कम होगी तो गरीबी भी कम होगी। जाने-माने विशेषज्ञों व उनके द्वारा किए गए अध्ययनों ने विषमता कम करने को गरीबी कम करने का बहुत असरदार उपाय बताया है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में अनेक देशों की सरकारों ने विषमता बढ़ाने वाली नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों का विरोध जरूरी है। यह एक अजीब विसंगति है कि एक ओर गरीबी कम करने की बातें तो बहुत की जाती हैं, गरीबी कम करने के लिए ढेरों सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं, पर साथ में विषमता को भी बढ़ने दिया जाता है जिससे गरीबी कम करने का आधार ही कमजोर हो जाता है। अतः अब इस बारे में दृढ़ राय बना लेनी चाहिए कि गरीबी कम करने के लिए विषमता को कम करना व समता लाना जरूरी है।

जब ग्रामीण समाज अधिक समता आधारित बनेगा तो उसकी न्यायसंगत एकता के आधार पर विकास योजनाओं में (ऐसी योजनाएं जो समता व न्याय से मेल रखती हैं) वास्तविक, सच्ची सामुदायिक भागीदारी बढ़ने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बहुत बढ़ जाएंगी और यही ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता के लिए सबसे जरूरी है। इस समता, एकता व उत्साहवर्धक भागीदारी की राह पर बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि गांवों के जो सबसे निर्धन व कमजोर परिवार हैं, उनके लिए संसाधनों और आजाविका के आधार को मजबूत किया जाए। जो भूमिहीन हैं, उनके लिए कुछ भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस बारे में प्रायः कहा जाता है कि अब गांवों में ऐसी जमीन बची ही कहां है जो गरीबों को दी जा सके। लेकिन अनेक देशों के अनुभव से पता चलता है कि जहां वास्तविक इच्छाशक्ति हो वहां प्रायः कुछ न्यूनतम कृषि भूमि की व्यवस्था गांव के सभी मूल परिवारों के लिए करना संभव होता है। अनेक देश इसके लिए सीलिंग कानून या हदबंदी कानून बनाते हैं। इन कानूनों से कृषि भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय की जाती है और इससे अधिक जो भूमि होती है, वह भूमिहीनों के लिए प्राप्त की जाती है।

● रजनीकांत पारे

कानून प्रभावी नहीं

हमारे देश में भी कृषि भूमि सीलिंग कानून बनाए गए, पर इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया। इन कानूनों के अंतर्गत भूदान आंदोलन भारत का अपना एक विशिष्ट प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था, जिसमें स्वेच्छा से दी गई भूमि के आधार पर भूमिहीनों में भूमि वितरण का प्रयास किया गया। एक समय इस आंदोलन ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, पर कुछ समय बाद यह कमजोर पड़ गया। एक अन्य प्रयास हमारे देश में यह हुआ कि जो गांव समाज की खाली जमीन है, उसे भूमिहीनों में वितरित किया जाए। कुछ ऐसी भूमि भी है तो इस समय खाली तो पड़ी हैं, पर कृषि के अनुकूल नहीं है। ऐसी काफी जमीन वन-विभागों के कब्जे में भी है। ऐसी भूमि की घेराबंदी कर इसे स्थानीय वन-भूमि के अनुरूप हरा-भरा होने का अवसर देना चाहिए। इस दौरान निर्धन भूमिहीन परिवारों को देख-रेख की मजदूरी सरकार की ओर से निश्चित मासिक आय के रूप में मिलनी चाहिए। बाद में इन वृक्षों से लघु वन उपज (चारा, ईंधन, बीज, फल, फूल, पत्ती, बांस) आदि प्राप्त करने का अधिकार इस रूप में मिल जाना चाहिए जिससे उनकी आजीविका टिकाऊ तौर पर पनप सके।

हड़बड़ी में प्लान

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में प्रदेश में अव्वल और देश में दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन भोपाल स्मार्ट सिटी के प्लान में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। जिससे यह साबित हो रहा है कि अधिकारियों ने हड़बड़ी में कागजी प्लान बना दिया है, जबकि धरातल पर स्थिति कुछ अलग ही है। इसका असर यह हो रहा है कि स्मार्ट सिटी की राह में जगह-जगह बाधाएं खड़ी हो रही हैं। टीटी नगर में 342 में से 87 एकड़ जमीन का स्मार्ट सिटी कंपनी को पजेशन ही नहीं मिल सकता। इसमें निजी मकान, दुकान, स्कूल और मांगलिक भवन आदि शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के व्यापारियों के विरोध के बाद कंपनी ने फिर सर्वे कराया है। इसके बाद तैयार नक्शे में 'नॉट इन पजेशन' जमीन का अलग से उल्लेख है। कंपनी को यहां डेवलपमेंट करने के लिए इस क्षेत्र को डिनोटिफाई करना पड़ेगा।

नए नक्शे से पता लगता है कि स्मार्ट सिटी का प्लान हड़बड़ी में तैयार हुआ है। टीटी नगर की बसाहट के समय का नक्शा लेकर प्लान बना दिया, जबकि बाद में शासन ने जमीन लीज पर दी है। इसमें से कई तो हाल के वर्षों में ही अगले 30 वर्षों के लिए रिन्यू भी की गई हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी के ईडी वीएस चौधरी कोलसानी का कहना है कि फिलहाल फोकस चालू प्रोजेक्ट पूरा करने पर है। इस मसले पर बाद में विचार किया जाएगा। माता मंदिर से जवाहर चौक तक लगभग तैयार हो चुकी **बुलेवर्ड स्ट्रीट** के दोनों ओर अवैध सब्जी मंडी बन गई है। एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कब्जा करा दिया है। 40 करोड़ से तैयार हुई बुलेवर्ड स्ट्रीट पर स्मार्ट सिटी कंपनी 30 करोड़ रुपए से लेकर 80 करोड़ रुपए के प्लॉट बेचकर पहले चरण में 265 करोड़ जुटाना चाहती है। लेकिन यहां हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

स्मार्ट सिटी कंपनी ने जनवरी के पहले सप्ताह में जवाहर चौक से 211 दुकानदारों को हटाया था। करीब सालभर में भी इनका व्यवस्थापन नहीं हो सका है। व्यापारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष राकेश जैन ने कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम के कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी और स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ आदित्य सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं और निजी व्यक्तियों को लीज पर दी गई जमीन को स्मार्ट सिटी के प्लान में शामिल करने से आ रही परेशानियों पर अफसरों से चर्चा की। अफसरों ने उन्हें बताया कि नए सिरे से सर्वे कराया गया है। रंगमहल चौराहे से जवाहर चौक तक सड़क को 45 मीटर चौड़ा करने की प्लानिंग है। ऐसी स्थिति में ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के 24 मकान दायरे में आ रहे हैं। सड़क के दूसरी ओर की निजी दुकानें भी इसमें आ रहीं हैं। कुल मिलाकर 2000 से अधिक दुकानदार और 100 निजी मकान स्मार्ट सिटी के दायरे में हैं।

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट घटिया निर्माण और धांधली के कारण भी चर्चा में है। वर्ष 2017 में जिस स्मार्ट रोड के भूमिपूजन के दौरान दावा था कि प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड का निर्माण ऐसा होगा, जो देश के लिए मिसाल बन जाएगी, हकीकत तो यह है कि जिम्मेदारों की लापरवाही, धांधली और मनमानी का शिकार हुई। 32 करोड़ रुपए की लागत से भारत माता चौराहे से पॉलीटेक्निक तक 95 प्रतिशत बनकर तैयार स्मार्ट रोड की हालात आम सड़कों से भी बदतर है। गुणवत्ता इनती खराब कि हाथों से ही सीमेंट के थप्पे निकल जाते हैं। सेंट्रल वर्ज तक जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। शहर की आम सड़कों की स्थिति भी स्मार्ट रोड से कही बेहतर है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सपने दिखाने का काम किया है। स्मार्ट रोड को दो भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। घटिया निर्माण कार्य के चलते कई स्थानों पर डिवाइडर जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। हिंदी भवन से कुछ ही दूरी पर डिवाइडर टूटे पड़े हुए हैं। स्मार्ट रोड में साइकिल ट्रैक व रोड के बीच एक पट्टी का निर्माण किया गया है। सिविल वर्क के तहत निर्माण कार्यों की लेवलिंग तक नहीं की गई है। कई स्थानों पर निर्माण समतल नहीं है। वर्ज की वॉल भी बिना स्ट्रक्चर के तैयार की गई। इन पर पेंट भी कर लिया गया। स्मार्ट रोड में बनाए गए साइकिल ट्रैक का अलाइमेंट तक नहीं किया गया। इसके अलावा फिनिशिंग वर्क के पहले ही लाल रंग का पेंट पोता गया। यह ट्रैक समतल दिखने के स्थान पर ऊपर-नीचे दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी परियोजना के एबीडी एरिया टीटी में जमीन मोनेटाईजेशन की प्रक्रिया शुरू की दी गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी के पास जर्मनी और सिंगापुर सहित पूरे देश निवेशकों के फोन कॉल के जरिए संपर्क किया। प्रक्रिया शुरू होते ही पहले दिन करीब 1400 निवेशकों ने स्मार्ट सिटी कंपनी की संपत्ति खरीदने इच्छा जाहिर की। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई निवेशक स्मार्ट सिटी परियोजना में किस आधार पर निवेश करेगा।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

ये हो रहे डेवलपमेंट

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएससीडीसीएल) द्वारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) व पेन सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। टीटी नगर स्थित 343 एकड़ क्षेत्र में एबीडी प्रोजेक्ट के तहत बुलेवार्ड स्ट्रीट, स्मार्ट रोड, गवर्नमेंट हाउसिंग फेस-1 व दशहरा मैदान रीडेवलपमेंट का काम अंतिम चरणों में है। पेन सिटी प्रोजेक्ट में हैरिटेज कंसर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल सदर मंजिल को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। यह काम भी 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। छोटे तालाब के रानी कमलापति घाट पर पुराने शहर को नए शहर से जोड़ने वाला आर्च ब्रिज का निर्माण दो माह के अंदर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य भी ऐसे किया जा रहा है कि लोग इसका उपयोग कर सके। उधर, स्मार्ट सिटी ने बड़े तालाब स्थित वीआईपी रोड पर लगाए सोलर प्लांट का काम भी पूरा कर लिया है।

कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय नेता और गांधी परिवार के करीबी कमलनाथ मप्र की सियासत का वो चेहरा हैं, जिन्होंने मप्र में सत्ता का वनवास काट रही कांग्रेस को वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अपने कुछ नेताओं और विधायकों की गद्दारी के कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। अभी भी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। इसलिए कमलनाथ परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।

नाथ का विकल्प कौन?

मप्र में पहले सरकार गंवाने और अब हाल ही में उपचुनावों में करारी हार झेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। गत दिनों छिंदवाड़ा में समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया है। कांग्रेस में लगातार कमलनाथ के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच उनके इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ सिर्फ कोई पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर कयास लग रहे हैं। कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है।

बता दें कि अभी कमलनाथ मप्र विधानसभा में विपक्ष के नेता होने के साथ-साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में हाल ही में जब उपचुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी तो लगातार कई **नेताओं, विधायकों** ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। राज्य में नेता लगातार कह रहे हैं कि अब किसी युवा नेतृत्व की जरूरत है और हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं। राज्य में कमलनाथ पर गलत टिकट बंटवारे, कमजोर उम्मीदवारों और गलत रणनीति का आरोप लगा।

आपको बता दें कि इससे पहले जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भिड़ंत हुई थी। तब कमलनाथ तो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसी का खामियाजा कांग्रेस अब तक उठा रही है, पहले सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से कमलनाथ की सरकार गिर गई और उसके बाद अब उपचुनावों में अधिकतर विधायकों ने भाजपा के टिकट से जीत हासिल कर ली। केंद्रीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने के बाद चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ राज्य की राजनीति में एक्टिव हुए थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद भी मिल गया था। लेकिन लगातार हार, सिंधिया के पार्टी छोड़ने और उससे पैदा हुए असर से कमलनाथ लगातार बैकफुट पर आते गए हैं।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कमलनाथ के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्हें भोपाल में अपना सरकारी मकान वापस कर देना चाहिए। वह अपना कारोबार बंद करें और अपने घर में आराम करें। हालांकि भाजपा नेता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी उस दिन मैं संन्यास लूंगा।

कमलनाथ यदि राजनीति से संन्यास लेते हैं तो क्या मप्र में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो जाएगी? पंद्रह साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कमलनाथ के नेतृत्व में ही हुई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार पंद्रह माह भी ठीक से नहीं चल सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो जाने के कारण विधानसभा में कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार गिर जाने के बाद कमलनाथ पर संतुलन बनाकर सरकार न चला पाने के आरोप दबी जुबान से कांग्रेसी लगा रहे हैं। अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी उनका समर्थन करने वाला नेता नहीं है।

कमलनाथ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में राजनीति छोड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने

संन्यास वाले बयान पर पॉलिटिकल बवाल?

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है यदि छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो संन्यास ले लूंगा। उनके इस बयान के बाद मप्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी नेता इस बयान के अपनी तरह से मायने निकाल रहे हैं। कमलनाथ समर्थक कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता के बीच ऐसे बयान देना आम बात है, लेकिन अन्य गुटों के नेता कह रहे हैं कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं। कमलनाथ ने सौंसर में संन्यास लेने के संकेत क्यों दिए? इसके पीछे वजह चौरे परिवार को बताया जा रहा है, जिसे कमलनाथ राजनीति में लाए थे। कमलनाथ ने रेवानाथ चौरे (अब दिवंगत) को विधायक का टिकट देकर राजनीति में उतारा था। वे अर्जुन सिंह की सरकार में दो बार मंत्री बने। इसके बाद सौंसर से उनकी पत्नी कमला चौरे विधायक बनीं। उनके बेटे अजय चौरे विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में विजय चौरे विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि अजय चौरे के भाजपा में जाने से कमलनाथ नाराज हैं, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने वाला बयान सौंसर जाकर दिया।

गत दिनों छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा कि जिले की जनता और कार्यकर्ताओं से उनके सदैव पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस आधार पर यदि सब चाहते हैं कि अब मैं आराम करूं तो मैं रिटायर्ड होने के लिए तैयार हूं। इस पर प्रतिक्रिया में सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि आपको आराम नहीं काम करना है और फिर से सरकार बनाना है। अपने रिटायरमेंट के सवाल पर कमलनाथ कहते हैं- जिले की जनता ने मुझे सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूं, जिस दिन जनता कहेगी उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उल्लेखनीय है कि 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद से मप्र में कांग्रेस के भीतर ही भीतर असंतोष पनप रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी इक्का-दुक्का नेता उठा रहे हैं। कमलनाथ वर्तमान में मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ-साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष हैं।

कमलनाथ के नेतृत्व पर सबसे ज्यादा सवाल दिग्विजय सिंह समर्थकों की ओर से ही खड़े किए जा रहे हैं। श्योपुर जिले के विधायक बाबूलाल जंडेल ने कहा कि यदि उपचुनाव में दिग्विजय सिंह को आगे रखा जाता तो कांग्रेस की पराजय न होती। राज्य में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे पिछले माह आए हैं, उनमें कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही मिल पाई हैं। जबकि जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें 27 सीटें आम चुनाव में कांग्रेस ने जीती थीं। इन सीटों से जीते विधायकों ने ही मार्च में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले विधायकों का आरोप था कि कमलनाथ की आड में सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं।

2018 में हुए विधानसभा के आम चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया था। दिग्विजय सिंह के चेहरे को पर्दे के पीछे रखा गया था। राज्य में सरकार बनने के बाद सिंधिया को हाशिए पर डाल दिया गया। उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया गया। नतीजा वे अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में चले गए।

मार्च में सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ-साथ विधायक दल के नेता भी बने रहे। जबकि दिग्विजय सिंह समर्थक डॉ. गोविंद सिंह को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने का दबाव भी उन पर था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कमलनाथ के मामले में दखल नहीं दिया। मप्र भाजपा के प्रवक्ता हितेष वाजपेयी कहते हैं कि कमलनाथ पद से चिपके रहना चाहते हैं। जबकि उनकी **स्वीकार्यता** ही नेताओं के बीच नहीं है। कमलनाथ ने 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अपवाद स्वरूप एक बार को छोड़कर वे लगातार यहां से चुनाव भी जीतते रहे, लेकिन वे मप्र की राजनीति में मैदानी स्तर पर सक्रिय नहीं रहे। दिल्ली में अपने प्रभाव का उपयोग कर समर्थकों को टिकट अथवा महत्वपूर्ण पद दिलाते रहे। कमलनाथ की पूरी राजनीति अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का समर्थन कर चलती रही। माधवराव सिंधिया और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनका विरोध रहा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कारण राज्य में नया नेतृत्व भी उभरकर सामने नहीं आ पाया है।

कमलनाथ के विकल्प के तौर पर एक ही नाम हमेशा सामने आता है। यह नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है, लेकिन उनकी बहुसंख्यक विरोधी छवि के कारण पार्टी नेतृत्व सौंपने से झिझकती है। दूसरा नाम अजय सिंह का है और वे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र चुरहट से चुनाव हारने के बाद हाशिए पर हैं। कमलनाथ से भी इनकी दूरी दिखाई देती है। पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव को पार्टी एक बार पांच साल अध्यक्ष बनाकर देख चुकी है, लेकिन वे अपने आपको स्थापित नहीं कर पाए। नई पीढ़ी में दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को नेतृत्व दिए जाने की मांग यदाकदा उठती रहती है। कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। कमलनाथ की तरह उनका चेहरा भी कोई खास लोकप्रिय नहीं है। राहुल गांधी के टीम मेंबर के तौर पर जीतू पटवारी का नाम भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चा में रहता है। पटवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस कारण उनका नेटवर्क भी है और वे पंद्रह महीने की सरकार में मंत्री भी रहे हैं।

● लोकेन्द्र शर्मा

अनुसूचित जाति और आदिवासी चेहरे का भी विकल्प है

कमलनाथ की चिंता अपने पुत्र नकुलनाथ की राजनीति की है। उपचुनाव के प्रचार में नकुलनाथ ही कमलनाथ के साथ हर महत्वपूर्ण जगह मौजूद थे। दिल्ली की राजनीतिक स्थितियां भी कमलनाथ के अनुकूल दिखाई नहीं दे रही हैं। राहुल गांधी से उनकी दूरी अभी भी बनी हुई है। कमलनाथ खुद आगे आकर पार्टी अध्यक्ष अथवा विधायक दल की जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नकुलनाथ के स्थापित होने से पहले कमलनाथ राजनीति छोड़ेंगे, यह संभव दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा कहते हैं कि कमलनाथ कुर्सी की राजनीति नहीं करते वे सेवा करने मप्र में आए हैं। वर्तमान राजनीतिक हालतों को देखा जाए तो यह तय है कि दो में से कोई एक पद कमलनाथ को छोड़ना होगा। कमलनाथ विधायक दल के नेता का पद छोड़ सकते हैं। इस पद के लिए उनकी ओर से विजयलक्ष्मी साधौ का नाम आगे बढ़ाया गया है। साधौ अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। आदिवासी वर्ग से बाला बच्चन का नाम भी विकल्प के तौर पर दिया गया है।

दोगुना मिलेगा मुआवजा

भोपाल और इंदौर मेट्रो ट्रेन को दौड़ाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की नीति भी बना ली है। अब बाजार दर की राशि के साथ एक लाख रुपए अतिरिक्त देकर भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन, मकान, दुकान आदि का अधिग्रहण किया जाएगा। यदि रास्ते में कोई अतिक्रमित संपत्ति भी है तो उसे भी हटाने का पैसा राज्य सरकार देगी। कैबिनेट ने भी नए प्रावधानों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का विवाद न हो।

यदि आपकी संपत्ति (आवासीय व कर्मशियल) मेट्रो प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही है तो भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से तय बाजार मूल्य की दोगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी। इसके अलावा एक यह भी होगा कि आप बाजार मूल्य के साथ 200 प्रतिशत हस्तांतणीय विकास अधिकार (टीडीआर) भी ले सकते हैं। एकबारगी संदाय (सिर्फ एक बार दिया जाने वाली राशि) के रूप में 6 लाख रुपए और पुन: विस्थापन भत्ता के लिए 50 हजार रुपए की राशि भी मिलेगी।

दरअसल, सरकार ने भोपाल व इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए खाका तैयार कर लिया है। यह प्रावधान भी केंद्र सरकार के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के आधार पर तय किए गए हैं। सरकार ने भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2023 में संचालन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। लिहाजा मेट्रो डिपो, स्टेशन, भूमिगत मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी जिला प्रशासन से जमीन की मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा की गई है।

मेट्रो प्रोजेक्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दो वर्ष पहले ही टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलमेंट राइट अर्थात् हस्तांतणीय विकास अधिकार) को लागू कर दिया है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को भूमि के बदले एक अधिकार पत्र दिया जाता है। जहां से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है उसे जनरेटिंग एरिया और इस जमीन के बदले जहां दोगुना फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) दिया उसे रिसीविंग एरिया का नाम दिया गया है। इसके लिए भू-स्वामी को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। भू-स्वामी सर्टिफिकेट का हस्तांतरण या अन्य व्यक्ति को बेच भी सकता है। अधिग्रहण के नियमों में टीडीआर 200 प्रतिशत किया गया है। मतलब भू-स्वामी मास्टर प्लान में तय स्थान पर बेस एफएआर से दोगुना निर्माण का अधिकार होगा।

भोपाल में इन रूट पर होगा अधिग्रहण

राजधानी भोपाल में मेट्रो के लिए कई रूटों पर जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। करोंद से एम्स तक (लाइन-2)- पर्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। पहले कॉरिडोर के तहत 14.99 किमी में करोंद से एम्स तक मेट्रो का निर्माण कराया जाएगा। इसमें करोंद से कृषि उपज मंडी, डीआईजी बंगला, सिंधी कॉलोनी, नादरा बस स्टैंड, भारत टाकीज, बोगदा पुल, ऐशबाग स्टेडियम के पास, सुभाष नगर अंडर ब्रिज, मैदा मिल, एमपी नगर, सरगम सिनेमा, हबीबगंज कॉम्पलेक्स, अलकपुरी से एम्स तक निर्माण कराया जाएगा। भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक (लाइन-5)- रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरे कॉरिडोर में 12.88 किमी तक पूर्व निर्धारित रूट को तैयार किया जाएगा। इस रूट पर भदभदा चौराहा, डिपो चौराहा, जवाहर चौराहा, रंगमहल चौराहा, मिंटो हॉल, लिलि टॉकीज, जिंसी, बोगदा पुल, प्रभात चौराहा, गोविंदपुरा उद्योगिक क्षेत्र, इंद्रपुरी, पिपलानी से रत्नागिरी तिराहे तक मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो के संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा करोंद से एम्स तक करीब 47 एकड़ कुल जमीन के अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। इसमें सरगम टॉकीज के पास स्थित पेट्रोल पंप की जमीन, सुभाष नगर चौराहा, बोगला पुल के पास ग्लू फैक्ट्री, बोगदा पुल रोड, भोपाल रेलवे स्टेशन क्षेत्र, बड़े बाग कब्रिस्तान के पास, सिंधी कॉलोनी चौराहा के पास, निशातपुरा स्थित कृषि उपज मंडी व करोंद चौराहा पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

आवासीय और व्यवसायिक (बिना विस्थापन) आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित भू-स्वामी को भूमि के बाजार मूल्य की राशि दी जाएगी। साथ ही तोषण राशि (बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत) या 200 प्रतिशत हस्तांतणीय विकास अधिकार भी मिलेगा। सहायता के रूप में 6 लाख और पुन: विस्थापन भत्ता के लिए 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। आवासीय और व्यवसायिक (विस्थापन के लिए) पूर्ण रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि के बाजार मूल्य की राशि दी जाएगी। साथ ही तोषण राशि (बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत) या 200 प्रतिशत हस्तांतणीय विकास अधिकार भी मिलेगा। सहायता के रूप में 6 लाख, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता 50 हजार, जीवन निर्वाह भत्ता 36 हजार और परिवहन भत्ता 50 हजार रुपए मिलेगा।

आवासीय संपत्ति का निर्माण की दशा में क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। संरचना (निर्माण) का बाजार मूल्य के साथ इतनी ही राशि की तोषण राशि भी मिलेगी। मकान निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। व्यवसायिक संपत्ति का निर्माण की दशा में क्षतिपूर्ति संरचना (निर्माण) का बाजार मूल्य व इतनी राशि का तोषण मूल्य के अलावा 25 हजार रुपए वित्तीय सहायता मिलेगी। श्रमिक श्रेणी में क्षतिपूर्ति हाथ ठेला श्रमिकों को 10 हजार व गुमठी श्रमिकों को 15 हजार रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में आने वाले दिव्यांग व नि:शक्त जन के लिए 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। आवासीय संपत्ति की दशा में लीजधारकों को परिवहन भत्ता व पुन: विस्थापन भत्ता के लिए कुल एक लाख रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि व्यवसायिक संपत्ति की दशा में परिवहन भत्ता 50 हजार व आर्थिक सहायता के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

● सुनील सिंह

अब मार्च में सर्वे

कोरोना संक्रमण की वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को दो महीने आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार यह सर्वे जनवरी की बजाय मार्च में होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसके लिए 1 से 28 मार्च तक का समय निर्धारित किया है। अब नगर निगम को सर्वे के लिए दो महीने का समय अतिरिक्त मिलेगा। इसका फायदा रैंकिंग में मिलने की उम्मीद की जा रही है। जो काम लॉकडाउन के दौरान नगर निगम नहीं कर पाया था, वह पूरे किए जा सकेंगे। संभावना है कि सर्वे की तिथि में बदलाव होने के कारण अब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी जल्द कराए जा सकते हैं।

अब 2021 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण नए बदलाव के साथ होगा। सर्विस लेवल प्रोग्रेस 2400 अंक का होगा। इसके तहत जुलाई से अगस्त की पहली तिमाही के 600, सितंबर से नवंबर की दूसरी तिमाही के 600 और दिसंबर से फरवरी तक की तीसरी तिमाही के 1200 अंक होंगे। सर्टिफिकेशन 800 अंक का होगा। इसके तहत गार्बेज फ्री सिटी के 1100, ओडीएफ व वाटर प्लस के 700 अंक रहेंगे। पहली बार वॉटर प्लस सर्वे भी होगा, इसमें गंदे पानी को साफ करने के प्रयास देखे जाएंगे। सिटीजन वाइस भी 1800 अंक का है। इसके तहत लोगों से बात कर फीडबैक लिया जाएगा।

इस बार रैंकिंग का मुख्य आधार सिटीजन फीडबैक होगा। यह प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक 84 दिन चलेगी। इसमें नागरिकों से 7 सवाल पूछकर फीडबैक लिया जाएगा। सरकारी एजेंसी भी अपने स्तर पर सीधे या फोन व अन्य माध्यम से फीडबैक लेगी। सर्वेक्षण में दो माह का अतिरिक्त समय मिलने से नगर पालिका रैंकिंग सुधारने के लिए इसमें कई नए प्रयोग कर सकती है। आयुक्त नगरीय आवास एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव कहते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जनवरी में प्रस्तावित था। किन्हीं कारण से सर्वे की तारीख और महीने में बदलाव किया गया है। अब सर्वे का काम 1 से 28 मार्च तक होगा।

स्वच्छता सर्वे के तहत अब वॉटर प्लस सर्टिफिकेट और सेवन स्टार रेटिंग पाने के लिए नगरीय निकाय 20 फरवरी तक दावा पेश कर सकेंगे। पहले यह तारीख 30 नवंबर थी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वे के साथ इन दोनों सर्वे के लिए आवेदन देने संबंधी नई तारीखें घोषित की हैं। माना जा रहा है कि नगरीय निकायों के आग्रह पर यह समयसीमा बढ़ाई गई है। कोरोना संक्रमण के कारण ज्यादातर नगरीय निकाय दूसरी व्यवस्थाओं में जुटे रहे और स्वच्छता सर्वे की गाइडलाइन के अनुरूप ज्यादा काम नहीं कर सके। इसी कारण कई शहरों के निकायों ने मंत्रालय के वॉटर प्लस और सेवन स्टार रेटिंग के लिए दावा पेश करने और स्वच्छता सर्वे के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था, जिसे मंत्रालय ने मान लिया है। स्वच्छता सर्वे अब मार्च में होगा, जबकि बाकी दोनों सर्वे 20 फरवरी बाद शुरू होंगे।

उधर, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भले ही भोपाल नगर निगम भाग लेने जा रहा हो, लेकिन इस सर्वेक्षण में स्थान बना पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल, इस चैलेंज में ऐसे मानक दिए गए हैं जिसमें नगर निगम द्वारा अब तक काम शुरू नहीं किया गया है। इसमें सीवेज के पानी का दोबारा उपयोग करना, जल स्त्रोतों में मल-मूत्रों को जाने से रोकना और शत-प्रतिशत मशीनों से सीवेज संबंधित काम करने पर अंकों का निर्धारण किया गया है।

दरअसल, शहर के तीन दर्जन से अधिक बड़े नालों के लिए काम शुरू नहीं हो सका है। इसमें अन्ना नगर, आनंद नगर, अवधपुरी समेत अन्य नालों से खुले में बहता हुआ सीवेज सालों से लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही सीवेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो सका है। बीते दिनों निगमायुक्त ने टाटा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। वहीं बड़े तालाब, छोटे तालाब, हताईखेड़ा डेम, मोतिया तालाब समेत अन्य जल स्त्रोंतो में नालों की गंदा पानी मिल रहा है। चैलेंज की गाइडलाइन के मुताबिक सीवेज के ट्रीट वाटर का अन्य प्रोजेक्टों में उपयोग के लिए अंकों का निर्धारण किया गया है। मामले में इंदौर नगर निगम ने सीवेज ट्रीट वाटर का उपयोग निर्माणों में शुरू भी किया है। साथ इंदौर नगर निगम ने इसे आय का जरिया भी बनाया है। उधर, भोपाल में अब तक सीवेज ट्रीट वाटर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई है। बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक सीवेज ट्रीट वाटर से उद्यानों में सिंचाई, निर्माण में उपयोग, धुलाई आदि जैसे कामों में उपयोग करने का प्रावधान है।

● जितेन्द्र तिवारी

ऐसे होगा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। चैलेंज के तहत आगामी 31 मार्च तक गाइडलाइन के तहत तैयारियां पूरी करनी होगी। अप्रैल 2021 में दस्तावेज जमा करने होंगे। फिर मई से जून के बीच चैलेंज के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर सर्वे होगा। 15 अगस्त 2021 को इस परिणामों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय आवासन मंत्रालय ने इस प्रतिस्पर्धा में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार रखा है। जबकि द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 6 करोड़ रुपए एवं 3 करोड़ रुपए की राशि संबंधित निकाय को दी जाएगी। नगर निगम द्वारा सीवेज संबंधित कार्यों के लिए 39 मशीनों से काम लिया जाता है। निगम के सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इसके अलावा तीन अन्य एसटीपी प्रोजेक्ट का सिविल वर्क जारी है। निगम के पास ओडीएफ डबल प्लस का भी तमगा है। दावा किया जाता है कि सीवेज के लिए मैनुअल काम नहीं किया जाता।

बढ़ा नक्सली मूवमेंट

मप्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस की सतर्कता से नक्सली आक्रामक होने लगे हैं। विगत दिनों बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों से बीच मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गईं। किरनापुर थाना क्षेत्र के कितनी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले बोरवन के जंगल में पुलिस और नक्सलियों में भिड़ंत हुई है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से रसद और 12 बोर का राइफल बरामद हुआ है। दोनों महिला नक्सलियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि रात में हुई मुठभेड़ में मलाजखंड आलम से जुड़ी महिला नक्सली शोभा मारी गई। वहीं, सुबह सर्चिंग के दौरान एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें दररेक्सा दलम की महिला नक्सली सावित्री मारी गई। इससे पहले 7 नवंबर को भी बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क के पास मालखेड़ी के जंगल में जवानों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर किया था। ये महिला नक्सली खटिया मोचा दलम दो की बताई गई थी। पुलिस को उस दौरान भी सूचना मिली थी कि 25 से 30 नक्सली दो अलग-अलग जगहों पर हैं। टीम मौके पर पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की थी।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एजेंसियों के दबाव के बाद मप्र के विस्तार इलाके में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है। खासतौर पर कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व में पिछले दो-तीन माह में इन्हें देखा गया है। मुकी क्षेत्र व मंडला में इनकी गतिविधियां हैं। इसी को देखते हुए जनवरी-फरवरी में सीआरपीएफ की छह कंपनियां मंडला-बालाघाट में तैनात की जाएंगी। इनमें 75 फीसदी लड़ाकू जवान होंगे। नवंबर में कान्हा के बफर क्षेत्र में एक नक्सली ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा चुका है। नक्सली गतिविधि बढ़ने के कारण हॉकफोर्स का मुख्यालय बालाघाट शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें 5 दिसंबर को ही आईपीएस नागेंद्र सिंह और सहायक पुलिस निरीक्षक घनश्याम मालवीय की पोस्टिंग की गई है।

दो साल बाद यह स्थिति बनी है कि मप्र के छग के सीमावर्ती इलाके में नक्सली देखे गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक दिन पहले हुए ऑपरेशन में मारी गईं मप्र, छग और महाराष्ट्र की इनामी नक्सली शोभा और सावित्री का मूवमेंट कान्हा में ही देखा गया था। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों के कारण मंडला के वन क्षेत्र में कटाई कुछ दिन प्रभावित रही। बहरहाल, अब गृह विभाग ने मंडला और बालाघाट में सर्विलांस बढ़ा दिया है। कान्हा रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह को मूवमेंट की जानकारी नहीं है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) असीम श्रीवास्तव ने भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता।

नक्सलियों के अभियान को कमजोर करने के लिए मंडला में ही तीन एकलव्य स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। ताकि युवाओं व किशोरों को उनके संपर्क में आने से रोका जा सके। एडीजी, नक्सल ऑपरेशन जीपी सिंह कहते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व में मूवमेंट छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ बढ़ा है। नवंबर में रिजर्व के बफर क्षेत्र में एक ऑपरेशन किया जा चुका है। सर्विलांस तेज है। एक्सट्रा फोर्स बुलवाई जा रही है। बस्तर और गढ़चिरौली में कार्रवाई जारी है, इसीलिए कुछ ने रुख मप्र की तरफ किया है।

कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे छत्तीसगढ़ बार्डर में 10 किमी के करीब मप्र का छत्तीसगढ़ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही गढ़चिरौली में भी मप्र की टीम गई है। नक्सलियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लोगों की संख्या ज्यादा है। मप्र के फिलहाल पांच नक्सलियों की ही सूचना मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मप्र में नक्सली लोगों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सरकार ने गलत ढंग अपनाया। इसी वजह से लोगों के रोजगार चले गए। हालांकि अभी तक पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लोगों पर इसका असर हुआ।

● **प्रवीण कुमार**

डकैतों को खोजने के लिए बने थाने अब ढूंढ़ रहे चोरी हुए मवेशी

डकैतों के लिए बदनाम ग्वालियर-चंबल अंचल में अब कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। 1980-90 में दस्युओं का भय बस्तियों से लेकर बीहड़ और जंगलों तक ऐसा था कि राज्य सरकार को इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा एंटी डकैत (एडी) थाने व पुलिस चौकियां बनानी पड़ीं। इनका एकमात्र काम डकैतों पर अंकुश लगाना था। बीते एक दशक से चंबल में कोई डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है, फिर भी एडी थाने, चौकियों से लेकर हर जिले में एडी टीम तैनात है। हाल यह है कि अब यह टीम चोरी गए भैंस, बकरियों को ढूंढती है। यही नहीं, एंटी डकैत टीमों को आधुनिक हथियार व अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल ही में ऐसा ही एक रोचक मामला सामने आया। मुरैना जिले की पहाड़गढ़ जनपद के कहारपुरा गांव निवासी बलराम पुत्र छीतरिया बाथम को 23 नवंबर को कुछ बदमाशों ने बांध दिया और उसकी 28 बकरियों को हांक ले गए। पहाड़गढ़ व निरार एंटी डकैत थाना के अलावा एसपी अनुराग सुजानिया ने एडी की 14 सदस्यीय टीम को बकरियां ढूंढने के काम में लगाया। टीम ने दस दिन बाद इन बकरियों को ग्वालियर जिले में तिघरा के पास ढूंढ निकाला। यह एक बानगी मात्र है। मुरैना जिले में एडी थाने पहाड़गढ़, निरार, चिन्नौनी, बागचीनी, देवगढ़ और कन्हार चौकी का स्टाफ सबसे ज्यादा भागदौड़ चोरी हुए मवेशियों के लिए करता है। ग्वालियर-चंबल संभाग के भिंड, श्योपुर, दतिया व ग्वालियर जिलों की एडी टीम व अधिकांश एडी थाने इसी तरह के छोटे-मोटे अपराधों को सुलझाने में व्यस्त हैं।

अनाज खरीदी में 'खेल'

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली अनाज खरीदी में पड़ोसी राज्यों से आने वाला अनाज मप्र के लिए मुसीबत बन रहा है। मुरैना में बाजरा की रिकॉर्ड आवक हो रही है। इससे आशंका बढ़ रही है कि राजस्थान के धौलपुर से तो व्यापारी किसानों के नाम पर बाजरा नहीं बुला रहे हैं। इसी तरह रीवा के त्योंथर और बालाघाट के धानेगांव में उप्र से धान बुलवाया गया है। सीमावर्ती जिलों में यह समस्या अधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा में भी यह बात सामने आई है। इसके मद्देनजर अब कलेक्टरों ने सीमाओं पर नाके लगाने के साथ खरीदी केंद्रों की जांच भी शुरू करा दी है। मप्र में अब तक 97 हजार मीट्रिक टन बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। 30 नवंबर को बाजरा उपार्जन केंद्रों में 900-900 गठान बारदाने, 1 और 2 दिसंबर को 500-500 गठान बारदाने उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी 9 हजार 638 किसानों से बाजरा खरीदना बाकी है। करीब 38 हजार 400 किसानों ने इस मौसम में समर्थन मूल्य पर बाजरा बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था।

सूत्रों के मुताबिक मुरैना में इस बार बाजरा की बंपर आवक हो रही है। अभी तक 30 हजार टन की आवक होती थी। पहले लक्ष्य बढ़ाकर 75 हजार टन किया लेकिन यह भी कम पड़ने लगा तो इसे फिर बढ़ाकर एक लाख और अब सवा लाख टन किया है। बताया जा रहा है कि मुरैना से राजस्थान का धौलपुर लगा है और वहां बाजरा की खेती होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरा मप्र में खरीदा जा रहा है। जबकि, बाजार में यह 1,500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि सीमावर्ती गांवों के किसानों के माध्यम से राजस्थान के व्यापारी बाजरा बिकवा सकते हैं। यही कारण है कि मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नाके लगवाकर जांच बढ़वा दी है।

दतिया, रीवा और बालाघाट में उप्र से धान लाने की बात सामने आई है। रीवा के त्योंथर में 500 क्विंटल तो बालाघाट के धानेगांव में 270 क्विंटल धान पकड़ी गई है। दतिया में भी उप्र से धान आने की सूचनाएं मिल रही हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर संजय कुमार ने नाकेबंदी करा दी है। उन्होंने बताया कि इस समस्या की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीमावर्ती स्थानों पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक तरुण कुमार पिथोड़े का कहना है कि सभी कलेक्टरों को सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि पड़ोसी राज्यों से फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने के लिए न आ सकें। उधर, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि मुरैना में खरीदी एकदम से बढ़ी है। बारदाने की कमी को दूर कर लिया है। अन्य राज्यों से फसल न आए, इसके प्रबंध कलेक्टरों ने किए हैं। जहां भी शिकायतें आ रही हैं, वहां जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

सूत्रों का कहना है कि बाजरा की कीमत बाजार में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। जबकि समर्थन मूल्य 2,150 रुपए है। इसलिए व्यापारी किसानों के नाम पर दूसरी जगह से उपज लाकर समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। इसमें किसान के साथ-साथ खरीदी केंद्र के कर्मचारी और पटवारी की भी भूमिका रहती है। दरअसल, ई-उपार्जन व्यवस्था में किसान का पंजीयन होता है। इसमें उन किसानों के नाम भी दर्ज हो जाते हैं, जिन्होंने संबंधित फसल की खेती ही नहीं की होती है।

ग्वालियर-चंबल अंचल में किसान और प्रशासन इन दिनों एक और नई समस्या से जूझ रहा है। इसकी वजह उपज की तुलना में खरीदी केंद्रों पर खरीदी के बावजूद हजारों किसान ऐसे हैं, जिनका बाजरा प्रशासन खरीद नहीं पाया है। इसका कारण मप्र में बाजरे का समर्थन मूल्य (2,150 रुपए) बाजार मूल्य करीब 1,500 रुपए से अधिक है। उप्र और राजस्थान से सटे होने के कारण भिंड-मुरैना, दतिया और शिवपुरी में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं, जो खरीदी केंद्रों पर बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं। इन जिलों में हजारों क्विंटल बाजरा पकड़ा भी गया है। इसके बावजूद खरीद केंद्रों पर बाजरे से भरे वाहनों की कतार लगी हुई है।

● **नवीन रघुवंशी**

मुरैना में बोरियों में अंकुरित हो चुके बाजरे को गोदामों में रखवा रहीं सोसायटी

बारिश से भीगे बाजरे को सोसायटियों ने खरीद लिया और बोरों में भर दिया। अब यह बाजरा बोरों के अंदर ही अंकुरित हो गया है और जब इन बोरों को गोदामों में भेजा जा रहा है तो यह गड़बड़ पकड़ में भी आ रही है। नजीता गोदामों के बाहर भीगे व अंकुरित हो चुके बाजरे के बोरों के ढेर लगवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 14-15 नवंबर की रात मुरैना जिले में बारिश और कहीं-कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। इस कारण मुरैना, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ के खरीदी केंद्रों पर हजारों बोरे बाजरा भीग गया। मुरैना व कैलारस की सोसायटियों पर तो भीगकर गीला हुआ बाजरा तीन दिन बाद अंकुरित भी हुआ। इसके अलावा किसानों का भी हजारों क्विंटल बाजरा भीग गया। इस गीले और अंकुरित बाजरे को सोसायटियों ने खरीद डाला जबकि समर्थन मूल्य खरीदी के लिए तय एफएक्यू (फाइन एवरेज क्वालिटी) मानक जरूरी है। इसमें अनाज की नमी, उसका आकार, मिलावट व चमक तक देखी जाती है। अब सोसायटियों से जो बाजरा बोरों में भरकर गोदामों में रखने पहुंच रहा है तो तब गोदामों पर हो रही जांच में बाजरा गीला व अंकुरित पाया जा रहा है। सेंट्रल वेयर हाउस मुरैना के गोदामों पर भैंसरोली सोसायटी से बोरे पहुंचे हैं उनके अंदर अंकुरित हुआ बाजरा बोरों से बाहर निकल आया है। इसी तरह धनेला सोसायटी, उधर कैलारस की मामचौन, पचोखरा व कैलारस मार्केटिंग सोसायटी ने भी गीले बाजरे को खरीदकर बोरों में भर दिया है।

समस्या बन रहे जंगली हाथी

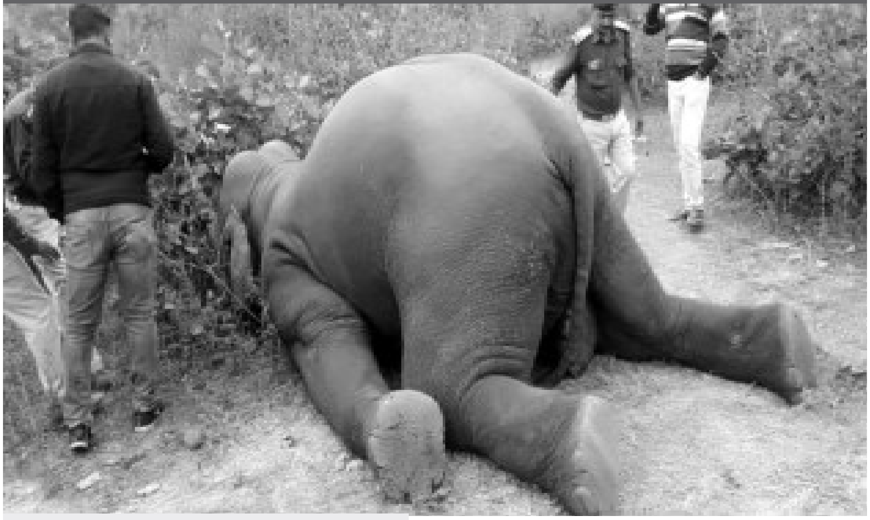

बरगी के मोहास में बलराम हाथी (20) की शिकारियों द्वारा बिछाए गए करंट से मौत के बाद साथी हाथी राम बेकाबू हो गया है। वह काफी गुस्से में दिख रहा है। मंडला के बीजाडांडी वन परिक्षेत्र में उसने दो ग्रामीणों पर हमला किया। एक ग्रामीण के घर की बाड़ी में घुसकर नुकीले दांतों से पीठ पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं खेत की रखवाली कर रहे दूसरे ग्रामीण को सूंड से धक्का दे दिया। गुस्साए हाथी ने उसे रौंदने का भी प्रयास किया, लेकिन उसने भाग कर जान बचाई। सीसीएफ जबलपुर एचडी मेहिले के मुताबिक खतरनाक हो चुके राम का रेस्क्यू करने के लिए कान्हा व पेंच के डायरेक्टर मंडला वन विभाग की टीम के साथ उसे ट्रेंक्युलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडला डीएफओ कमल अरोड़ा के मुताबिक राम हाथी की लोकेशन टिकरिया रेंज में मिली है। कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर एसके सिंह और पेंच के विक्रम सिंह परिहार की अगुवाई में वन विभाग की **टीम टिकरिया रेंज** में पहुंच चुकी है। ट्रेंक्युलाइज कर हाथी का रेस्क्यू किया जाएगा। उसे पकड़कर कान्हा नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। कर्नाटक के विशेषज्ञों से भी बातचीत चल रही है। यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बुलाया जाएगा।

ग्रामीणों से मिले राम-बलराम के उपनाम वाले दोनों जंगली हाथियों ने अप्रैल 2020 में सिवनी में महुआ फूल एकत्र कर रहे घंसोर तहसील में एक ग्रामीण को मार डाला था। इसके बाद दोनों के द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। ओडिशा से भटककर कान्हा आए 20 हाथियों के झुंड से राम-बलराम भटक कर सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। 24 नवंबर को दोनों नर्मदा के किनारे से होते हुए बरेला में प्रवेश किए थे। वहां से दोनों 25 को बरगी में, 26 को मंगेली में दिखे थे। 27 नवंबर को बलराम हाथी का शव मोहास गांव के पास कैनाल किनारे मिला था। जंगली सुअर के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से उसकी मौत की पुष्टि पीएम रिपोर्ट में हुई है। इसके बाद से राम हाथी की तलाश चल रही थी।

छत्तीसगढ़ के रास्ते आने वाले जंगली हाथी मप्र के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। उमरिया व सीधी जिलों में 54 हाथियों ने ढाई साल से डेरा डाल रखा है। ये हाथी अपने रास्ते में आने वाले खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को उजाड़ रहे हैं और अब तक अलग-अलग घटनाओं में आधा दर्जन लोगों को मार चुके हैं, पर राज्य सरकार के पास हाथियों को काबू में करने का कोई प्लान नहीं है। इस समस्या को लेकर राज्य सरकार को अब तक केंद्र सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली है। राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश को हाथी परियोजना में शामिल करने की मांग की है।

हाथी एक दशक से मप्र आ रहे हैं, पर कुछ दिनों में लौट भी जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ढाई साल पहले आए 40 हाथियों के एक झुंड ने उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ क्षेत्र को अपना स्थाई ठिकाना बना लिया है। वे टाइगर रिजर्व और उसके बाहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे ही आठ हाथियों का एक झुंड सीधी जिले में स्थित संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास सक्रिय हैं। दो नर हाथी तो प्रदेश के लगभग मध्य में स्थित नरसिंहपुर जिले में पहुंच गए थे। जिनमें से एक की पिछले दिनों करंट से मौत हो गई और दूसरे की बरगी क्षेत्र और उसके आसपास ड्रोन और पदचिन्ह की मदद से तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि ये हाथी ओडिशा और झारखंड के हैं तथा छत्तीसगढ़ के रास्ते यहां आते हैं।

वन विभाग को जब हाथियों से बचने का उपाय नहीं सूझा तो वनकर्मियों और हाथियों के रास्ते में बसी बस्तियों के लोगों को हाथियों से बचने के लिए तैयार करने की कोशिशें शुरू हुई हैं। जिन क्षेत्रों में **हाथी** सक्रिय हैं, उन क्षेत्रों के वनकर्मियों और ग्रामीणों को हाथियों के साथ रहने का सबक सिखाया जा रहा है। इसके लिए पिछले साल पश्चिम बंगाल से हाथी विशेषज्ञ बुलाए गए थे। उन्होंने तीन दिन रुककर वनकर्मियों को प्रशिक्षित किया। ये वनकर्मी आसपास के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाथियों से संबंधित कुछ और बारीकियां जानने के लिए विशेषज्ञों को फिर बुलाने की योजना है।

जंगल और जंगल के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों को बताया गया है कि खड़ी लालमिर्च भरकर गोबर के गोले बनाएं और पटाखे घर में रखें। हाथियों का दल जब नजदीक आ जाए तो पटाखे चलाएं और गोबर के गोलों में आग लगाकर उनकी ओर फेकें। इससे वे दूर हटेंगे। प्रदेश के वन अधिकारी हाथियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर उनके ओडिशा, झारखंड छोड़कर मप्र आने का कारण यहां की प्राकृतिक संपदा को बताते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हाथी वैसे तो झाड़ियों में रहते हैं, पर उन्हें भी खुले घास के मैदान पसंद हैं। शायद इसीलिए प्रदेश पसंद आ गया। यहां खाने के लिए वनस्पति भी भरपूर है।

● **अरविंद नारद**

खनन के चलते कम हो रहे वन क्षेत्र से पलायन

कुछ समय पहले तक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जंगल में ही हाथी दिखते थे। वहां से वे निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। पहली बार ये हो रहा है कि उनका पलायन मप्र की ओर हुआ है। माना जा रहा है कि इन राज्यों में बढ़ते खनन से जंगलों का दायरा सिमट रहा है। इस कारण हाथी नए रहवास की खोज में पलायन करने पर विवश हुए हैं। ओडिशा से अप्रैल में 20 हाथियों का झुंड भटककर कान्हा पहुंचा था। सितंबर में इनका पलायन सिवनी से मंडला के जंगलों की ओर हुआ। दो महीने तक वे मंडला के जंगल में ही रहे। इसके बाद दो हाथी भटककर नर्मदा तीरे-तीरे जबलपुर की ओर बढ़ गए। वहीं झुंड के अन्य हाथी वापस कान्हा की ओर लौट गए। चार दिन पहले दोनों हाथियों ने बरेला क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब से वन विभाग के 25 सदस्यों की टीम उनकी निगरानी में लगाई गई थी। गत दिनों दोनों हाथी बरगी में पहुंचे थे। वहां से दोनों ग्वारीघाट के दूसरी ओर मंगेली में देखे गए थे।

फिर उठी अलग राज्य की मांग

विकास की राह से भटका हुआ वह भूभाग जिसने अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री तक दिए लेकिन हर बार सरकारों ने इस क्षेत्र को विकास और इसकी आहटों से दूर रखा हालांकि लंबे वक्त से लंबित मांग अब सरकार द्वारा पूरी करने की कवायद शुरू की जा रही है लेकिन इस कवायद के साथ ही राजधानी को लेकर लोग आक्रोश में है। दरअसल सरकार की मंशा है कि वह प्रयागराज को बुंदेलखंड की राजधानी बनाए मगर लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पहले से ही विकसित प्रयागराज क्षेत्र पर तो सरकारी कृपा बरसेगी लेकिन कोर बुंदेलखंड का क्या होगा?

अगर सूत्रों की मानें तो अब वह दिन दूर नहीं जब भारत में नए राज्य का गठन किया जाएगा। जल्द ही भारत में एक नए राज्य बुंदेलखंड की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है। जिसके लिए कई दशकों से लगातार मांग और आंदोलन इत्यादि चल रहे थे हालांकि इसमें कई पेंच हैं लेकिन इन पेंचों के बावजूद भी मप्र और उप्र के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है इससे यह समझ में आता है कि अगर सरकारें चाहें कि राज्य का गठन हुआ है तो ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है।

उप्र और मप्र का ऐसा भूभाग जो पूर्व में बुंदेली शासन में रहे या दूसरे शब्दों में ऐसा क्षेत्र जो बुंदेला राज्य में रहा वह बुंदेलखंड में माना जाता है। हालांकि सरकारी बुंदेलखंड और लोगों द्वारा स्वघोषित बुंदेलखंड में काफी अंतर है। दरअसल मूल रूप से लोगों द्वारा यह माना जाता है कि उप्र-मप्र का एक निर्धारित क्षेत्र है जिसमें संस्कृति, भाषा, संस्कार, रहन-सहन के साथ-साथ वैवाहिक संबंध बनते हैं, वह बुंदेलखंड है। अगर इस दृष्टि से देखें तो उप्र के महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट और हमीरपुर शामिल हैं। वहीं मप्र से छतरपुर, पन्ना, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, भिंड, सतना इत्यादि जिले शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में भाषायी समानता के साथ-साथ संस्कृति का भी बेहद मिला-जुला रूप नजर आता है लेकिन अगर वर्तमान सरकार का प्लान सोचें तो इसमें मप्र के जबलपुर समेत उप्र के प्रयागराज जिले को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है।

दरअसल सरकार जिस बुंदेलखंड के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है उसमें प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) को बुंदेलखंड राज्य की राजधानी बनाने के मूड में है, लेकिन सरकारों के इस काम को लेकर बुंदेली मड़ई काफी आक्रोश में है। लोगों का मानना है कि अगर बुंदेलखंड की राजधानी प्रयागराज हुई तो उनके लिए सास मरी और बहू के बिटिया हुई वाली कहानी साबित होगी। लोगों का कहना यह है कि अभी उन्हें अपने विकास के लिए प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ के मुंह की तरफ देखना पड़ रहा है। कल उन्हें प्रयाग की तरफ देखना पड़ेगा और यह हर प्रकार से बुंदेली समाज के खिलाफ एक साजिश है। जिससे बुंदेली लोगों को जानबूझकर पूर्वांचल के ऊपर निर्भर किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड खनिज संपदा के लिए स्वर्ग है इस प्रकार से बुंदेलखंड का दोहन बरकरार रहेगा और इसका मुफ्त में लाभ प्रयाग उठाएगा।

उप्र सरकार ने 7 जनपदों क्रमशः झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट एवं महोबा को मिलाकर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया है। इसी प्रकार मप्र सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया एवं निवाड़ी को मिलाकर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इन्हीं समस्त जिलों को बुंदेलखंड मानकर केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। इन क्षेत्रों के साथ लहार, पिछोर, करेरा, गोहांड, चंदेरी, गंजबासौदा, कटनी, सतना का चित्रकूट आदि क्षेत्रों को जोड़कर अखंड बुंदेलखंड राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। देश की आजादी के 73 वर्ष बाद भी देश के हृदय स्थल बुंदेलखंड को सरकारी दस्तावेजों में अति पिछड़ा क्षेत्र लिखा जाता है जो सरकारों के विकास के नजरिए को दर्शाता है। बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने के वादे के 6 साल 4 माह पूरे हो गए हैं परंतु अभी तक केंद्र सरकार में राज्य निर्माण की कार्यवाही तक प्रारंभ नहीं हुई है।

उधर, उप्र के झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा (बुनिमो) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड राज्य की अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए गत दिनों जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की। बुनिमो अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया था लेकिन आज 6 साल 6 माह हो गए हैं कुल मिलाकर दोगुने से ज्यादा समय बीत चुका है और इनको अपने वादे की कोई परवाह नहीं है। इनकी दोमुंही राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस सरकार को चुनाव में वोट लेने के लिए बुंदेलखंड राज्य की याद आती है और सत्ता में आकर यह वादा बिसरा कर अपने काम में लग जाते हैं। इस व्यवहार को बुंदेली अब बर्दाश्त नहीं कर सकते।

● राकेश ग्रोवर

नई नहीं है राज्य की कल्पना

ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड राज्य किसी कल्पना का अंग हो। दरअसल बुंदेलखंड राज्य अपने आप में एक राज्य रह चुका है। आजादी के बाद 12 मार्च 1948 को संविधान सभा द्वारा बाकायदा इस बुंदेलखंड राज्य का गठन किया गया था जो लगातार 8 वर्ष और 7 माह तक एक राज्य की भांति रहा। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी कामता प्रसाद सक्सेना रहे लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य का विलय उप्र और मप्र में कर दिया गया था। बुनिमो अध्यक्ष ने कहा कि अगले चुनाव में बुंदेलियों का नारा होगा- 'जो बुंदेलखंड की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा।' हम इस सरकार के दोगले नुमाइंदो को सत्ता से बाहर करेंगे, यह केवल चुनावी बुंदेली हैं। हम लोग चुनाव में असली बुंदेली के साथ खड़े नजर आएंगे। अब बुंदेली, जनप्रतिनिधियों के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। बुंदेलखंड राज्य हमारा सपना है यह हमारी आन है, बान है और हमारी शान है। इसके साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बुंदेलखंड तो हम लेंगे ही और जैसे दोगे वैसे लेंगे।

किसानी के असली मर्ज भी तलाशिए

भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। इसकी वजह है सरकार की नीति और नीयत में अंतर। इसी का परिणाम है कि आजादी के 73 साल बाद भी देश का किसान खुशहाल नहीं हो पाया है। सरकार ने किसानों में खुशहाली लाने के लिए जिस नए कृषि कानून को लागू किया है, उसे किसान कॉरपोरेट हितैषी मान रहे हैं। इस कानून के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार की एक नहीं सुन रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा हमेशा बदलाव को आवाज देती है। जब तंत्र बेदम हो जाए तो इसे समाप्त कर एक नए जीवन तंत्र की स्थापना के सपनों को साकार कर पाना ऐसी क्रांति कहलाता है, जिसका युगों से पददलित इंतजार करते हैं। जब वक्त आता है तो इसके लिए संघर्ष करते हैं, जूझ मरते हैं। कुछ ऐसे ही संघर्ष का आव्हान सितंबर अंत से पंजाब और हरियाणा से उभरते हुए उस किसान आंदोलन से मिला, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पैदल या अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सवार होकर देश की राजधानी की सीमा की ओर कूच कर गए। इनके साथ उप्र और राजस्थान के किसानों ने भी स्वर मिलाया। यह एक अजब शांतिप्रिय अनुशासित आंदोलन है, जिसका विश्वभर में संज्ञान लिया गया। दिल्ली सीमा का घेराव करते हुए आंदोलनकारी अपनी बेहतरी के लिए बनाए गए कानूनों को किसान विरोधी बताकर उन्हें बदलने की बात कर रहे थे।

संसद ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए हैं

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे के साथ सरकार ने किसानों के लिए तीन नए कानून बनाए हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं। लेकिन किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता है। कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम देखने को मिले। इस एक कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। जीएसटी को भारत की आर्थिक आजादी के रूप में दिखाया गया। दो फीसदी जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया। जीएसटी आधी रात में आ तो गया। लेकिन, कभी जीडीपी को ऊपर नहीं बढ़ा पाया। अलग से अर्थव्यवस्था को और नीचे लेकर चला गया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश में महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ। लेकिन, हजारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर खत्म हो गईं। लाखों नौकरियां चली गईं। अर्थव्यवस्था निगेटिव हो गई। अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। सदन में तमाम हो-हल्ले के बीच किसानों की नई आर्थिक आजादी की कहानी लिखी जा चुकी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लाए गए सुधारों को नई आजादी के रूप में प्रचारित किया है। लेकिन, सच कितना है, इसे लेकर कई सवाल हैं। कानून को लेकर किसान जिस तरह आंदोलन पर अड़े हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वे कानून को हर हाल में निरस्त कराना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार तीन नए कानूनों को खत्म कर दे, तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। उनको आशंका है कि इन कानूनों के कारण वे अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। अब देखना यह है कि किसान और सरकार के बीच में चल रही यह लड़ाई किस मुकाम पर पहुंचकर खत्म होती है।

सरकार से उनकी बात दर बात होती रही। जो कानून उनकी आय को दोगुना करने के लिए बनाए गए थे या फसलों की खरीद-बेच को शोषण रहित बनाने के लिए एक नियमित मंडियों के साथ वैकल्पिक निजी मंडियों की स्थापना का उद्घाटन थे, उन्हीं को आक्रोशित धरती पुत्र कह रहे हैं कि देश के 80 प्रतिशत अढ़ाई हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को **कॉरपोरेट** घरानों के रहमोकरम पर छोड़ा जा रहा है। बदलाव का नाम लेकर उन्हें एक छद्म परिवर्तन के समक्ष बंधक बनाया जा रहा है। यह एक अजब स्थिति है, जिसमें दोनों पक्ष अपने आपको सही और दूसरे को गलत, अपने आपको बदलाव से प्रतिबद्ध और दूसरे पक्ष को **प्रतिक्रियावादी** बता रहे हैं। दोनों ओर से संवाद की स्थिति का आव्हान हो रहा है, लेकिन कोई पक्ष भी लोचशील होकर किसी सर्व स्वीकार्य निर्णय को अपनाने के लिए तैयार नहीं।

निश्चय ही किसानों के इस क्रांति मार्च और घेराव को यह कहकर नकारा नहीं जा सकता कि उन्हें कानून समझने में भूल हो गई है। क्या कहीं न कहीं इस बदलाव के लिए चिल्लाते लोगों के मन में यह धारणा नहीं पैठ गई कि फसल उगने और बेचने वालों के सामने खरीदने वालों की ताकत कहीं अधिक है और वे अपनी शर्तों पर उनकी फसलें खरीद लेंगे, जो उनकी मेहनत या लागत का पूरा मूल्य नहीं देगी। वे लोग इसीलिए हर मंडी चाहे वह नियमित हो या निजी में एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, या उसके लिए कानून बना देने का हठ कर रहे हैं। कानून बनाने वाली सरकार की बाध्यता यह है कि अगर न्यूनतम कीमत की गारंटी ही दे दी तो कौन-सा निजी कॉरपोरेट घराना इन फसलों की ओर आएगा, जो उन्हें मांग और पूर्ति के खुले खेल के बिना निश्चित कीमतों के साये तले लाभप्रद नहीं लगेंगी। इसकी जगह वे क्या देश के दूसरे राज्यों में नकद फसलों की खेती की ओर नहीं चले जाएंगे? एमएसपी की गारंटी मिल भी गई, तो किसानों को ग्राहक न मिलने की शिकायत पैदा हो जाएगी। यह शिकायत पुरानी है। इससे पहले शांता कुमार कमेटी का सर्वेक्षण भी यही बता गया कि जब इन नए कानूनों की वैकल्पिक मंडी व्यवस्था नहीं थी, एएमपीसी की पुरानी खरीद प्रणाली थी, तब भी किसान अपनी फसलों का 6 प्रतिशत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते थे।

पहले भी अपनी आर्थिक दुरावस्था के कारण इन्हें अपनी फसलों को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता था, अब भी बेचना पड़ेगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को उसकी फसल लागत और 50 प्रतिशत लाभ की शर्त पहले भी थी, अब भी मांगी जा रही है। लेकिन झंझट यह है कि परंपरागत धान और गेहूं के फसल चक्र का अनुसरण ही पंजाब और हरियाणा में होता रहा है, अब भी हो रहा है। इसलिए कुल उत्पादन मांग से कहीं अधिक हो जाता है। अब आपूर्ति अधिक और मांग कम, इसलिए अर्थशास्त्र के सादे संतुलन सिद्धांत के मुताबिक कीमत तो कम मिलेगी, चाहे जितनी भी एमएसपी की गारंटी दे दी जाए।

शोषण का डर

आय बढ़ाने का तो एक ही सीधा उपाय यहां है और वह है फसलों का वैविध्यकरण और जीवन-निर्वाह फसलों के स्थान पर नकद एवं व्यावसायिक खेती को अपनाना। जिन राज्यों ने फसल विविधता के इस चक्र को अपना लिया है, वहां इसीलिए उन्हें इस आंदोलन में एक प्रतिबद्धता के साथ कूदते नहीं देखा गया, जितना कि पंजाब और हरियाणा के परम्परागत फसल चक्र वाले किसान सामने आए। किसान की

किसानों को मोहरा बना रहे राजनीतिक दल

देश के किसानों के हितों और उनकी स्थिति में सुधार को लेकर जितना काम बीते पांच-छह साल में हुआ है, उतना उससे पहले कभी नहीं हुआ। खेती-किसानी की लागत कम करने से लेकर उनके लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इन दिनों जिन तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के कुछ किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, दरअसल वे भी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से ही लाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दल राजनीतिक स्वार्थ के चलते इनका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में आज की तारीख में ये सभी दल अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और जनता का विश्वास उन पर से उठ चुका है। इसलिए मुद्दों से विहीन ये पार्टियां कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। जबकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में इन्हीं दलों ने कृषि और मंडी कानूनों में बदलाव की शुरुआत की थी, जिसे मौजूदा सरकार ने केवल परिणति तक पहुंचाया है। अगर 2014 से पूर्व मंडी कानून में बदलाव किसानों के हित में थे तो 2020 में ये किसान विरोधी कैसे हो गए?

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने शोषण का डर एवं धनाढ्य खरीदारों द्वारा जमाखोरी की बंदिश खुल जाने के बाद उनके द्वारा अनुचित लाभ और किसान की आय का वहीं का वहीं रह जाने का संशय अनुचित नहीं और इसीलिए उनके आंदोलन को इसकी तीखी धार भी मिली है। लेकिन समय की परख बताती है कि किसानों का आर्थिक **कायाकल्प** केवल किसान कानूनों में संशोधन अथवा उनके रद्द करके नए कानून बनाने से नहीं होगा।

ऐसा न हो कि किसानों का एक आंदोलन का अपना-अपना वोट बैंक भुनाने के लिए भी विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिकरण हो जाए। यही बात हर क्रांति आंदोलन को उसकी राह से भटका कर नेताओं की सत्तालिप्सा की ओर धकेल देती है। यह भी सही है कि अभी तक किसानों का यह क्रांति आंदोलन एक साफ-सुथरे और अनुशासित ढंग से चलाया जाता रहा, लेकिन भारत बंद और टोल फ्री आवागमन और भूख हड़ताल की घोषणाओं ने जहां इसका राजनीतिकरण हो जाने की संभावना बढ़ा दी, वहां अराजक तत्वों और देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ के लिए भी चोर दरवाजे खुलने का अंदेशा है। जरूरी है कि हर तरह के राजनीतिक हठ को त्याग कर जल्द से जल्द एक नई समझ और समझौता पैदा किया जाए, ताकि नवजागरण का ध्वजवाहक यह आंदोलन अपनी असफलता के बीज स्वयं ही बोने न लगे। यह भी न भूला जाए कि भारत की सरहदों पर शत्रु और आतंकी घात लगाए बैठे हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अगर यह उद्वेलन चलता रहता है, तो इनके लिए भारत विरोधी खेल खेलने के लिए एक खुला और उपजाऊ मैदान मिल जाएगा।

संविधान का अपहरण

देश की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा हमारे किसान या कृषि सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। किसानों का आर्थिक कायाकल्प ही उसकी सब समस्याओं का संपूर्ण हल है। तब तक किसान कानूनों के संशोधन का झगड़ा उनके किसी काम न आएगा। फसलों का वैविध्यकरण, कृषि संबंधित सेवाओं का विनिर्माण और ग्रामीण युवा शक्ति को खेतीबाड़ी में अपने नए जीवन की तलाश करने का संदेश ही उनका मुक्ति प्रसंग है, न कि अराजक हो सकने वाले आंदोलनों की उथल-पुथल।

संविधान विशेषज्ञों की दलील है कि केंद्र के ये तीनों कानून संविधान के संघीय चरित्र का घोर उल्लंघन हैं। कृषि हमेशा राज्य सूची का विषय रहा है और केंद्र के पास समवर्ती सूची में भी कृषि के मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सांसद तथा वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी कहते हैं, 'नए कानून के जरिए केंद्र ने राज्यों को राज्य सूची के तहत अनुसूची 14,18, 46, 28 के तहत प्रदत्त विशेष अधिकारों का अपहरण करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं, वह वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। ये कानून राज्यों को शुल्क या लेवी के जरिए राजस्व जुटाने से वंचित करते हैं। इसलिए ये तीनों कानून सत्ता के बंटवारे को चुनौती देते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है।'

तुलसी की दलील है, इन कानूनों के विवाद निपटाने के प्रावधान यह भी साफ नहीं करते कि विवाद की स्थिति में संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। फिर, कानून कृषि करार में सुलह की प्रक्रिया के अभाव में विवाद निपटाने का बोझ भी पहले से काम से लदे अनुमंडलाधिकारी (एसडीएम) पर डाल देता है। कानून के प्रावधानों में सबसे अमानवीय तो किसान से अपील करने का अधिकार छीन लेना है। लगता है कि राज्य नौकरशाहों की फौज के जरिए अपनी ताकत के इजहार में खुद को ईश्वर समझ बैठा है, जो हर तरह के सवाल और चुनौती से परे है। ऐसे में, अगर उच्च अधिकारी का फैसला भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह या महज तुनकमिजाजी की वजह से पक्षपाती हो, तो उसके खिलाफ किसान को कोई अधिकार न होना अजीबोगरीब है।

नए कानून का क्या होगा असर ?

यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं हैं और न ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेनदेन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वह बाजार में दखल करने के लिए कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। यह कानून तो दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा। एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं। लेकिन, सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में पांच आढ़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे। किसानों को परेशानी होती थी। लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात ही नहीं कही गई है।

मंडी व्यवस्था में कमियां थीं। बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां हैं तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतजार इसलिए

भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं हैं। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार, हर 5 किमी के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में कुल 7000 मंडियां हैं, लेकिन जरूरत 42000 मंडियों की है। आप इनका निर्माण करें। कम से कम हर किसान की पहुंच तक एक मंडी तो बना दें। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं। क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समानांतर निजी संसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों?

जिम्मेदारी से बचना चाहती है सरकार?

आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रीटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समानांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल समाप्त हो गई। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने-पौने दाम पर फसल बेचेगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन की 1 प्रतिशत ही सरकारी खरीद हो पाई। बिहार में यही एपीएमसी कानून तो 2006 में ही खत्म किया गया था। सबसे कम कृषि आयों वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है। लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहां खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बनाया हो।

सरकार कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा। यह दीर्घकालिक नीति है। लेकिन, बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था तो 2006 में ही खत्म हो गई थी। 14 वर्ष बीत गए। यह लंबा समय ही है। अब जवाब है कि वहां कितना निवेश आया? वहां के किसानों को क्यों आज सबसे कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है? अगर वहां इसके बाद कृषि क्रांति आ गई थी तो मजदूरों के पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा यहीं क्यों दिखा? क्यों नहीं बिहार कृषि आय में अग्रणी राज्य बना? क्यों नहीं वहां किसानों की आत्महत्याएं रुकीं? कई सवाल हैं।

दूसरा कानून है- 'कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020'। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। यह तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। चलिए हम मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं। लेकिन, कानून में किसानों को दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया गया है। सबसे अधिक कमजोर तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद निस्तारण के संदर्भ में है। विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा तो जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति में महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे।

कितना समर्थ है किसान

कानून के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटाए और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए। नहीं हुआ तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। हर जगह एसडीएम अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा-19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वह महीनों लग कर सही दाम हासिल करे? वह तहसील जाने से ही घबराते हैं। उन्हें तो अगली फसल की ही चिंता होगी।

तीसरा कानून है-'आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020'। यह न सिर्फ किसानों के लिए

अपनी शर्तों पर सौदा करने में सक्षम होंगे किसान

तकरीबन यही स्थिति मंडी कानून में हुए बदलाव को लेकर भी है। मंडी कानून में बदलाव कर सरकार की मंशा किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करना है, ताकि किसान अपनी फसलों की बिक्री के लिए केवल मंडी के आढ़तियों पर आश्रित न रहें। इससे किसान न केवल अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य हासिल कर सकेंगे, बल्कि अपनी शर्तों पर सौदा करने में सक्षम भी होंगे। खुद कांग्रेस ने 2004 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद मंडी कानून में बदलाव पर चर्चा शुरू की और इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। आज इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले शरद पवार का राज्यों के साथ 2010 और 2011 में हुआ पत्र-व्यवहार इस बात का गवाह है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार मंडी कानून यानी एपीएमसी (कृषि उत्पाद विपणन समिति) एक्ट में बदलाव के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बना रही थी। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस वक्त इस आशय का एक मॉडल कानून भी राज्यों को भेजा था। विभिन्न संगठनों समेत इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा की प्रक्रिया भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही शुरू की थी। इसी तरह विपक्षी दल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसानों को भड़का रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस प्रावधान के तहत किसानों को अपनी पैदावार का सौदा ही कंपनियों के साथ करना है, जमीन का नहीं। ऐसे में उनकी जमीन छिनने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

बल्कि आमजन के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है? खुली छूट। यह तो जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वह सिर्फ युद्ध या भुखमरी या किसी बहुत विषम परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। सिर्फ दो कैटेगरी में 50 प्रतिशत (होर्टिकल्चर) और 100 प्रतिशत (नॉन-पेरिशबल) के दाम बढ़ने पर रेगुलेट करेगी नहीं बल्कि कर सकती है की बात कही गई है। सरकार कह रही है कि इससे आम किसानों को फायदा ही तो है। वे सही दाम होने पर अपनी उपज बेचेंगे। लेकिन यहां मूल सवाल तो यह है कि देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है? हमारे यहां तो 80 प्रतिशत तो छोटे और मझोले किसान हैं।

आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 से सामान्य किसानों को एक फायदा नहीं है। इस देश के किसान गोदाम बनवाकर नहीं रखते हैं कि सही दाम तक इंतजार कर सकेंगे। सरकारों ने भी इतने गोदाम नहीं बनवाएं हैं। किसानों को अगली फसल की चिंता होती है। तो जो बाजार में दाम चल रहा होगा उस पर बेच आएंगे। लेकिन, फायदा उन पूंजीपतियों को जरूर हो जाएगा जिनके पास भंडारण व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी पूंजी उपलब्ध है। वे अब आसानी से सस्ती उपज खरीदकर स्टोर करेंगे और जब दाम आसमान छूने लगेंगे तो बाजार में बेचकर लाभ कमाएंगे।

किसान को सहारे की जरूरत

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुकी है। यह देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है। शांता कुमार समिति कहती है कि महज 6 फीसदी किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। बाकी 94 फीसदी बाजार और बिचौलियों पर ही निर्भर रहते हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र आय असमानता को सबसे अधिक देख रहा है। इसलिए किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिए जाने की जरूरत है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर न खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करे। यह कितना विचारणीय विषय है कि जो किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है, आज वह अपनी उपज का सही दाम भी हासिल नहीं कर पाता है। देश के किसी किसान या किसान संगठन ने कभी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। किसान और कृषि संगठनों की मांग हमेशा एमएसपी और उसका सी2 के आधार पर निर्धारण, कर्ज मुक्त किसान और 100 प्रतिशत फसल खरीदी की रही है।

यह कानून सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है। कारण है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है और यह समवर्ती सूची में आता है। एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है। इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी हो सकता है। यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर (संघवाद) को कमजोर करने वाला कानून है। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम कर रही है न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए।

दुनियाभर से किसानों को समर्थन

आज सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच से किसान आंदोलन को दुनियाभर में बसे भारतीयों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में बसे या गए भारतीय शामिल हैं। विदेश में मौजूद आप्रवासी किसानों के समर्थन में ऑनलाइन अर्जियों पर दस्तखत कर रहे हैं। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने वहां के विदेश सचिव डॉमिनिक राब को साझा पत्र लिखा कि भारत खासकर पंजाब और दिल्ली के मुहाने पर जुटे व्यापक किसान आंदोलन के प्रति ब्रितानी नागरिकों की चिंताओं को उचित मंच पर उठाया जाए। कनाडा में बड़ी संख्या में मौजूद पंजाबी मूल के वोटरों के मद्देनजर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बयान जारी करने वाले दुनिया के पहले नेताओं में हैं। उन्होंने 4 दिसंबर को दोबारा किसानों का समर्थन दोहराया, 'कनाडा हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता रहेगा। बातचीत की कोशिशों को देखकर हमें खुशी है।' भारत ने कड़ी आपत्ति जारी की कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां दोनों देशों के रिश्ते में खटास पैदा कर सकती हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 7 दिसंबर को कोविड-19 महामारी की रोकथाम की रणनीति तैयार करने के मकसद से कनाडा के नेतृत्व में विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार किया। कनाडा के भारतवंशियों में पंजाब के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का ही असर था कि 5 दिसंबर को पुराने टोरंटो में भारतीय दूतावास के सामने किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

किसान आंदोलन का इतिहास

कहते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है। आज से करीब 32 साल पहले 1988 में 25 अक्टूबर से नवंबर की शुरुआत तक लगभग हफ्ते भर दिल्ली में किसानों की ऐसी ही घेरेबंदी देखी गई थी। तब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के करिश्माई नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में लगभग पांच लाख किसानों ने 35 मांगों की भारी-भरकम फेहरिस्त के साथ बोट क्लब पर लगभग कब्जा जमा लिया था, जिससे कुछ गज की दूरी पर सत्ता-केंद्र नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ संसद भवन है। तब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने ही वाला था। खासकर पश्चिमी उप्र से आए किसानों की बड़ी मांगों में गन्ने की ज्यादा कीमत, बिजली और पानी के शुल्क से मुक्ति जैसे अहम मुद्दे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह गोलबंदी इतनी बड़ी थी कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का पूरा लंबा-चौड़ा इलाका किसानों से पटा पड़ा था। भारतीय किसान यूनियन के उस आंदोलन पर गहरा शोध करने वाली प्रोफेसर जोया हसन कहती हैं, 'टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन दिवंगत राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अहम ताकत का प्रदर्शन था। तब कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज थी। हालांकि, प्रो. हसन कहती हैं, 'फिर भी भाकियू तब मोटे तौर पर पश्चिमी उप्र तक सीमित एक क्षेत्रीय ताकत ही थी। उसके विपरीत मौजूदा किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे देश के फलक पर फैला है और उसकी मांगें भी अधिक महत्वाकांक्षी हैं।

पुलिस सुधारों की अनदेखी

इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि अपने देश में चाहे कोई शिकायतकर्ता हो, गवाह हो या आरोपी, उसे पुलिस स्टेशन जाने में असहजता ही महसूस होती है। उसे वहां अपने साथ होने वाले संभावित सुलूक को लेकर संदेह रहता है। उसे रूखे व्यवहार, उत्पीड़न और अदालती चक्कर लगाने की आशंका सताती है। जो भी हो, तमाम लोगों को पुलिस से संपर्क साधना ही होता है और उसका पहला पड़ाव पुलिस स्टेशन ही बनता है। इसकी पड़ताल आवश्यक है कि आखिर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों करती है? इसके लिए हमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करना होगा।

एक जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सिविल पुलिस के 16.51 लाख स्वीकृत पद हैं, लेकिन असल में 13.03 लाख पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं। कायदे से प्रति एक लाख की आबादी पर 126.9 पुलिसकर्मी होने चाहिए, परंतु असल में 99.78 पुलिसकर्मी ही हैं। यानी **सौ लोगों पर एक पुलिसकर्मी** भी नहीं है। झारखंड में यह आंकड़ा 0.039, बिहार में 0.005, असम में 0.05, बंगाल में 0.06, ओडिशा में 0.07, तमिलनाडु में 0.08 और उत्तर प्रदेश में 0.08 है। इसके अलावा प्रति सौ वर्ग किमी के दायरे में भी पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं हैं। उदाहरण के लिए बिहार में प्रति सौ वर्ग किमी में 6.25 और ओडिशा में 17.26 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये उदाहरण बदहाल तस्वीर को दिखाने के लिए काफी हैं।

देश के कई पुलिस स्टेशनों में 20 से भी कम पुलिसकर्मी हैं। ओडिशा और बिहार के ग्रामीण इलाकों के पुलिस स्टेशनों में 12, उप्र में 15, हिमाचल में 16, आंध्र और त्रिपुरा में 18 पुलिसकर्मी ही हैं। इनमें से कुछ का काम तो महज कागजी कार्रवाई से ही जुड़ा है। 88 पुलिसकर्मियों के लिए औसतन एक वाहन की उपलब्धता से भी बहुत कुछ स्पष्ट होता है। देश में कुल 16,587 पुलिस स्टेशन हैं, जहां 14,784 वाहन हैं। करीब 85 पुलिस स्टेशनों में तो एक अदद वाहन तक नहीं है। 539 पुलिस स्टेशनों में एक फोन तक नहीं और 200 पुलिस स्टेशनों के पास वायरलेस सुविधा का अभाव है। करीब 1,474 पुलिस स्टेशन किराए की इमारत से संचालित हो रहे हैं। पुलिस के पास जो इमारतें हैं भी, वे बहुत जर्जर हालत में हैं। वहां पेयजल और खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मियों को जो आवास मिले हैं, उनकी हालत भी बेहद खस्ता है।

देश के दो तिहाई (10,021) पुलिस स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग की स्थिति अत्यंत लचर है। पुलिस के पास संसाधनों से लेकर मानव संसाधन का अभाव है। इन इलाकों में गरीबों, वंचितों और खासतौर से महिलाओं की शिकायतों पर बमुश्किल ही सुनवाई होती है। यदि पुलिस खुद तमाम मुश्किलों से जूझ रही है तो इस आधार पर उसका खराब व्यवहार जायज नहीं ठहरता। लोग यही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस उनके लिए नायक की भूमिका निभाए, परंतु उसके पास संसाधनों की किल्लत को देखते यह संभव नहीं दिखता। पुलिसकर्मियों को बेहद मुश्किल भूमिका निभानी पड़ती है और उनमें से तमाम को बिना किसी अवकाश के लगातार 18 घंटों की ड्यूटी करनी पड़ती है। वे अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन्हें तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याएं आ घेरती हैं। इससे उनका व्यवहार प्रभावित होता है, खासतौर से जब उन्हें कानूनी शक्ति मिली होती है तो वे अहंकारी और अक्खड़ हो जाते हैं।

कानूनी प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हैं

न्यायपालिका का कामकाज भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। निर्भया के दोषियों और कसाब जैसे मामले को परिणति तक पहुंचाने में अदालतों को करीब 8 साल लग गए। कानूनी प्रक्रियाएं भी दोषपूर्ण हैं। महज कानूनों में बदलाव और उनकी संख्या बढ़ाने से भी भला नहीं होने वाला। समूचा आपराधिक न्याय तंत्र छिन्न-भिन्न है। ऐसे में यदि पुलिस अप्रिय व्यवहार करती है तो उस पर हैरानी क्यों? हालात सुधारने में किसी की दिलचस्पी नहीं। इस स्थिति में समाज को लगातार प्रताड़ना ही झेलनी होगी। जब भी पुलिस की गलती होती है तो हमेशा की तरह उसकी आलोचना होती है। मुख्यमंत्री भी मीडिया में खीझ उतार देते हैं। फिर अगले किसी हादसे तक सब कुछ भुला दिया जाता है। जनता का आक्रोश भी कुछ समय के लिए ही रहता है। कोई भी उन पुलिस सुधारों की बात नहीं करता, जो सबसे आवश्यक हैं।

पुलिसकर्मियों की गुणवत्ता भी एक अहम मसला है। बीते कई वर्षों से भर्तियों में भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला बढ़ा है। यह नेताओं द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे में भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की कल्पना आसानी से की जा सकती है। उनका प्रशिक्षण भी बहुत दोयम दर्जे का होता है, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रायः अच्छे प्रशिक्षक या अनुभवी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं होती। तमाम पुलिस स्टेशनों में फोरेंसिक सुविधा भी नहीं है। असम, मप्र और ओडिशा जैसे कई राज्यों में मात्र एक ही फोरेंसिक लैब है। इस प्रकार क्षेत्रीय लैब में जांच अटकने से आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाता। आखिर पुराने हथियारों और बिना कंप्यूटर के कैसे हालात सुधर सकते हैं? आजकल साइबर अपराधियों के पास इतने आधुनिक संसाधन हैं कि पुलिस हमेशा पीछे रह जाती है। साइबर पुलिस में ही 5 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है।

पुलिस संस्कृति भी एक अहम पहलू है। अंग्रेजी राज वाली पुलिस की शासक प्रवृत्ति आज भी वही है। अभी तक 1861 के पुलिस अधिनियम को बदला नहीं गया है। पुलिस की जवाबदेही सरकारों के प्रति है, न कि कानून के प्रति। इस कारण अधिकांश राज्यों में पुलिस मुख्यमंत्रियों की निजी सेनाओं में तब्दील हो गई है। इस गिरावट में कई दशक लगे हैं। कोई नेता पुलिस सुधार नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस पर पकड़ से उसके हितों की पूर्ति होती है। पुलिसकर्मी भी नेताओं से हाथ मिला लेते हैं। वहीं तमाम अपराधी ही नेता बन जाते हैं। पुलिस सुधारों के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशें और 2006 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश धूल ही फांक रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए नौकरशाही और पुलिस नेतृत्व भी जिम्मेदार है।

● राजेश बोरकर

कांग्रेस की मजबूरी है गांधी परिवार

> अगले आम चुनाव में अभी तीन साल हैं। कांग्रेस चाहे तो उसके पास एक नए नेतृत्व में खुद को तैयार करने और दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन बनाने के लिए यह समय काफी है। अपनी पार्टी और अपने देश का हित देखते हुए गांधी परिवार को अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को ही अलविदा कह देना चाहिए। अगर वे पार्टी में बने रहे तो एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र बना रहेगा जो सिर्फ साजिशों और असंतोष के लिए ईंधन देने का काम करेगा।

कांग्रेस इन दिनों दुविधा में फंसी हुई है। क्योंकि न राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वापस आने को फिलहाल तैयार हैं और न ही 'भारत यात्रा' जैसी जनसंवाद की कोई विस्तृत योजना कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित है। मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक ही नहीं, अन्य मोर्चों पर भी पस्त नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए बड़ा अवसर है। लेकिन जैसी तैयारी और घेरेबंदी की जरूरत है, वह कांग्रेस नेतृत्व में नजर नहीं आती। राहुल और प्रियंका गांधी की ओर से रोजाना विभिन्न मसलों पर ट्वीट किए जाते हैं, पर उनकी आलोचना किसी आक्रोश की संगठित शक्ति बन जाए, ऐसी कोशिश नहीं दिख रही।

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी स्थिति से बेचैन हैं। 23 वरिष्ठ नेताओं के एक समूह की ओर से पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी। बिहार में सरकार बनाने से विपक्षी महागठबंधन के चूक जाने के बाद इस समूह की ओर से फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे नेता खुलकर नेतृत्व की कमजोरी पर सवाल उठा रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हर स्तर पर नेतृत्व चुनने को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उस पर इस समूह के लोग भी पूरी तरह खरे नहीं उतरते। सिब्बल जैसे नेता सरकार रहने पर केंद्रीय मंत्री और न रहने पर सुप्रीम कोर्ट की वकालत के तय ढर्रे पर जिंदगी जीते हैं। संगठन खड़ा करने या उसमें योगदान देने की उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती। लेकिन क्या ऐसी कोई योजना है भी जिसके तहत ऐसे नेताओं के सामने स्पष्ट कार्यभार पेश किया जाए?

सोनिया गांधी ने आर्थिक, विदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की समितियां जरूर बनाई हैं, लेकिन उनसे यह कमी पूरी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें शक नहीं कि राहुल गांधी जैसा नेता मध्यमार्गी राजनीति में फिलहाल दूसरा नहीं है। कोरोना महामारी से लेकर अर्थव्यवस्था तक को लेकर राहुल गांधी लगातार जो आशंकाएं जता रहे थे, वे सब सही साबित हुई हैं। लेकिन वे दार्शनिक ज्यादा और राजनेता कम नजर आ रहे हैं। उन्होंने 'फासीवाद' से लेकर 'मनुवाद' तक को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के शीर्ष से एक नई भाषा की गूंज दी है, लेकिन संगठन और जनाधार में इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है।

किसी भी संगठन में कार्यकर्ताओं के जूझने की दो वजहें होती हैं। एक तो विचारधारा, दूसरी स्वार्थ। केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का निजी स्वार्थ पूरा करने का ज्यादा सामर्थ्य नहीं बचा है और जो कार्यकर्ता विचारधारा की वजह से हैं, उनके सामने भी स्थिति अमूर्त है। जिस नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति को कभी कांग्रेस ने शुरू किया था, मौजूदा सरकार उसे ही बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा रही है। कांग्रेस की ओर से 'क्रोनी कैपिटलिज्म' को बढ़ावा देने की चाहे जितनी आलोचना की जाए, मूल नीतियों की न

कांग्रेस को दुविधा से बाहर आना ही होगा

70 के दशक में एक फिल्म आई थी, हीर-रांझा। इस फिल्म के एक गाने की शुरुआती लाइनें कुछ यूं थीं, 'मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है?' इस गाने की ये लाइनें जेहन में अचानक इसलिए आईं कि कांग्रेस मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रही है। उसे मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन वह मुसलमानों से दूरी भी दिखाना चाहती है। दरअसल 2014 के चुनाव में पार्टी की जबरदस्त हार के बाद सीनियर लीडर एके एंटनी की अगुवाई वाली इंटरनल कमेटी ने पाया था कि मुसलमानों के तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस की हार की मुख्य वजह है। उसके बाद पार्टी ने 'सॉफ्ट हिंदुत्व' के रास्ते पर चलने का फैसला किया, लेकिन करीब छह साल के दरम्यान यह कोशिश करते रहने के बावजूद उसे न तो खुदा ही मिला और न विसाल-ए-सनम। हां, उसे हर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए किसी एक अदद चेहरे की तलाश जरूर हुई।

'सॉफ्ट हिंदुत्व' पर कामयाबी क्यों नहीं

सवाल उठता है कि कांग्रेस ने भाजपा के 'हिंदुत्ववादी एजेंडे' से पार पाने के लिए 'सॉफ्ट हिंदुत्व' वाले रास्ते पर चलने का जो फैसला किया, उसमें उसे कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? इस सवाल का जवाब पाने के लिए 2017 के गुजरात चुनाव को रीकॉल करना होगा। दरअसल यह वह चुनाव था, जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल एक नए अवतार में देखे गए थे। उनका पूरा चुनावी अभियान इस तरह से शेड्यूल किया गया था कि 'मंदिर दर्शन' जरूर हो। राहुल ने चुनाव अभियान के दौरान गुजरात के 27 मंदिरों में हाजिरी लगाई थी। पार्टी की तरफ से यहां तक दावा कर डाला गया था कि राहुल सिर्फ एक हिंदू ही नहीं हैं, बल्कि वे जनेऊधारी भी हैं। इन सबके बावजूद कांग्रेस गुजरात नहीं जीत सकी। भले ही नजदीकी मुकाबला रहा हो, लेकिन भाजपा एक बार फिर से गुजरात जीतने में कामयाब रही थी। वजह यह थी कि कांग्रेस ने खुद चुनाव को 'हिंदुत्व' की पिच पर ला खड़ा किया और उस 'पिच' पर भाजपा को हराना बहुत आसान नहीं है। वह तो उस 'पिच' पर खेलने की इतनी अभ्यस्त है कि कांटे के मुकाबले में भी जीत हासिल कर सकती है। या यूं समझिए कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद है तो भी हम बड़े 'ब्रैंड' का प्रोडक्ट लेने को तरजीह देते हैं। कांग्रेस को समझना होगा कि दो नावों पर सवारी करके किसी दरिया को पार नहीं किया जा सकता है। उसमें डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। आधे-अधूरे मन से कोई बात नहीं बनने वाली।

तो कोई समीक्षा की गई है और न उन्हें उलटने का कोई प्रस्ताव ही है। यह सच है कि उसने संगठन में दलित और पिछड़ी जातियों को हाल के दिनों में ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन डॉ. अंबेडकर के 'जाति उच्छेद' के कार्यक्रम को अपनाने या निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसी मांग करने का साहस उसके पास नहीं है।

ऐसे में सत्ता में दलित-पिछड़ी जातियों को सांकेतिक भागीदारी देकर अपने विस्तृत 'हिंदुत्व प्रोजेक्ट' को पूरा करने में जुटी भाजपा के सामने वह कोई गंभीर चुनौती पेश करे भी तो कैसे? गांधी परिवार की सीमा बताने वालों की कमी नहीं लेकिन यह भी सच है कि यह परिवार ही कांग्रेस की शक्ति भी है। जो भी नेता नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनमें किसी के पास अपना कोई राष्ट्रव्यापी आधार नहीं है। सच्चाई यह भी है कि राजीव गांधी की शहादत के बाद इस परिवार ने राजनीति से दूरी बना ली थी। कांग्रेस के पास पूरा अवसर था कि वह बिना गांधी परिवार के खड़ी हो जाए, लेकिन पार्टी पूरी तरह असफल रही। जाहिर है, कांग्रेस के लिए गांधी परिवार बोझ नहीं, मजबूरी है।

कांग्रेस में अकेला गांधी परिवार है जिस पर कार्यकर्ता शर्त लगा सकते हैं कि वह महात्मा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा के सामने समर्पण नहीं करेगा। तमाम कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस अब भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो मानते हैं कि राहुल गांधी इतिहास की पुकार हैं। लेकिन क्या किसी नए आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम और जमीनी गतिशीलता के बगैर इस पुकार को एक ठोस जनाधार में बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेतृत्व को भी ढूंढना होगा। खासतौर पर तब, जब वह मानता है कि संघ और भाजपा के हमले से 'भारत' नाम का विचार खतरे में है।

जिस तरह बिहार के चुनाव में हार के लिए पार्टी हद दर्जे तक असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार मान रही हैं, ऐसे ही करीब पांच साल पहले असम विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए एआईडीयूएफ के मौलाना बदरूद्दीन अजमल को जिम्मेदार माना गया था। कहा गया था कि अगर उनकी पार्टी ने मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं किया होता तो पूर्वोत्तर के किसी राज्य में जिस तरह भाजपा की पहली बार एंट्री हो रही है, वह नहीं होती। इस तर्क को सही साबित करने के लिए आंकड़ों का सहारा लिया गया, बताने की कोशिश हुई कि एआईडीयूएफ ने किस हद तक वोटों का बंटवारा किया। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिन मौलाना अजमल को पार्टी हार के लिए जिम्मेदार मान रही थी, वे जब कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश में थे तो पार्टी उनके साथ कोई रिश्ता रखने को राजी नहीं हो रही थी। असम में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने मौलाना अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ इस बात पर चुनावी गठबंधन करने से इंकार कर दिया था कि मौलाना की छवि मुस्लिम परस्त नेता की है, उनके साथ गठबंधन करने पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की गुंजाइश ज्यादा होगी और वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है।

मौलाना अजमल से दूरी बनाने के बावजूद असम में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा अपने गठबंधन के साथ सत्ता में आ गई और कांग्रेस पार्टी, जो राज्य की 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वह महज 26 सीटों पर जा सिमटी। उधर एआईयूडीएफ 74 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा। चुनाव के नतीजे आने के बाद मौलाना अजमल का बयान आया था, 'राज्य में भाजपा को रोकने के लिए हम गठबंधन करना चाह रहे थे, कांग्रेस राजी नहीं हुई तो राज्य में हम कांग्रेस को जिताने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं।' ऐसा ही कुछ बिहार में भी हुआ। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राज्य में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन यहां भी उससे दूरी बनाने का ही फैसला हुआ। वजह वही थी कि ओवैसी का साथ नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ जाएगा।

मुस्लिम परस्त छवि से बचने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवार बनाने में भी कंजूसी दिखाई, उसके हिस्से जो 70 सीटें आईं, उनमें महज 12 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। ओवैसी ने बिहार चुनाव के दरम्यान कई मौकों पर यह कहा भी कि कांग्रेस और अपने को सेक्युलर कहने वाले दूसरे दलों को मुसलमानों के वोट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी दाढ़ी और टोपी उन्हें पसंद नहीं। उन्हें मुसलमानों से ध्रुवीकरण का खतरा तो दिखता है, लेकिन वे फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर ही लड़ना चाहती हैं। इससे पहले 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भी हार का ठीकरा ओवैसी पर ही फोड़ा गया, लेकिन वहां भी ओवैसी कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई।

● इन्द्र कुमार

सांसद निधि पर कोरोना की काली छाया पड़ गई है। संक्रमणकाल के दौर में केंद्र सरकार ने देशभर के सांसदों को संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली सांसद निधि पर इस बार रोक लगा दी है। बीते तीन वर्षों तक सांसदों को निधि जारी नहीं की जाएगी। इसके चलते सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के मनमुताबिक विकास कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। जाहिर है इसके चलते सांसदों को मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

सांसद निधि पर नकेल जरूरी

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सांसद क्षेत्र विकास निधि के तहत होने वाले कार्यों को दो साल के लिए बंद कर दिया है, परंतु आने वाले समय में उसको इस मामले में कोई दो टूक निर्णय करना पड़ेगा। यानी इसे दोबारा शुरू किया जाए या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कई विवेकशील सांसदों, नेताओं तथा संस्थानों ने इसे हमेशा के लिए बंद करने के पक्ष में समय-समय पर अपनी राय दी है। याद रहे कि इस निधि के उपयोग में गड़बड़ियां लाख कोशिशों के बावजूद दूर नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण राजनीति, राजनेता और सरकारी अधिकारियों की साख दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका दुष्परिणाम सरकार के अन्य कामों पर भी पड़ रहा है। अपवादों को छोड़कर इससे अनाप-शनाप दामों पर चीजें खरीदी जा रही हैं। हालांकि इसके व्यय को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश मौजूद हैं, पर जरूरत इसे कानूनी रूपरेखा प्रदान कराने की है।

अदालतें, कैग, केंद्रीय सूचना आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग समय-समय पर सांसद निधि के दुरुपयोग के खिलाफ टिप्पणियां कर चुके हैं। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो 2007 में ही इसकी समाप्ति की सिफारिश कर दी थी। तब उसने कहा था कि सुशासन के लिए यह जरूरी है कि सांसद निधि को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। हालांकि इसके बावजूद लोक लेखा समिति के तत्कालीन प्रमुख और कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने कहा था कि कई दलों के तमाम सांसद यह चाहते हैं कि सांसद निधि की सालाना राशि को पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया जाए। शुक्र है कि ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं होने दिया, किंतु इस निधि को समाप्त करने की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। हां, इस बीच इसके भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति जरूर बना दी गई है। वैसे राजनीतिक हलकों में आम धारणा यह है कि अधिकांश सांसद इसे समाप्त करने के सख्त खिलाफ हैं। जो सांसदगण इस निधि को लेकर अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय या फिर किन्हीं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को एकमुश्त राशि दे देते हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: इस निधि को लेकर कोई कड़ा कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि वह इसके दुरुपयोग या फिर कम उपयोग की खबरों से अनभिज्ञ नहीं हैं। साथ ही वे राजनीति और प्रशासन में शुचिता लाने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील भी हैं।

अब जरा इस निधि के इस्तेमाल को लेकर आए दिन मिल रही शिकायतों के बारे में विचार करें। इस निधि को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोडल एजेंसी बना रखी है। इसका काम राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय बनाए रखना है। जांच से पता चला है कि आमतौर पर कोई समन्वय नहीं हो पाता। अपवादों की बात और है। सांसद निधि के खर्चे की जब कैग ने जांच की तो उसे 90 प्रतिशत योजनाओं के कार्यों में अनियमितता नजर आई। तत्कालीन योजना आयोग ने 2001 में ही कह दिया था कि इस निधि के खर्चे की निगरानी का काम बहुत कमजोर है। लोक लेखा समिति ने 2012 में कहा कि जितनी निधि उपलब्ध रहती है, उसकी आधी ही खर्च हो पाती है। खर्चे का हिसाब एवं प्रगति रिपोर्ट भी समय पर उपलब्ध नहीं होती। इनमें पारदर्शिता का अभाव है। याद रहे कि सांसद निधि में कमीशन लेने के कारण एक राज्यसभा सदस्य की सदस्यता तक जा चुकी है। इसके अलावा विधायक निधि मंजूर करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में बिहार के एक विधायक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

प्रशासन के लिए चिंता का विषय

सांसद-विधायक निधि को लेकर जो आम चर्चाएं होती रहती हैं, वे स्वच्छ प्रशासन के लिए बहुत चिंता पैदा करती हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस निधि में भ्रष्टाचार की आम चर्चा होती है, उसे रोकने के लिए जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से आवाज क्यों नहीं उठाते? विडंबना यह है कि कुछ बड़े नेता जब विपक्ष में रहते हैं तब तो वे इस निधि के खिलाफ खूब बोलते हैं, किंतु सत्ता में आने पर उनका रुख ही अलग हो जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सांसद निधि की शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। उन्होंने इसकी सालाना राशि एक करोड़ रुपए रखी थी। यह जब हो रहा था, तब राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह विदेश दौरे पर थे। बाद में उन्होंने कहा कि 'यदि मैं तब देश में होता तो इस सांसद क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत ही नहीं होने देता।' याद रहे कि सांसद निधि से मिले चंदे का इस्तेमाल अनेक सांसदगण सियासी खर्चे पर करते हैं। कुछ अन्य सांसद उसका उपयोग कुछ और काम में भी करते हैं। मनमोहन सिंह ने उस समय तो सांसद निधि का विरोध किया, किंतु जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसकी राशि दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दी।

सांसद निधि पर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए

बहरहाल असल फैसला नरेंद्र मोदी को तब करना होगा जब निधि स्थगन की दो साल की अवधि पूरी हो जाएगी। हालांकि एक बात तो तय है कि सांसद निधि की राशि नहीं बढ़ेगी, परंतु शासन में शुचिता लाने के लिए इसको पूरी तरह समाप्त करने का काम होगा या नहीं? तब तक यह यक्ष प्रश्न कायम रहेगा। वैसे देश के तमाम विवेकशील लोगों की यह राय है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की पर्याय बनी सांसद निधि पर जरूर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इससे शासन में शुचिता लाने के मोदी के प्रयास को भारी बल मिल जाएगा। साथ ही सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी। कोरोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सांसद आदर्श ग्राम पर भी ग्रहण लगा दिया है। सांसद निधि की राशि से सांसदों द्वारा आदर्श ग्राम का विकास किया जाता है। विकास कार्य के दौरान बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सांसद आदर्श ग्राम के चयन के बाद सांसद कार्यालय से जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी जाती है। केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आदर्श ग्राम में फंड स्वीकृत किए जाते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सांसदों को संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए प्रतिवर्ष सांसद निधि के तौर पर पांच करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस बार सांसद निधि को पीएम केयर्स फंड में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 की पूरी निधि पीएम केयर्स फंड में जमा होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का एक असर यह भी हुआ कि वर्ष 2018 के लिए केंद्र सरकार ने सांसद निधि की पहली किश्त ढाई करोड़ रुपए की जारी कर दी थी। दूसरी किश्त अब तक जारी हो जानी थी। दूसरी किस्त जारी होने की प्रत्याशा में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले लोकसभा क्षेत्र के सांसदों ने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जिला योजना मंडल में प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रस्ताव के साथ ही सांसदों ने अपनी टीप में आवश्यक कार्यों को कराने के लिए तकनीकी जांच पड़ताल के बाद स्वीकृत करने की छूट भी जिला योजना मंडल को दे दी है। अब तक दूसरी किश्त की राशि भी नहीं आ पाई है। जानकारी के अनुसार दूसरी किश्त ढाई करोड़ में से एक करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड में जमा करा दी है। लिहाजा अब सांसद निधि के रूप में एक करोड़ रुपए ही सांसदों के खाते में जमा कराई जाएगी। एक करोड़ रुपए खाते में जमा कराने को लेकर भी संशय बना हुआ है।

साल 1993 से ये योजना लगातार चल रही थी। लेकिन फिर आया 2020। और अपने साथ लाया कोरोना का वायरस। इससे लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया गया। सारी गतिविधियां ठप हो गईं और फिर तय किया गया कि देश के सांसदों को मिलने वाली सालाना पांच करोड़ की रकम अब अगले दो साल तक नहीं दी जाएगी। देश में सांसदों की कुल संख्या है 790। इसमें 545 लोकसभा सदस्य हैं और 245 राज्यसभा के सदस्य। पांच करोड़ रुपए साल के लिहाज से इन सांसदों की दो साल की निधि हो रही है 7900 करोड़ रुपए। इसी का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में किया जाएगा। इसे देखते हुए उप्र सरकार ने भी विधायकों को मिलने वाले फंड को एक साल के लिए रोक दिया और इससे बचने वाले 1209 करोड़ रुपए को कोरोना से लड़ने वाले फंड में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन पहले बात करते हैं सांसद निधि की। सांसद निधि लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद दोनों की ही होती है। राज्यसभा के सांसद में राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त सांसद भी हैं, जिन्हें सांसद निधि मिलती है। इनके पास ये अधिकार होता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में हर साल ये पांच करोड़ रुपए तक के विकास के काम कर सकते हैं। राज्यों के विधायकों के साथ भी यही होता है। हालांकि हर राज्य के विधायक की निधि अलग-अलग होती है। दिल्ली जैसे राज्य में एक विधायक हर साल 10 करोड़ रुपए तक के विकास का काम करवा सकता है। पंजाब और केरल के विधायक हर साल पांच करोड़ रुपए तक के विकास का काम करवा सकते हैं। उप्र के विधायक पहले दो करोड़ रुपए तक का काम हर साल करवा सकते थे, लेकिन अब उनका फंड बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए कर दिया गया है। असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधायक दो करोड़ रुपए तक के विकास के काम हर साल अपने क्षेत्र में करवा सकते हैं।

लेकिन क्या सरकार की ओर से ये पैसे सीधे सांसदों या विधायकों के खाते में जमा कर दिए जाते हैं? जवाब है नहीं। ये पैसे आते हैं स्थानीय प्रशासन के पास। अब सांसद या विधायक स्थानीय प्रशासन जैसे डीएम को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में विकास काम की जानकारी देता है। फिर डीएम उस काम के लिए एजेंसी का चुनाव करता है। एजेंसी काम करती है और फिर डीएम की ओर से उसे पैसे मिल जाते हैं। सांसद के लिए विकास कार्य का मतलब है कि वो अपने इलाके में सड़कें बनवाए, स्कूल की बिल्डिंग बनवाए। इसमें भी एक क्लॉज होता है कि सांसद को अपनी साल की कुल निधि की 15 फीसदी रकम अनुसूचित जाति के विकास के काम पर खर्च करनी होगी और 7.5 फीसदी रकम अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च करनी होगी। यानि कि पांच करोड़ में से 75 लाख रुपए अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च होंगे और 37.5 लाख रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे। हालांकि कोरोना के आने के बाद इस साल के लिए जो सांसद निधि मिली है, उसे सांसद अपने इलाके लिए पीपीई किट और कोरोना टेस्टिंग किट खरीदने पर भी खर्च कर सकते हैं।

अब इस फंड को अगले दो साल तक के लिए रोक दिया गया है। सीधा मतलब है कि अब कोई सांसद अपनी निधि से अपने इलाके में स्कूल की बिल्डिंग, सड़कें, पीने का पानी, शौचालय या फिर विकास का कोई भी छोटा-मोटा काम नहीं करवा सकता है। उसकी जनता भी उससे एक बार भी नहीं पूछ पाएगी कि आपने इलाके के विकास के लिए क्या किया है, क्योंकि जनता को भी पता है कि सांसद के पास फंड नहीं है। सांसद भी अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो ये कहकर बच जाएंगे कि उनका फंड तो केंद्र सरकार ने रोक लिया है। और ये फंड है मात्र 7900 करोड़ रुपए।

● दिल्ली से रेणु आगाल

आज भी बीमारू राज्य

दो दशक बाद भी मकसद अधूरे

2000 में जब तीन नए अपेक्षाकृत छोटे राज्यों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, तब कहा गया था कि ये राज्य न सिर्फ लोगों की भावनाओं और पहचान को तुष्ट करेंगे, बल्कि विशाल राज्यों उप्र, बिहार और मप्र से टूटकर बने ये छोटी प्रशासनिक इकाइयां विकास के पैमाने पर खरी उतरेंगी और स्थानीय आबादी को अपने राज्य में ही संबल मिलेगा। लेकिन, क्या दो दशक बाद वे वादे, वे मकसद कहीं पूरे हुए? क्या इन तीनों राज्यों से रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना थमा? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-यापन की स्थितियां सुधरीं? हालात तो विपरीत छवि पेश करते हैं, जैसा कि इन राज्यों की रिपोर्ट में हम देख सकेंगे। कोरोना महामारी के दौर में भी सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियां थीं। अलबत्ता तीनों राज्यों में राजनीति के लिहाज से जरूर लगातार सरगर्मियां बनी रही हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन तीनों में अलग राज्य के लिए आंदोलन पर कांग्रेसी सरकारें आंखें मूंदे रहीं लेकिन तत्कालीन एनडीए सरकार को अपना जनाधार बनाने का इसमें अच्छा मौका सूझा। तब के उसके रणनीतिकार उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसकी बाकायदा रूपरेखा रखी और छोटे राज्यों की अवधारणा पर जोर दिया।

नवंबर 2000 में मप्र से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। नया राज्य बनाने के पीछे तर्क दिया गया था कि वहां प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, लेकिन उसका फायदा स्थानीय निवासियों को नहीं मिल रहा है। सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से भी अलग होने की वजह से वहां विकास नहीं हो पा रहा है। यह बात सही थी कि बिजली, खनिज और वन संपदा के लिहाज से वह क्षेत्र जितना समृद्ध था, वहां के स्थानीय निवासी उतने ही गरीब थे। यह माना गया कि नए राज्य में संसाधनों का फायदा स्थानीय निवासियों को मिलेगा और उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव आएंगे।

छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं, अलग राज्य सरीखे भावनात्मक मुद्दे का विरोध करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अलग राज्य बनाना उस समय की न केवल राजनीतिक आवश्यकता थी, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए भी यह जरूरी था। अंग्रेजों के समय भी छत्तीसगढ़ अलग कमिश्नरी हुआ करती थी, जिसे 1956 में मप्र के साथ मिला दिया गया। कागजों पर तर्क देकर राज्य तो बना दिया गया, लेकिन 20 साल बाद भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मानव विकास सूचकांकों में आज भी छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में वहीं हैं जहां अलग होने से पहले हुआ करता था। यहां स्थिति निरंतर राष्ट्रीय औसत से खराब बनी हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार देश के 30 फीसदी घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाया जाता था, जबकि छत्तीसगढ़ में 19.6 फीसदी था। आज भी इसकी एक-तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के मामले में भी स्थिति राष्ट्रीय औसत से खराब है। उपरोक्त सर्वे के अनुसार 2015-16 में शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 41 प्रति 1000 था, जबकि छत्तीसगढ़ में 54 था। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव हुआ है। आर्थिक विषमता के विरोध में शुरू हुई नक्सली समस्या आज भी बनी हुई है।

केवल राज्य की विकास दर के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। छत्तीसगढ़ की औसत विकास दर सात फीसदी रही है। 2010-11 में जब भारत की विकास दर 8.9 फीसदी थी, तब छत्तीसगढ़ की 10.6 फीसदी पहुंच गई थी। हालांकि दोनों ही राज्यों में विकास दर, प्रति व्यक्ति आय और कुल राजस्व में बढ़ोतरी लगभग समान है। सामाजिक विकास पर कई अध्ययन कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता गुरुचरण सचदेव कहते हैं कि छोटे राज्य बनने से छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं मिल पाया है। आज भी वहां भयावह आर्थिक विषमता है। मानव विकास सूचकांकों के मामले में यह निचले पायदान पर है। बड़ी आबादी ऐसी है जिसे भरपेट पौष्टिक भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। आज भी नवजात बच्चे बड़ी संख्या में दम तोड़ रहे हैं। सचदेव कहते हैं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सामाजिक विकास से संबंधित ज्यादातर विभाग आवंटित राशि का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद सामाजिक सूचकांकों में सुधार की गति तेज नहीं हो पाई है।

आदिवासी कलाओं पर लंबे समय से काम कर रहीं डॉ. मीनाक्षी पाठक कहती हैं, हर भूगोल की अपनी कुछ खासियत होती है। बड़े राज्यों में इनको लेकर विशेष नीति नहीं बनती, इसलिए छत्तीसगढ़ का बनना सही फैसला था। वहां के लोगों की सभ्यता और संस्कृति को सहेजने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहां की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की रूपरेखा तय नहीं की गई। यह वहां के राजनीतिक नेतृत्व की विफलता है।

गठन के 20 साल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम बिजली, सड़क और कृषि क्षेत्र में हुआ है। कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। बिजली उत्पादन और आधारभूत संरचना के निर्माण पर भी काफी खर्च हुआ है। लेकिन आर्थिक विषमता की खाई बढ़ती जा रही है। यहां अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी जनसंख्या है। उनके और उनके क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं, अलग बजट आवंटित होता है, लेकिन जमीन पर 20 साल बाद भी बड़ा बदलाव नहीं दिखता है।

विशेषज्ञ इसके लिए नेताओं को कसूरवार मानते हैं। उनका मानना है कि अलग राज्य बनाने के पीछे की मूल भावना को समझकर विकास की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जो नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं कि 20 साल पहले जो भी राज्य बने वे सब कई मायनों में मूल राज्य के दूसरे हिस्से से अलग थे। वहां के संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास का नया ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिए था।

● रायपुर से टीपी सिंह

गहलोत बन सकते हैं दूसरे अहमद पटेल

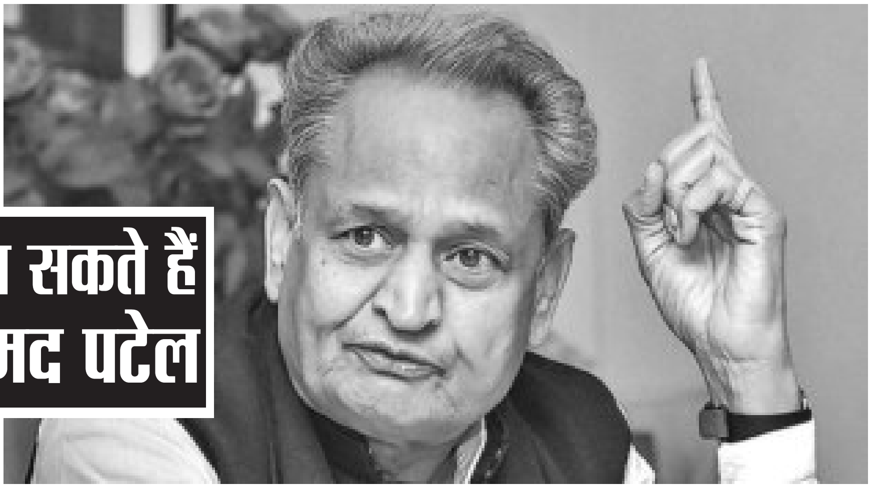

कांग्रेस के लिए अब सबसे कठिन सवाल यह है कि अगला अहमद पटेल कौन बनेगा? क्या अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से तपे-तपाए नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर के मुख्य रणनीतिकार बन सकते हैं? या गांधी परिवार के लिए एक ही विकल्प रह गया है कि वह एक नया अहमद पटेल तैयार करे? पटेल और तरुण गोगोई की मृत्यु ऐसे समय पर हुई है जिससे बुरा समय कांग्रेस के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता था। पार्टी के सामने एक अभूतपूर्व समस्या खड़ी हो गई है। इन दोनों नेताओं की कमी आसानी से कोई नहीं पूरी कर सकता है। वे दोनों अपनी-अपनी तरह से पार्टी के लिए अपरिहार्य थे।

आज जबकि कांग्रेस अपना वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटी है, उसमें आमूलचूल बदलाव की जरूरत है; चुनावों में खुद को साबित करना, नए दोस्त बनाना और पुरानों को साथ बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में पटेल की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण होती। अब पटेल की कमी की भरपाई कौन करेगा? क्या पार्टी में ऐसा कोई वरिष्ठ कोई नेता है, जो सियासत की समझ रखता हो, सभी दलों में जिसके प्रति सम्मान का भाव हो, और जिस पर राहुल गांधी को भरोसा हो? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कसौटियों पर काफी हद तक खरे उतरते हैं।

जहां तक तरुण गोगोई की बात है, असम में कांग्रेस के वे एकमात्र असली नेता थे, जो विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले गुजर गए। अब कांग्रेस वहां अपना सफाया नहीं होने दे सकती। उसके लिए संकट एक जैसा है- निकट भविष्य में किसी विकल्प का न होना। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अहमद पटेल के बिना कांग्रेस वही नहीं रह जाएगी, जो वह पहले थी। गुजरात के भड़ूच के इस नेता के अनूठे कौशल, भारतीय राजनीति पर उनकी पकड़, अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए उनकी अपरिहार्यता के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि पटेल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार और आलाकमान के चतुर सलाहकार की जो भूमिका निभाते थे वह अब कौन निभाएगा? वास्तव में भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को अगर कोई तगड़ी चुनौती दे सकता था तो वे पटेल ही थे।

कांग्रेस के लिए विडंबना यह है कि पटेल की जगह लेने वाला उनकी टक्कर का शायद ही कोई नाम उसके सामने उभर रहा है। लेकिन सारे अहम विकल्पों पर नजर डालने के बाद, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ रखने वाले, इस कीचड़ में उतरने को तैयार, दोस्तों और दुश्मनों तक समान पहुंच रखने की क्षमता साबित कर चुके अनुभवी नेता अशोक गहलोत का नाम इस सवाल के जवाब के रूप में तुरंत सामने उभरता है। गहलोत ने राजस्थान में काम करके दिखाया है, वे संगठन के पक्के नेता हैं, राजनीति की क्या मांगें हो सकती हैं इसकी उन्हें गहरी समझ है, और वे गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं, पेचीदगियों से निपटने के मामले में वे जुगाड़ू हैं, सभी दलों के नेताओं का सम्मान उन्हें हासिल है, और सचिन पायलट प्रसंग ने साबित कर दिया है कि चाणक्य नीति के मामले में वे युवा नेताओं से कोसों आगे हैं।

गहलोत राहुल गांधी के भी चहेते हैं। अगर भविष्य में दोनों को मिलकर काम करना है तो इस लिहाज से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे अपने समकालीनों की तुलना में गहलोत इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं। दिग्विजय सिंह अस्थिर मिजाज के हैं और बयान देकर पलटने की आदत से ग्रस्त रहे हैं। कमलनाथ में मुश्किल स्थितियों से निपटने का कौशल तो है मगर मप्र में अपनी गद्दी न बचा पाने के कारण उनकी स्थिति काफी कमजोर पड़ चुकी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे मगर वे 80 की उम्र छू रहे हैं, और अब वे ज्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को राष्ट्रीय राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है। जयराम रमेश जैसे नेता पर्दे के पीछे सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं मगर चुनावी राजनीति के दांवपेचों को इतना नहीं समझते कि संकटमोचन की भूमिका निभा सकें। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं मगर वे नियमों के हिसाब से चलने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वे ठेठ सियासतदां वाली भूमिका में नहीं आ सकते। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ नेताओं में वह राजनीतिक कौशल और दमखम नहीं है। युवाओं में राहुल गांधी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीब हैं, जो पूर्व पार्टी अध्यक्ष के भरोसेमंद सहायक के रूप में उभरे हैं। लेकिन सुरजेवाला में अनुभव की कमी है, उनकी वह पहुंच या प्रवृत्ति नहीं है जिसके लिए पटेल मशहूर थे। 2017 में गुजरात के चुनाव से ठीक पहले सुरजेवाला ने जिस तरह राहुल को 'जनेऊधारी' ब्राह्मण घोषित किया था वह कांग्रेस पार्टी को वर्षों तक परेशान करता रहेगा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

तरुण गोगोई के बाद क्या?

अब राजस्थान से असम, उत्तर-पूर्व की ओर चलें। असम में तरुण गोगोई ही कांग्रेस के एकमात्र नेता बचे थे। बेहद कामयाब नेता और सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे गोगोई ने उत्तर-पूर्व के इस राज्य में पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाया। लेकिन असम को एकजुट रखने वाले ताकतवर नेता गोगोई को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में हमेशा कमतर करके आंका जाता रहा। सीधी बात यह है कि असम में कांग्रेस का असल में अब कोई नेता नहीं रहा। हिमंत बिसवा सरमा को भाजपा में जाने देना उसके लिए आत्मघाती हुआ। और अब गोगोई के निधन से जो शून्य पैदा हुआ है वह बहुत बड़ा और वास्तविक है। गौरव गोगोई को राज्य में पार्टी का नेतृत्व संभालने और अपने पिता की क्षमता की बराबरी करने में अभी लंबा समय लगेगा। उन्हें राज्य को ज्यादा समय देना पड़ेगा, पार्टी संगठन पर पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी और चुनावों में अपना कौशल दिखाना पड़ेगा। रिपुन बोरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक कोई खास संभावनाएं नहीं उजागर की हैं। न तो वे गोगोई जैसे लोकप्रिय हैं, और न पार्टी संगठन पर उनकी वैसी पकड़ है।

संगठित हो रही भाजपा

महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 2019 में हुए चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा के कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं को पूरा भरोसा था कि उनकी पार्टी 288 सदस्यीय सदन में 135-140 सीटें जीतने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे। नतीजों ने सारी उम्मीदें धराशायी कर दीं- भाजपा 105 विधायकों की जीत के साथ साधारण बहुमत के लिए जरूरी 144 सीटों के आंकड़े से काफी पीछे रह गई, और फिर सहयोगी शिवसेना के साथ बढ़ी तकरार ने आखिरकार शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता खोल दिया।

भाजपा नेताओं को उस समय तो यही लग रहा था ये गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हालांकि, पार्टी को अब विपक्ष में बैठे करीब एक साल हो गया है और इसके साथ ही एक युवा नेता की अगुवाई में 'विकास सर्वप्रथम' एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली एक अपराजेय पार्टी की उसकी छवि भी प्रभावित हो रही है। भाजपा अब धर्मनिरपेक्ष पार्टी वाली छवि को लेकर शिवसेना के खिलाफ माहौल बनाकर महाराष्ट्र के हिंदूवादी वोट बैंक को अपने पाले में लाकर फिर संगठित होने की उम्मीदें लगाए बैठी है।

राजनीतिक टिप्पणीकार प्रकाश बल कहते हैं, 'राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा किसी भी पार्टी को तोड़ने और सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए तो उसे किसी पार्टी को पूरी तरह ही अपने साथ लाना होगा।' महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 53 (एक विधायक की पिछले महीने मृत्यु होने से आंकड़ा 54 से घट गया) और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं।

बागी अजित पवार के साथ मिलकर बनाई गई फडणवीस की 80 घंटे की नाकाम सरकार का जिक्र करते हुए बल ने कहा, 'जो कुछ हुआ था उसके बाद एनसीपी तो भाजपा के साथ नहीं जाएगी, इसके अलावा न तो कांग्रेस उसके साथ जाएगी और न ही शिवसेना जाएगी। यह स्थिति भाजपा के लिए थोड़ी पेचीदा है और इसीलिए वह अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए राजभवन का इस्तेमाल करने और 'धर्मनिरपेक्ष छवि' को लेकर शिवसेना पर निशाना साधने की कोशिश में जुटी है।' एमवीए सरकार के गठन के बाद से ही महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के साथ उसके रिश्ते ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। कोश्यारी भाजपा के पूर्व पदाधिकारी और कट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक हैं।

शिवसेना के नेता अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए राजभवन का दुरुपयोग कर रही है। उदाहरण के तौर पर राज्यपाल राज्य विधान परिषद के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुने जाने संबंधी कैबिनेट की सिफारिश लटका रहे थे। नियमानुसार 2019 का चुनाव नहीं लड़ने वाले ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के छह महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी था। राज्यपाल उस समय भी मुख्यमंत्री के साथ टकराव की स्थिति में नजर आए जब भाजपा मार्च में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही बंद चल रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार, राज्य सरकार ने पिछले महीने पूजा स्थल खोलने का फैसला किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले एक साल के घटनाक्रम ने देवेंद्र फडणवीस की छवि को काफी हद तक प्रभावित किया है और ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनका पार्टी में वैसा नियंत्रण नहीं रह गया है जैसा मुख्यमंत्री रहने के दौरान था। राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई कहते हैं, 'उद्धव ठाकरे को परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री को यह बताना होगा कि वह महामारी के बीच प्रदर्शन के नाम पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से भीड़ जुटाने वाले भाजपा नेताओं पर लगाम कसें।' देसाई ने कहा, 'फडणवीस खुद तो गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। फिर ऐसे नेता भी हैं जो ऐसे बयान देते रहते हैं कि कैसे तीन महीने में, छह महीने में या फिर अब दिवाली के बाद एमवीए सरकार गिर जाएगी। इस सबके बीच फडणवीस कहते हैं कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, वह खुद-ब-खुद गिर जाएगी।' उन्होंने कहा, 'इससे पहले, जब वह मुख्यमंत्री थे, तब कोई भी बड़े विवादित बयान नहीं आते थे, लेकिन अब जब विपक्ष के नेता हैं तो ऐसा नहीं रहा।' एकनाथ खडसे और जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे ने भी फडणवीस के नेतृत्व को झटका दिया है। खडसे ने तो खुले तौर पर अपने इस्तीफे के लिए फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है जबकि पाटिल ने कहा था कि वह पार्टी के लिए काम करना चाहते थे लेकिन पार्टी उन्हें मौका नहीं दे रही थी।

देसाई ने कहा, 'विपक्ष में एक साल रहने के बाद भी हम अभी तक यह नहीं कह सकते कि भाजपा ने अपनी जमीन खो दी है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और नेता विपक्ष के व्यापक दौरों के जरिए पार्टी ने दिखा दिया है कि वह अब भी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन एक एकजुट और जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के तौर पर उसकी छवि पर प्रतिकूल असर जरूर पड़ रहा है।'

● बिन्दु माथुर

हिंदुत्व बनेगा हथियार

पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने दोहरे उद्देश्य के साथ हिंदुत्व के एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। एक तो यह कि शिवसेना को प्रतिक्रिया के लिए उकसाया जाए, जिससे कांग्रेस और एनसीपी के असहज होने और गठबंधन के बीच वैचारिक दरार बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन, इससे भी अहम बात यह है कि भाजपा की नजरें 2022 पर टिकी हैं। जब 'मिनी विधानसभा चुनाव' माने जाने वाले 10 नागरिक निकायों, जिनमें शिवसेना के गढ़ मुंबई और ठाणे शामिल हैं, और 27 जिलों में जिला परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। शिवसेना अब चूंकि पूर्व में अपनी वैचारिक विरोधी रही कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला चुकी है, भाजपा को उम्मीद है कि वह शिवसेना की हिंदुत्ववादी पार्टी वाली छवि खत्म कर देगी और 2022 के चुनावों में राज्य में भगवा वोट-बैंक पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी।

सबको भायी भाजपा की रणनीति

उ प्र विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल से अधिक समय शेष है लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दल भी अपने-अपने मुहरे फिट करने में जुटे हुए हैं। उप्र की वर्तमान राजनीति पर गहराई से गौर करें तो पता चलता है कि यहां विपक्ष की करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियां भाजपा की चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। यही रणनीति भाजपा ने पिछले उप्र विस चुनावों में अपनाई थी जो काफी सफल रही थी। अब इसी रणनीति पर करीब-करीब सभी बड़े राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर इसी रणनीति को साध रही है।

दरअसल, भाजपा ने पिछले चुनावों में बड़े राजनीतिक दल यथा सपा और बसपा से उलट वहां से स्थानीय और छोटे-छोटे राजनीतिक दलों से संपर्क साधा था। उप्र में दर्जनभर से अधिक छोटे राजनीतिक दल हैं। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा को 8 और अपना दल को 11 सीटें दीं जबकि खुद 384 सीटों पर मैदान में लड़ी थी। इसके दूसरी ओर पिछली सत्ता में काबिज सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया। बसपा ने अलग चुनाव लड़ा लेकिन किसी को भी उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जितनी मिलनी चाहिए थी। भाजपा ने विजय पताका यादवों के गढ़ में फहराई।

अब इसी सफल और कारगर रणनीति पर अन्य राजनीतिक दल भी चल रहे हैं। इनमें सबसे आगे है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो सबसे अधिक छोटे दलों को साध रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2022 में बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने के बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस कड़ी में सपा ने महान दल के साथ हाथ मिलाया और हाल ही में हुए उपचुनाव में चौधरी अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट छोड़ी थी जिसके यह संकेत हैं कि आगे भी वह अजित सिंह के साथ तालमेल कर सकते हैं।

जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। वर्तमान में भी चौहान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। इसके अलावा अखिलेश ने सपा से विद्रोह कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की सीट पर 2022 में प्रत्याशी न उतारने की बात कह कर साफ कर दिया है कि उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि अखिलेश की मंशा लोहिया का सपा में विलय करने की है और इस बारे में उन्होंने शिवपाल को बताया भी है लेकिन शिवपाल केवल गठबंधन के लिए राजी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव ने विलय की बात से साफ इनकार कर दिया है और विस चुनाव के करीब आते ही एक बार फिर सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। इधर, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा लेकिन सपा को बहुत लाभ नहीं मिला। सपा सिर्फ पांच सीटों पर ही रह गई लेकिन बसपा को 10 सीटें जरूर मिल गईं। यही वजह है कि अखिलेश अब बसपा के साथ गठजोड़ करने में ज्यादा इच्छुक नहीं हैं। राज्यसभा चुनावों में एक सीट पर उलटफेर करने के चक्कर में वैसे भी मायावती अखिलेश यादव से खफा हैं।

उप्र में कांग्रेस भी इस बार नए प्रयोग की तैयारी में है और वह भी इस बार चुनाव में छोटे दलों से समझौता कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार मृतप्राय पार्टी में प्राण फूंकने का काम कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि अभी हमारी कोशिश पार्टी संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने की है जिसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद गठबंधन को लेकर कोई बात करेंगे लेकिन हमारी कोशिश जरूर है कि सूबे के जो भी छोटे दल हैं उन्हें साथ लेकर चलें। कांग्रेस पहले भी छोटे दलों को सियासी तरजीह देती रही है। कांग्रेस ग्राम स्तर पर लगातार छोटे दलों को साध रही है।

अब बात करें भीम आर्मी प्रमुख और उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने भीम आर्मी के राजनीतिक फ्रंट आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उपचुनाव के जरिए सियासी एंट्री की है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को बुलंदशहर में मिले मतों के आधार पर चंद्रशेखर दलित समाज में अपनी पैठ मजबूत करने में कामयाब हो रहे हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

होने लगे गठबंधन

उप्र के पांच स्थानीय दलों ने बड़े दलों के साथ जाने के बजाय आपस में ही हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। सुहेलदेव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के नेतृत्व में बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से नया गठबंधन तैयार किया है। ये उप्र की पिछड़ी जातियों के नेताओं का गठबंधन है जिसका ऐलान ओमप्रकाश राजभर ने दो दिन पहले ही किया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के समाज की जहां भागीदारी होगी, वहां पर वो पार्टी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी। उप्र में पिछड़े वर्ग में प्रभावी कुर्मी समाज से आने वालीं सांसद अनुप्रिया पटेल इस दल की अध्यक्ष हैं जबकि अति पिछड़े राजभर समाज के नेता ओमप्रकाश राजभर सुहेलदेव भाजपा का नेतृत्व करते हैं। भाजपा को 312, राजभर को 4 और अपना दल (एस) को 9 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ओमप्रकाश राजभर ने बाद में पिछड़ों के हक का सवाल उठाते हुए भाजपा से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में भाजपा और अपना दल (एस) अभी भी एक साथ हैं और माना जा रहा है कि 2022 में फिर एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

भंवर में नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार के शपथग्रहण के बाद कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, कैबिनेट की पहली बैठक अब तक नहीं हुई है। नीतीश को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना भी अभी बाकी है, जिसमें वह जदयू और भाजपा के मंत्रियों की 50-50 हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि नीतीश अपनी सहयोगी भाजपा से डर गए हैं, वहीं जदयू का कहना है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि कैबिनेट बैठक साप्ताहिक आधार पर बुलाई जाए। लेकिन जदयू के ही सूत्रों ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद भी कैबिनेट बैठक नहीं होना 'नीतीश की ताकत घटने का संकेत है।' इस बीच, राजनीतिक **विशेषज्ञों** का मानना है कि नीतीश को अभी विधानसभा चुनावों में अपनी और अपनी पार्टी को लगे झटकों से उबरने में समय लगेगा।

विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि उनके शपथ ग्रहण के एक सप्ताह के भीतर ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।' उन्होंने कहा, 'हर मंत्रालय बड़ा है और उनके लिए अलग से मंत्रियों की आवश्यकता है। प्रत्येक मंत्री को 4 से 5 विभाग दिया जाना यह बताता है कि केवल कुछ नियमित कार्य किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित बैठकें और समीक्षा बैठकें करें।' राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, 'आत्मविश्वास के अभाव से अधिक ऐसा लगता है कि नीतीश भाजपा के मंत्रियों से डरते हैं। उन्हें डर है कि उनके प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों की तरफ से खारिज कर दिया जाएगा।'

243 विधायकों वाले बिहार में कैबिनेट क्षमता मुख्यमंत्री समेत 37 मंत्री बनाने की हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री समेत केवल 14 मंत्री हैं। भाजपा सूत्रों ने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले भाजपा कोटे के मंत्रियों की सूची को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, 'जदयू कैबिनेट में 50-50 की हिस्सेदारी पर जोर दे रहा है और यह मसला सुलझाया जाना बाकी है। राज्य विधान परिषद् में राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों का मामला भी अनसुलझा है।' नेता ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने बिहार को 'एकदम भुला दिया' है।

बहरहाल, जदयू नेताओं का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी कैबिनेट की बैठक नहीं होना 'नीतीश की ताकत घटने को ही दर्शाता है जो भाजपा नेतृत्व की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते।' जदयू के एक विधायक ने कहा, '2019 में जब उन्हें केंद्र में जदयू का अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था तो नीतीश ने एकतरफा (भाजपा के साथ चर्चा के बिना) अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था।' जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अनुपस्थिति कैबिनेट विस्तार को प्रभावित कर रही है और कैबिनेट की बैठक में भी देरी हो रही हैं। ऊपर उद्धृत जदयू विधायक ने कहा कि मोदी यह सुनिश्चित करा पाते थे कि भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री के भेजे सभी प्रस्तावों से सहमत हों।

साथ ही जोड़ा, 'उनके उत्तराधिकारी तारकिशोर प्रसाद भाजपा के मंत्रियों के बीच उस तरह का रुतबा नहीं रखते हैं जैसा मोदी का था। उन्होंने कई **फैसलों पर केंद्र** और राज्य सरकार के बीच समन्वय किया और नीतीश के फैसलों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें कीं।' लेकिन यह व्यवस्था नहीं रही है। अब जबकि मोदी राज्यसभा सांसद बन चुके हैं तब भाजपा से ज्यादा तो जदयू इसकी उम्मीद कर रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए।

विधायक ने कहा, 'मोदी हो सकता है कि अरुण जेटली के निधन के कारण खाली हुई जगह को भरने में सक्षम हो पाएं जो नीतीश सरकार की जरूरतों को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाते थे। नीतीश कुमार की किसी अन्य भाजपा नेता के साथ जेटली जैसी निकटता नहीं रही है।' साथ ही कहा कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जीवित होते, तो मंत्रिमंडल विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। इस बीच, राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर भी मुख्यमंत्री घिर गए हैं। दरभंगा में दिनदहाड़े एक दुकान से 7 करोड़ रुपए के आभूषणों की डकैती के बाद नीतीश को समीक्षा बैठक करनी पड़ी। यह घटना निकटतम पुलिस स्टेशन से बमुश्किल 250 मीटर की दूरी पर हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया, जिसे लेकर न केवल विपक्ष हमलावर है बल्कि सहयोगी दल भाजपा भी चिंता जताने लगी है।

● विनोद बक्सरी

पिछली कैबिनेट के फैसलों पर काम हो रहा

हालांकि, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि कैबिनेट की साप्ताहिक बैठकें करना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा, 'कैबिनेट की बैठकें सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए होती हैं। अभी पिछली कैबिनेट बैठकों में पारित कई प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो कैबिनेट की बैठकें होंगी।' कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि यह भाजपा और जदयू नेताओं के बीच चर्चा के बाद होगा। हालांकि, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना कि ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश के पास निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा, 'कैबिनेट की बैठकें साप्ताहिक आधार पर होती हैं जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठकें न होना यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार अभी विधानसभा चुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को मिली हार के झटके से उभरे नहीं है। पहले सरकार नीतीश के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती थी। अब ऐसा लगता है कि नीतीश में निर्णय लेने का आत्मविश्वास कम हो गया। यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।'

चीन की बुरी नजर

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो नवंबर को गिलगिट में ऐलान किया कि उनकी सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नए प्रांत का दर्जा देने जा रही है। इस ऐलान ने दक्षिण एशिया में पहले से कायम तनाव में एक और खतरनाक आयाम जोड़ दिया है। कुछ लोग इसे गत वर्ष भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन करने के खिलाफ केवल स्वाभाविक पाकिस्तानी प्रतिक्रिया मान रहे हैं। ऐसा आंकलन न केवल सतही और अज्ञानता भरा, बल्कि चीन के उस षड्यंत्र को अनदेखा करने वाला भी होगा, जिसका लक्ष्य एक कमजोर और हताश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर लद्दाख पर भारत की पकड़ को कमजोर करना और अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे बलूचिस्तान और गिलगिट-बाल्टिस्तान होते हुए शिनजियांग तक के इलाके पर स्थायी नियंत्रण कर लेना है।

भारत सरकार ने अपेक्षानुरूप इमरान के बयान की निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट-बाल्टिस्तान को 1947 में राज्य के संवैधानिक विलय के आधार पर कानूनी और हर तरह से भारत का अटूट हिस्सा बताया और पाक से इन्हें तुरंत खाली करने की मांग की। चीनी नेता पाकिस्तान की सरकारों को तबसे गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी राज्य बनाने की सलाह देते रहे हैं, जबसे चीन ने पाक के रास्ते अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत (ईस्ट-तुर्किस्तान) से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का 'सीपैक' प्रोजेक्ट शुरू किया है। शुरू में 25 अरब डॉलर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ाते-बढ़ाते 60 अरब डॉलर का कर लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ विवाद वाले गिलगिट-बाल्टिस्तान और पाक के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के इलाकों से गुजरता है। चीन को वहां भारत की ओर से कानूनी अड़चनों और सैनिक कार्रवाई की आशंका बनी रहती है।

चीन चाहता है कि अगर पाकिस्तान इन इलाकों को कानूनी तौर पर अपने प्रांत घोषित कर देता है तो वह सीपैक और दूसरी कई रियायतों के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ कानूनी संधि कर सकेगा। तब भारतीय विरोध केवल सैनिक चरित्र वाला रह जाएगा। भारत की सैनिक कार्रवाई की स्थिति में चीन को पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ दोहरे मोर्चे खोलने का बहाना मिल जाएगा। सीपैक प्रोजेक्ट की पूंजी और उस पर ब्याज के दबाव से पाक को राहत देने के लिए चीन पूरे गिलगिट-बाल्टिस्तान को 99 साल के लिए लीज पर लेने की फिराक में है।

गिलगिट-बाल्टिस्तान को लेकर चीन की और भी चिंताएं हैं। लद्दाख में जिस गलवन घाटी पर अचानक हमला करके चीनी सेना ने कब्जे का प्रयास किया था, वह चीन के काराकोरम हाईवे की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सड़क भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन और पाकिस्तान से गिफ्ट के तौर पर मिले शक्सगाम के माध्यम से गिलगिट-बाल्टिस्तान के रास्ते नए सीपैक मार्ग को जोड़ती है। इस हमले का एक और चीनी लक्ष्य भारत के सियाचिन ग्लेशियर पर भी कब्जा जमाना था, जिससे अक्साई चिन और गिलगिट-बाल्टिस्तान के बीच भारतीय सेना की उपस्थिति खत्म हो जाए और चीनी सेना को गिलगिट-बाल्टिस्तान तक भारत की चुनौती से लगभग पूरी मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा चीन की आंतरिक सुरक्षा और शिनजियांग पर अपना औपनिवेशिक कब्जा बनाए रखने के लिए भी गिलगिट-बाल्टिस्तान का चीन के लिए बहुत महत्व है।

1946 से 1949 के बीच चीनी कब्जे से पहले शिनजियांग का मूल नाम ईस्ट तुर्किस्तान है। उइगर मुसलमानों की आबादी वाला यह देश शुरू से ही चीन के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है। चीनी कब्जे के बाद अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हजारों उइगर अपनी सीमा से लगते गिलगिट-बाल्टिस्तान और पाक के दूसरे इलाकों में जा बसे। वहीं से वे चीन के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते आए हैं। इन उइगरों के खात्मे के लिए चीन कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के अलावा वहां के कई जिहादी संगठनों और नेताओं की मदद लेता रहा है। अजहर मसूद जैसे आतंकियों और अन्य कट्टर मजहबी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से बचाने के लिए चीन सरकार जिस उत्साह से आगे बढ़कर काम करती आई है, उसके पीछे शिनजियांग में उनकी मदद ही असली कारण है।

गिलगिट-बाल्टिस्तान के मामले में पाकिस्तान और चीन की इस नई योजना के कुछ भू-राजनीतिक कारण भी हैं। अगर वे इसे पाकिस्तान का नया प्रांत बनाने की योजना में सफल होते हैं तो न केवल पीओजेके और गिलगिट-बाल्टिस्तान को भारत में वापस लाने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, बल्कि भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपना परंपरागत भौगौलिक संपर्क फिर से स्थापित करने का सपना भी टूट जाएगा।

● ऋतेन्द्र माथुर

भारत का सीधा संपर्क अफगानिस्तान से कट गया

इस इलाके को खोते ही भारत का सीधा संपर्क अफगानिस्तान से भी कट गया और उसके रास्ते ईरान पहुंचने की संभावनाएं खत्म हो गईं। गिलगिट-बाल्टिस्तान का कानूनी चरित्र बदलकर उसे एक पाकिस्तानी प्रांत बदलने के बारे में इमरान के बयान का महत्व समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होगा कि पाकिस्तानी संविधान में न तो उसके कब्जे वाले पीओजेके को और न नादर्न एरिया के नाम से मशहूर रहे गिलगिट-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। भारत के साथ विवादित क्षेत्र होने के कारण पाकिस्तान का इन इलाकों पर सैन्य नियंत्रण तो है, पर उनका प्रशासन मिनिस्टरी ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट-बाल्टिस्तान नामक एक विशेष मंत्रालय चलाता है, जिस पर फौज-आईएसआई के अफसरों का कब्जा है। यदि पाकिस्तान इमरान की घोषणा को अमली जामा पहनाने में सफल रहता है और भारत इसे नहीं रोक पाता तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

कसौटी पर खरे उतर पाएंगे बाइडन ?

अपने विजय भाषण के दौरान चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को हमारे ग्रह को बचाने के युद्ध में विज्ञान की ताकतों का इस्तेमाल तेज करना चाहिए। पद संभालते ही उन्होंने पेरिस समझौते को फिर से लागू करने की कसम खाई है। पिछले साल जून में, बाइडन ने कहा था कि उनके पास ग्रीन रिकवरी के लिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की योजना है, जो अगले 30 वर्षों में अमेरिकी उत्सर्जन को 75 गीगाटन कम कर देगा। बाइडन ने यह भी कहा है कि वह अमेरिकी जमीन और पानी पर किसी भी नए तेल और गैस खुदाई लीज को बंद कर देंगे। वह बिजली क्षेत्र के लिए उत्सर्जन मानकों को ठीक करने के लिए एजेंसियों को निर्देशित कर सकते हैं, ताकि शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य की ओर आगे जा सके।

लेकिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर 180 डिग्री बदलाव करना बाइडन के लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले, इसके लिए डेमोक्रेट को अमेरिकी सीनेट पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, चार साल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने 150 से अधिक जलवायु-अनुकूल नियमों में ढील दी, जैसे टेल-पाइप उत्सर्जन, लुप्तप्राय वन्य जीवन और वर्षावन संरक्षण आदि। इससे बाइडन को नुकसान को पूर्ववत करने में काफी समय लगेगा। तीसरा, गैस निकालने के लिए चट्टानों की ड्रिलिंग (हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग) भी एक विवादास्पद मुद्दा है। इस प्रक्रिया में पानी और जहरीले रसायनों की भारी मात्रा में खपत होती है, जिससे पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित होते हैं। इस चीज को लेकर भी जलवायु कार्यकर्ता विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन ओबामा सरकार के दौरान शेल ऑयल में गहरी भागीदारी के लिए बाइडन को जाना जाता है। इसलिए हम फ्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बाइडन से थोड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं।

बाइडन ने ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की कसम खाई थी। लेकिन ट्रम्प के बाद की दुनिया में अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय वार्ता में एक जलवायु नेता बनने के आसार कम हो गए है। 2025 तक 2005 के स्तर के बराबर कार्बन उत्सर्जन को 26-28 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य अमेरिका शायद ही हासिल कर पाए। वास्तव में, अमेरिका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर सबसे निचले रैंक पर है, जिसे 2020 में जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सर्जक होने के अलावा, अमेरिका अभी भी प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है। असल में 2019 में शुद्ध अमेरिकी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2016 से अधिक था।

बाइडन के लिए विश्वसनीयता हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी। बाइडन को न केवल अपने देश को व्यवस्थित करने की जरूरत है, बल्कि बातचीत की मेज पर अमेरिका को वापस लाने पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगले साल ग्लासगो में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट एक्शन (यूएनएफसीसीसी) कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-26 के लिए गति प्रदान करना चाहिए। बाइडन के पास कुछ हद तक नेतृत्व करने का अवसर होगा और नेट शून्य लक्ष्य निर्धारित करने में चीन और जापान जैसे अन्य देशों के साथ भी शामिल होने का मौका होगा। इसके अलावा, अमेरिका को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और न्यूनीकरण पर गरीब विकासशील देशों को उचित हिस्सा देने की भी आवश्यकता है। लेकिन बाइडन के मध्यमार्गी नवउदारवादी राजनीतिक झुकाव को देखते हुए, वह बाजार-आधारित दृष्टिकोणों और जलवायु-कार्रवाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी का पक्ष लेंगे, न कि आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप का।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बाइडन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के ट्रम्प के फैसले को पलटने की कसम खाई है। ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस के संक्रामकता को कम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। विश्व की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के साथ अमेरिका के संबंधों को बहाल करने को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बाइडन पर भरोसा कर रहे हैं। वह अन्य देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को चलाने या वनों की कटाई को कम करने के लिए व्यापार सौदों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए दबाव डाल सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के प्रोफेसर रिफत अतन कहते हैं, संबंध पूरी तरह से पुनर्स्थापित होने चाहिए।

● **कुमार विनोद**

बाइडन जलवायु विज्ञान और जलवायु नीति को बहाल करेंगे?

बाइडन के साथ कुछ आशा है। 20 जनवरी 2021 को जब जो बाइडन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, तो उनसे जलवायु परिवर्तन पर मजबूत काम शुरू करने की उम्मीद है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान की भूमिका को मानते और उसका अनुसरण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते खतरनाक वैज्ञानिक प्रमाणों की पृष्ठभूमि में यह तथ्य विशेष रूप से प्रासंगिक है। तेजी से पिघलता आर्कटिक यह इंगित करता है कि ये उत्सर्जन 20 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को रोकने के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को असंभव बना सकता है। जलवायु परिवर्तन और जलवायु विज्ञान से संबंधित जो बुनियादी कदम बाइडन उठाएंगे, वह यह कि सभी कार्यकारी शाखाओं जैसे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, आंतरिक विभाग, कृषि विभाग और राज्य विभाग में जलवायु विज्ञान और नीति कर्मियों को बहाल करना होगा। इन सभी महत्वपूर्ण विभागों को ट्रम्प सरकार के दौरान कर्मियों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा है। लोगों को निकाल दिया गया। यह नया कदम मिशन इनोवेशन को फिर से मजबूत करेगा। यह पेरिस समझौते की शुरुआत में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जताई गई सहमति थी। दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में 85 प्रतिशत सरकारी निवेश की बात थी।

सुरक्षित नहीं भविष्य

केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद भविष्य (बच्चे) सुरक्षित नहीं हैं। खासकर बालिकाओं का भविष्य असुरक्षित है। मप्र में हर दिन 28 नाबालिग बच्चे लापता होते हैं उनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। सीआईडी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े देखें तो प्रदेश से 18 हजार 628 नाबालिग गुमशुदा हुए हैं। इनमें 14730 लड़कियां है। यानी लापता हुए बच्चों में 80 फीसदी लड़कियों की संख्या होती है। प्रदेश में लाड़लियों के गुमशुदा होने की स्थिति बेहद चिंताजनक है यानी बचपन को नजर लगी हुई है। सीआईडी गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए खोया-पाया विशेष अभियान चलाती है जिसमें पिछले सालों में लापता हुए कई बच्चे पड़ोसी राज्यों में मिल जाते हैं लेकिन उनके गुम होने का सिलसिला नहीं थम रहा है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन अपहरण के मामलों में मानव तस्करी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो बच्चे लापता होते हैं वे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों जैसे झाबुआ, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, धार, बालाघाट जैसे सीमावर्ती जिलों में गुमशुदगी के प्रकरण ज्यादा दर्ज होते हैं। लापता बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र, उप्र, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं। कई लड़के-लड़कियां आपस में शादी भी कर लेते हैं। प्रदेश में इस साल पुराने लापता बच्चे भी घर लौटे। इस साल 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक 10 महीनों में 7684 नाबालिग बच्चे गुम हुए। इनमें से 6099 लड़कियां और 1284 लड़के शामिल थे। यानी करीब 83 फीसदी 18 साल से उम्र की बच्चियां इन दस महीनों में गायब हुईं। इस हिसाब से रोजाना 20 बच्चियां प्रदेश से लापता हो रही हैं। इस साल मजदूरों की वापसी और पुलिस की तलाश में 8134 गुमशुदा बच्चे बरामद हुए। इनमें 6741 लड़कियां और 1393 लड़के शामिल थे।

पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक एक साल में कुल 11244 नाबालिग बच्चे लापता हुए। इनमें 8631 लड़कियां और 2613 लड़के शामिल थे। यानी करीब 77 फीसदी नाबालिग बच्चियां इस साल गायब हुईं। इस हिसाब से 24 बच्चियां रोजाना गुमशुदा हुईं। इस साल पुलिस के खोया-पाया अभियान से 10868 बच्चे बरामद हुए, जिनमें 8310 लड़कियां और 2558 लड़के शामिल हैं। बच्चों की बरामदी करीब 96 फीसदी रही। एडीजी सीआईडी कैलाश मकवाना की मानें तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर रोक लगाई जा सके। हमारा खोया-पाया अभियान चलता है, जिसमें हम गुम हुए बच्चों को दस्तयाब करते हैं। विशेष अभियान चलाकर हमने हजारों बच्चों को खोज निकाला है। इस तरह के मामलों में हम तत्काल और सघन कार्रवाई करते हैं।

प्रदेश में हर साल अपराध बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बच्चों के अपहरण के मामले में मप्र तीसरे नंबर पर है। 2018 में प्रदेश से 7951 बच्चों के अपहरण के मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा लड़कियां थीं। इस हिसाब से प्रदेश में हर रोज 16 लड़कियों का अपहरण हो रहा है। 2018 में कुल 5767 लड़कियों और 2184 लड़कों का अपहरण हुआ। इनमें लड़कियों का सबसे ज्यादा 72.53 प्रतिशत है। प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव ने कहा कि यह चिंता का विषय है। पुलिस के साथ परिवार को सचेत रहने की जरूरत है, जिस तरीके की आजादी है, वैसी लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। पश्चिमी देशों जैसी मानसिक आजादी नहीं आई है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे ही शिकायत आए, वैसे ही एफआईआर के साथ जांच शुरू कर देनी चाहिए। यदि मामला झूठा है, तो उसमें खात्मा भेज देना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई के साथी सख्ती से निपटना पड़ेगा। 2018 में 12 से 16 और 16 से 18 साल की आयु की लड़कियों के अपहरण के मामले सबसे ज्यादा 94 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 92 प्रतिशत है। भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि यह सही बात है कि अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गाइडलाइन है कि यदि बच्चा थोड़ी देर के लिए भी चला जाए और शिकायत आए, तो उसमें अपहरण का केस दर्ज करना है। इसका पालन किया जा रहा है। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। अधिकांश मामलों में बच्चों को ढूंढ भी लिया जाता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर मात्र 27.2 प्रतिशत

दुष्कर्म के मामलों में देश में सजा की दर अब भी मात्र 27.2 प्रतिशत ही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2018 में दुष्कर्म के 1,56,327 मामलों में मुकदमे की सुनवाई हुई। इनमें से 17,313 मामलों में सुनवाई पूरी हुई और सिर्फ 4,708 मामलों में दोषियों को सजा हुई। आंकड़ों के मुताबिक 11,133 मामलों में आरोपी बरी किए गए जबकि 1,472 मामलों में आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया। खास बात यह है कि 2018 में दुष्कर्म के 1,38,642 मामले लंबित थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर 2018 में पिछले साल के मुकाबले घटी है। 2017 में सजा की दर 32.2 प्रतिशत थी। उस वर्ष दुष्कर्म के 18,099 मामलों में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और इनमें से 5,822 मामलों में दोषियों को सजा हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनसीआरबी भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानून के तहत देश में अपराध के आंकड़ों को एकत्रित करने तथा विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है।

कुंडली के दोषों का समाधान

भगवान श्रीकृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को महाभारत कथा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हम सभी के लिए मील का पत्थर है। इसे ज्ञान का अमृत गंगा कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। गीता हमें न केवल सकारात्मकता देती है, वह हमें मुश्किल परिस्थितियों में राह भी दिखाती है। गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्रीकृष्ण ने कुछ संकेत दिए हैं। जिनकी व्याख्या आज हम ज्योतिष विद्या के अनुरूप कर रहे हैं। इन सूत्रों का प्रयोग ग्रहों के फलादेश और अशुभ प्रभाव को दूर करने में किया जा सकता है।

श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करने से शनि जनित दोषों का निवारण होता है। निराशा, हताशा की स्थिति में होने पर व्यक्ति का इस अध्याय का पाठ करना सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जन्मपत्री में जब शनि से चंद्र पीड़ित हो तो व्यक्ति निराशा भाव में आकर अवसादग्रस्त होता है। इस अवसाद से बाहर लाने में भागवत गीता का प्रथम अध्याय उपयोगी साबित होता है। यदि जन्मपत्री में गुरु शनि द्वारा पीड़ित हो तो व्यक्ति को भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। द्वितीय अध्याय का अध्ययन करने से धन, ज्ञान, संतान और शिक्षा की प्राप्ति होती है। तृतीय अध्याय के अध्ययन से पुरुषार्थ आध्यात्मिक ज्ञान की आग में तपकर कुंदन हो जाता है। मंगल ग्रह कार्य करने का सूचक है, गुरु मार्ग दिखाता है और शनि कर्म के लिए प्रेरित करता है। यह योग व्यक्ति को जुझारु स्वभाव देता है।

फल की चिंता किए बिना कार्य करते रहना, चतुर्थ अध्याय का सार है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसके भीतर आगे बढ़ने की इच्छाएं भी मजबूत होती है परंतु पूर्ण समर्पण और लक्ष्य में स्थिरता की कमी व्यक्ति की सफलता में बाधक बनती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में नवमेश और दशमेश में राशि परिवर्तन योग बन रहा हो, उस व्यक्ति को पंचम भाव का अध्ययन करने से लाभ मिलता है। उत्तम सफलता अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि परिणामों की चिंता किए बिना ही अपना उत्तम प्रदर्शन करते रहना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव पर गुरु, शनि और शुक्र का प्रभाव आता है तो व्यक्ति एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। दुखों की रात के बाद सुख रूपी सूर्य के आगमन के जैसे यह योग फल देता है। इस योग से युक्त व्यक्ति को छठे अध्याय का अध्ययन करना चाहिए।

जिस व्यक्ति की कुंडली या गोचर में आठवां भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को सप्तम अध्याय का अध्ययन करने से राहत मिलती है। और मोक्ष के योग बनते है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु कारक भाव द्वादश भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति को मौत का भय पीड़ित करता है। इस भय से बाहर आने के लिए व्यक्ति को श्रीमद्भागवत गीता के अष्टम भाव का अध्ययन करना चाहिए। जन्मपत्री का लग्न भाव स्व भाव है, लग्नेश व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है और दशमेश को कर्म भाव का स्वामी कहा गया है, मूल स्वराशि से अभिप्राय: चंद्र राशि से है। तीनों एक-दूसरे के मित्र संबंध में हों तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप सफलता हासिल होती है। क्षमताओं के अनुरूप कामयाबी प्राप्त करने के लिए नवम अध्याय का अध्ययन करना चाहिए।

जब भी व्यक्ति कर्म भाव से विमुख हो रहा हो या उसे आलस्य घेर रहा हो, वह भाग्यवादी होकर जीवन की ओर जा रहा हो तो व्यक्ति को भागवत गीता के दशम अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। यदि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश और अन्य सभी ग्रह 8वें भाव से 12वें भाव के मध्य स्थित हो तो व्यक्ति को भागवत गीता के एकादश भाव का अध्ययन करना चाहिए। यदि कुंडली में पंचम भाव एवं नवम भाव शुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हो और चंद्र पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को श्रीमद्भागवत गीता के द्वादश भाव का अध्ययन करने से सुख मिलता है।

यदि कुंडली में चंद्र द्वादश भाव से संबंध रखता हो और द्वादशेश से किसी प्रकार से प्रभावित हो तो व्यक्ति को गीता के त्रयोदश अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। यदि कुंडली के आठवें भाव में कोई उच्च का ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति को चतुर्दश अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। पूर्व जन्म में हम क्या थे, और कौन से कार्यों के फलस्वरूप हमें यह जन्म प्राप्त हुआ। इसकी जानकारी लग्न और पंचम भाव से की जा सकती है। लग्न और पंचम का संबंध कुंडली में स्थित हो तो व्यक्ति को पंद्रहवें अध्याय का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। जब सूर्य कुंडली में अशुभ या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को षोडश अध्याय का अध्ययण करना चाहिए। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। जन्म के साथ व्यक्ति की जीवन यात्रा शुरू होती है, और कई बार अनेकों अनेक जन्मों तक चलती रहती है। इस जन्म जन्मांतर के चक्रों से बाहर आने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अठारहवें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।

इस प्रकार गीता के अट्ठारह अध्यायों का अध्ययन करने से व्यक्ति ज्ञानी बन, अपने पापों का नाश करता है, भगवतगीता के अट्ठारह अध्यायों के अध्ययन से व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति पाकर ईश्वर में लीन हो जाता है। व्यक्ति की कुंडली के अशुभ योगों का निवारण भी गीता के अट्ठारह अध्यायों का अध्ययन कर किया जा सकता है।

● ओम

पतझड़ की वह शाम

पतझड़ के दिन यूं तो हर वर्ष आते हैं लेकिन पिछले साल कुछ यादगार शाम लेकर आया, लगा जैसे जिंदगी बदलने वाली हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे शब्दों में कहा जा सकता था। बस महसूस हुआ जैसे पेड़ से पत्ते गिरते ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता हैं, उसे कभी भी, कोई भी, कुचल जाता हैं, तो कभी कोई जला जाता हैं वैसा ही कुछ महसूस हुआ था। अक्सर पेड़ से जुड़े पत्ते बहुत ही खूबसूरत और काम के होते हैं फिर वे गिरते ही बदसूरत कैसे हो गए? हो गए कैसे लावारिस लाश की तरह!

यह समझना ज्यादा मुश्किल तो नहीं लेकिन इस तरह लावारिस जीना यकीनन किसी तपस्वी के घोर तप से कम भी नहीं कह सकते। क्योंकि किसी फुदकती चिड़िया का किसी आंगन में यकायक खामोश हो जाना चिड़िया की गलती तो न होगी, हां! खुद्दारी की कीमत हो सकती हैं पर इसे समझने के लिए उस आंगन में जाना होगा; देखना होगा; समझना होगा...; पर आज इतना समय और समझ किसके पास हैं जो किसी चिड़िया पर व्यतीत करें। ऐसे में चिड़िया पर दोषारोपण करना बेहतर होगा और परिणाम जल्द मिल जाएगा, उसकी खामोशी का। ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ के पत्ते लावारिस नहीं, खाक होते हुए।

यकीनन वह शाम भी जिंदगी की कुछ ऐसी ही थी, मेरे माता- पिता का यूं एक साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार जाना और मेरा उसी क्षण समझदार हो जाना, पतझड़ के मौसम से किसी भी तरह कम न था। क्योंकि उसी शाम से मैं बच्ची न होकर 'शमा' हो गई। और अब पतझड़ की हर शाम 'शमा' हो गई।

– रेशमा त्रिपाठी

गंदा खून

एक युवा मच्छर खिड़की की फटी हुई जाली से कमरे में घुसने के प्रयास में घायल हो गया। आनन-फानन उसके साथी मच्छरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

ऑपेरशन के लिए उसे खून चढ़ाना होगा यह पता चलते ही एक अन्य युवा मच्छर बोला, डॉक्टर साहब! आप ऑपेरशन की तैयारी कीजिये, मैं अभी आया!

उसे टोकते हुए उस घायल मच्छर का वृद्ध पिता बोला, कहां से लाओगे इतनी जल्दी खून? कुकुरमुत्तों की तरह फैली इन गंदी बस्तियों में इंसानों की कमी कहां है? अभी उनके जिस्म से भर ले आता हूं जरूरत भर का खून! युवा मच्छर आत्मविश्वास से बोला।

ठहरो! अचानक वह वृद्ध मच्छर दहाड़ उठा, अपने कुकृत्यों से जानवरों को भी शर्मसार करने वाले नराधम, जाति-पाति व धर्म-मजहब के साथ ही जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले वहशी दरिंदों के गंदे खून से नहीं देनी मुझे अपने बेटे को जिंदगी!

नारी जीवन

शम्मा-सा जलता है पल-पल,
और पिघलता नारी जीवन।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।
कर्म निभाती है वो तत्पर,
हर मुश्किल से लड़ जाती
गहन निराशा का मौसम हो,
तो भी आगे बढ़ जाती
पत्नी, मां के रूप में सेवा,
तो क्यों खलता नारी जीवन।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।
संस्कार सब उससे चलते,
धर्म भी सभी उससे खिलते
तीज-पर्व नारी से पोषित,
नीति-मूल्य सब उसमें मिलते
आशा और निराशा लेकर,
नित ही पलता नारी जीवन।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।
कहने को तो दो घर उसके,
पर सब कुछ है बेमानी
भटक-भटककर, तड़प-तड़पकर
कटती देखो जिंदगानी
त्याग औ' करुणा, धैर्य-नम्रता,
कंटक चलता नारी जीवन।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।
कर्मठता, पर शोषण होता,
छल, मातम के मेले हैं
दुख, तकलीफें, व्यथा-वेदना,
हर पल रोज झमेले हैं
स्वयं छोड़कर, सारे गृह को
हरदम फलता नारी जीवन।।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।
ताकत बेहद, पर नेहिल है,
है संतोषम् परम् सुखम्
नहीं निराशा औ' मायूसी,
हाल वही अब भी कायम
नतमस्तक हो अनाचार सह,
खुद को छलता नारी जीवन।
देकर घर भर को उजियारा,
आंखें मलता नारी जीवन।।

– प्रो. (डॉ.) शरद नारायण खरे

कभी भारत में राजा-महाराजाओं का खेल रहा क्रिकेट आज आम भारतीय का खेल बन गया है। भारतीय क्रिकेट के उत्थान में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से एक रहे हैं सीके नायडू। राजा-महाराजाओं के हाथ से क्रिकेट को आम आदमी तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें अंग्रेज हिंदू ब्रेडमैन के नाम से पुकारते थे।

'हिंदू ब्रेडमैन'

1932 में भारत को टेस्ट खेलने वाले देश का दर्जा मिला तो भारतीय टीम में कप्तानी के लिए कोई महाराजा नहीं था। हालात ने उस टेस्ट की कप्तानी सीके नायडू को सौंप दी जो उस टीम में पहले ही कप्तानी के लिए सबसे योग्य थे। सीके नायडू महाराजा या प्रिंस नहीं थे लेकिन वे भी अभिजात्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता वकील थे और उनके जमींदार दादा को अंग्रेज सरकार ने रायबहादुर की उपाधि से नवाजा था। लेकिन सीके नायडू बेहतरीन क्रिकेटर थे। बंबई और लंदन के क्रिकेट दायरे में उनके प्रथम श्रेणी मैचों में प्रदर्शन के चर्चे थे। बंबई जिमखाना और मद्रास के मैचों में हिंदू टीम की ओर से खेलते हुए नायडू ने इतने लंबे छक्के मारे थे कि जो पवेलियन में जाकर गिरे थे।

भारतीय क्रिकेट के उस 'महाराजा-युवराज युग' में सीके नायडू को कप्तानी नियति ने सौंपी थी। पहले मैच में नायडू के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किया। 25 जून 1932 को शुरू हुए इस तीन दिवसीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। नायडू ने भारतीय गेंदबाज मोहम्मद निसार और अमर सिंह को गेंद को हर हाल में सही लेंथ पर डालने के निर्देश दिए। और नतीजा यह रहा कि भारत की नौसिखिया माने जाने वाली टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 19 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। बाद में कप्तान डगलस जार्डिन (जिन्हें बॉडीलाइन गेंदबाजी का जनक कहा जाता है) के 79 रनों की बदौलत इंग्लैंड संभला और टीम पहली पारी में 259 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद निसार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 93 रन देकर पांच विकेट चटकाए। कप्तान सीके नायडू ने भी मैच में दो विकेट लिए। उन्होंने डगलस जार्डिन का कीमती विकेट चटकाया। पर गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन को बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। पहली पारी में भारतीय टीम 189 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान सीके नायडू को गली में एक कैच पकड़ने के प्रयास में हाथ में चोट लग गई थी। इसके बाद भी उन्होंने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए।

दूसरी पारी में इंग्लैंड ने आठ विकेट पर 275 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में जहांगीर खान ने 60 रन देकर चार विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी 187 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत अपना पहला टेस्ट 159 रनों से हार गया। लेकिन पहले ही मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और नायडू की कप्तानी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। सीके नायडू का नाम भारत के पहले टेस्ट कप्तान के तौर पर दर्ज हो चुका था। सुर्खियां उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थीं। इसके बाद मिडिलसेक्स और सॉमरसेट काउंटी के खिलाफ उन्होंने 101 और 130 रन बनाए। 1932 में भारत का इंग्लैंड दौरा जब खत्म हुआ तो नायडू पांच शतकों के साथ 42.34 के औसत से 1613 रन बना चुके थे। इस दौरान उन्होंने 29.33 के औसत से 59 विकेट भी चटकाए। सीके नायडू ने पूरे दौरे में 32 छक्के जड़े। लॉर्ड्स में एमसीसी के खिलाफ नायडू ने जब 130 रनों की शानदार पारी खेली तो इंग्लैंड के तबके प्रसिद्ध अखबार स्टार ने उन्हें 'हिंदू ब्रेडमैन' तक कहा। द स्टार की हेडिंग थी- 'द हिंदू ब्रेडमैन इन फार्म एट लॉर्ड्स।' हिंदू ब्रेडमैन कहने के पीछे की वजह यह थी कि बंबई जिमखाना में सीके नायडू हिंदू टीम की तरफ से खेलते थे। भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले नायडू की ख्याति हिंदू टीम के खिलाड़ी के तौर पर ही थी।

सीके नायडू को होल्कर शासकों ने कर्नल की उपाधि दी थी। 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नायडू की उस समय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1941 में बाथगेट लीवर टॉनिक का विज्ञापन किया और किसी ब्रांड का प्रचार करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। सीके नायडू ने 36 साल की उम्र में भारत की कप्तानी की थी और वे 60 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। ब्रेडमैन से उनकी तुलना एक तात्कालिक उत्साह का नतीजा मानी जा सकती है, लेकिन नायडू का पूरा व्यक्तित्व खेल में रमा था। क्रिकेट के अलावा वे हॉकी और फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे और कहा जाता है कि 100 यार्ड की दौड़ कर्नल 11 सेकेंड में पूरी कर लेते थे। 14 नवंबर 1967 को सीके नायडू का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए पहला-दूसरा क्या, तीसरा विकल्प भी नहीं माने जा रहे कर्नल सीके नायडू ने भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की ऐसी बुनियाद रखी कि आगे चलकर भारत दो बार विश्व विजेता तक बना।

● आशीष नेमा

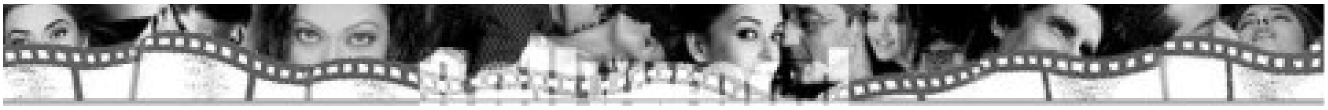

...जब 13 साल बड़े ऋतिक को डेट कर रही थीं कंगना रनोट

कंगना रनोट इन दिनों अपने एक्स-ब्वॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों के बीच हुए चार साल पुराने ईमेल विवाद की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलीजेंस यूनिट करेगी। कंगना एक वक्त अपने से 13 साल बड़े ऋतिक को डेट कर रही थीं, जब वे शादीशुदा थे। इतना ही नहीं, पत्नी सुजैन से तलाक के बाद ऋतिक ने कंगना से सगाई भी कर ली थी। हालांकि, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। वैसे, कंगना की लव लाइफ हमेशा चर्चा का विषय रही है। इतना ही नहीं अपने से 22 साल बड़े एक्टर आदित्य पंचोली के साथ भी कंगना का नाम जुड़ चुका है। कंगना रनोट जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थीं, तब उनका नाम 22 साल बड़े आदित्य पंचोली से जुड़ा। शादीशुदा और दो बच्चों के पिता आदित्य के साथ कंगना को कई जगह खुलेआम स्पॉट किया गया। दरअसल, आदित्य उनके मेंटर की भूमिका में थे। मीडिया रिपोर्ट्स तो इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि आदित्य और कंगना लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं। फिर कंगना ने आदित्य पर ये आरोप लगाकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया था कि वह उनके साथ मारपीट और शारीरिक शोषण करते थे।

अमिताभ बच्चन के साथ बोल्ड सीन शूट कर रातभर रोई थीं स्मिता पाटिल

80 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस स्मिता पाटिल बाजार, अर्थ, आक्रोश जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही हैं। पहले बच्चे प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद ही डिलीवरी में आए कॉम्पलिकेशन के चलते स्मिता का निधन महज 31 साल की उम्र में हो गया था। 13 दिसम्बर को उनको गुजरे हुए 34 साल हो चुके हैं। एक्ट्रेस साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई हैं। इस फिल्म का गाना आज रपट जाएं दोनों की बोल्ड केमिस्ट्री के कारण काफी चर्चा में रहा था लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के बाद एक्ट्रेस बहुत रोई थीं।

पॉपुलर गाने आज रपट जाएं में स्मिता के अमिताभ बच्चन के साथ कई बोल्ड सीन थे। बारिश में भीगते हुए दोनों ने कुछ बेहद सेंसेशनल सीन दिए थे हालांकि इससे एक्ट्रेस खुश नहीं थीं। जब गाने की शूटिंग पूरी हुई तो एक्ट्रेस घर पहुंचकर अपनी मां की गोद में जमकर रोई थीं। बोल्ड सीन देकर असहज हुईं एक्ट्रेस रात भर पछतावे में रोती रही थीं। बाद में एक्ट्रेस गुमसुम रहने लगीं।

अमिताभ के कहने पर दोबारा शुरू की शूटिंग... इस बात की जानकारी मिलने पर अमिताभ बच्चन ने स्मिता को समझाया कि वो इस एक्ट से परेशान ना हों क्योंकि ये स्क्रिप्ट और गाने की डिमांड थी। बिग बी ने उन्हें अच्छे तरीके से सहज महसूस करवाया और एक्ट्रेस ने दोबारा शूटिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म नमक हलाल एक बड़ी हिट साबित हुई और साथ ही दोनों के गाने को भी दर्शकों की खूब सराहना मिली। इसके बाद स्मिता और अमिताभ की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई। खबरों की मानें तो स्मिता अमिताभ को काफी पसंद भी करने लगी थीं लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में राज बब्बर आए और दोनों की शादी हो गई।

अर्चना पूरन सिंह ने 4 साल तक छिपाई थी शादी की बात

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि, चार साल तक पती परमीत सेठी और उन्होंने अपनी शादी की बात छिपाई थी। क्योंकि परमीत सेठी की फैमिली को अर्चना के एक्ट्रेस होने पर आपत्ति थी और वह इस शादी के खिलाफ थे। 'कपिल शर्मा शो' में सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह सेलिब्रिटी गेस्ट थे। इस दौरान अर्चना ने नेहा और रोहनप्रीत को बताया कि, परमीत सेठी के माता-पिता दोनों की शादी के खिलाफ थे। क्योंकि उन्हें अर्चना के एक्ट्रेस होने पर आपत्ति थी। जिसके कारण उन्होंने शादी के लिए इंकार कर दिया था। लेकिन परमीत ने अर्चना से कहा था कि वह उनसे ही शादी करेंगे।

अर्चना ने आगे बताया कि, जिस दिन परमीत के माता-पिता ने इंकार कर दिया था। उसी दिन परमीत उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद हम दोनों पंडित जी के पास गए। उन्होंने परमीत से पूछा कि लड़की बालिक तो है ना? पंडित जी के इस सवाल पर परमीत ने कहा कि वो मुझसे भी ज्यादा बालिक है। फिर पंडित जी ने हमें अगले दिन आने को कहा था।

अर्चना ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि, वे सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। सेट पर उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वे शादी करने वाली हैं। यहां तक कि जब उनकी शादी हो रही थी, तब उन्हें अपने हेयर ड्रेसर का फोन आया था। लेकिन उन्होंने उसे भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि करीब चार साल तक दोनों को अपनी शादी छिपानी पड़ी थी।

ग्राउंड जीरो

मैंने इस बार सोचा कि शायद प्ले ग्राउंड को ही ग्राउंड जीरो कह रहे होंगे पर ये प्ले ग्राउंड में पता नहीं प्ले की जगह बार-बार जीरो क्यों लगा रहे हैं, सीधा प्ले ग्राउंड पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं।

मेरे प्रिय मित्र भाई भरोसे लाल आए और बोले कि तैयार हो जाओ ग्राउंड जीरो पर चलना है। क्योंकि मेरा अंग्रेजी का ज्ञान अल्पतम है चलो पहले अल्पतम का ही मतलब बता दूं क्योंकि हो सकता है आप सब अंग्रेजी प्रेमी होंगे ही इसलिए संभव है कि आपका हिंदी ज्ञान भी अंग्रेजी जैसा ही हो। इसलिए ही बता रहा हूं। अल्पतम ज्ञान का अर्थ यानि मतलब है न के बराबर यानि बहुत कम जानकारी होना। पहले सोचा अल्पतम ही रहने दूं क्योंकि यदि सीधा-सीधा बता दूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो लोग मुझे बिलकुल ही अनपढ़ समझेंगे क्योंकि हमारे देश में उन्हें ही समझदार और पढ़ा-लिखा माना जाता है जिन्हे अंग्रेजी आती है। इसलिए अंग्रेजी जानने वालों को ही यहां अफसर बनाते हैं। इसीलिए सोचा था कि अल्पतम ही रहने दूं ताकि जिन्हे अंग्रेजी आती है कम से कम उन्हें तो मैं पढ़ा-लिखा लगूं।

पर भाई भरोसे लाल मेरे मित्र हैं तो मैं उन्हें जाने के लिए मना नहीं कर सकता था और वैसे भी आज छुट्टी थी कोई बहाना भी नहीं था। इसलिए उनके साथ जाने के लिए मैं तैयार होने लगा। अभी मैं तैयार भी नहीं हुआ था कि इतने में तो उन्होंने आकर दरवाजा भी खटखटा दिया और बोले जल्दी बाहर आ जाओ। मैंने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया पर आज वे नहीं माने और जल्दी चलने को बोलने लगे। मुझे अजीब सा लगा नहीं तो वे बिना चाय पिए तो कभी जाते ही नहीं थे। बस यही कहते रहे कि जल्दी करो। फिर भी मैंने पूछ ही लिया कि भाई जाना कहां है। तो फिर उन्होंने वही बात दोहरा दी कि ग्राउंड जीरो जाना है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ग्राउंड जीरो हमारे देश की सीमा से शुरू होता हो पर वह तो बहुत दूर है और वहां तो बिना प्रेस का ताम-झाम लिए बिना जा भी नहीं सकते हैं फिर पता नहीं वहां जाने की क्यों कह रहे हैं।

मैंने हिम्मत करके फिर पूछ लिया कि भाई आखिर जाना कहां है तो फिर उन्होंने वही जबाब दिया कि बताया तो ग्राउंड जीरो जाना है। मैंने इस बार सोचा कि शायद प्ले ग्राउंड को ही ग्राउंड जीरो कह रहे होंगे पर ये प्ले ग्राउंड में पता नहीं प्ले की जगह बार-बार जीरो क्यों लगा रहे हैं सीधा प्ले ग्राउंड पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं। यह सोचकर मैंने उन्हें पूछा कि क्या किसी स्कूल में कोई टूर्नामेंट यानि खेल प्रतियोगिता हो रही है। तो उन्होंने मेरी ओर बड़े आश्चर्य से ऐसे देखा कि पता नहीं मैं इनकी किसी महिला मित्र के विषय में पूछ रहा हूं। मुझे भी लगा कि शायद मैंने उनसे कोई गलत प्रश्न ऐसे पूछ लिया है जैसे जब घर में सब्जी बन चुकी हो और तब आप श्रीमती जी से कहे आज तो बाजार में खाना खाने का मन है, तो वह भी ऐसे ही देखेगी जैसे भाई भरोसे लाल ने मेरी और देखा। जिसके कारण मैं कुछ समय के लिए मजबूरी में चुप हो गया।

परंतु मेरी उत्सुकता दूध के उफान की तरह बाहर बड़ी तेजी से निकल रही थी, तो इसे रोकना मेरे बस की बात ही नहीं थी। आप समझ ही गए होंगे कि दूध में कैसे उफान आता है, वैसे ही मुझे ग्राउंड जीरो की प्रबल इच्छा हो रही थी इसलिए मेरे लिए इसे रोकना बड़ा मुश्किल था कि यह ग्राउंड जीरो कहां पर है। इसलिए इस बार मैंने थोड़े कड़ेपन से पूछा कि भाई आप बताते क्यों नहीं कि यह ग्राउंड जीरो कहां हैं या हम जा कहां रहे हैं। उन्होंने जब मेरा यह रुख देखा तो उनके मुंह से भी फूल तो नहीं झड़े पर चिंगारी की तरह शब्द झड़ने लगे कि तुझे कुछ पता भी है कि अपने शहर में क्या हो रहा है।

क्योंकि अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैंने भी लगे हाथ पूछा कि जब मुझे पता नहीं है तो क्या आप मुझे बता भी नहीं सकते हो कि कहां जाना है। आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि किसी दरिंदे ने किसी बच्ची के साथ अनाचार किया है वहीं जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि आखिर इस देश में यह क्या हो रहा है। आखिर हमारा समाज कितना गिरेगा। तब मैंने उन्हें पूछा कि वहां पुलिस नहीं पहुंची या पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की क्या? उन दरिंदों को पकड़ना तो पुलिस का काम है। तब उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस ने तो शाम को ही गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर हम वहां किसलिए जा रहे हैं उन्हें पकड़कर अब अदालत में सौंपना पुलिस का काम है और अब उन्हें सजा देना न्यायालय यानि अदालत का काम है। और हम न तो पुलिस हैं और न ही अदालत हैं। तो हम वहां किसलिए जा रहे हैं?

तब वे बोले बंधु आप भी रहे वही, अरे पुलिस और न्यायालय तो जो करेंगे वह करेंगे ही क्योंकि सब जानते हैं कि पुलिस कैसी है और कभी किसी दबाब में कुछ सही कर भी दे तो न्यायालय में कौन सा आसानी से न्याय मिल जाएगा। वहां तो कानून की किताब के हिसाब से न्याय होता है न्याय के हिसाब से नहीं। तो कुछ करना है। हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस पर दबाब कैसे बनेगा। मैंने उनसे कहा कि पर मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि हमे दबाब बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इस देश में कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। वे बोले आपको यह सब समझ नहीं आएगा हम दबाब बनाने के लिए ही तो ग्राउंड जीरो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वहां धरना देकर जुलूस निकालें और महामहिम राष्ट्रपति जी और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे सकें। इससे प्रशासन पर दबाब बनेगा।

अब मैं समझ गया कि यह ग्राउंड जीरो कौन सा है यानि जहां दुराचार हुआ है उसे ही ये ग्राउंड जीरो कह रहे हैं। परंतु यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हर दिन अलग-अलग शहरों से आती रहती है ऐसी कौन-सी जगह है जहां पर यह ग्राउंड है। कहीं दिन दहाड़े लूट या डकैती हो जाती है, कहीं पर दिन में ही गोलियां चल जाती हैं, कहीं पर सरेआम गुंडे आकर किसी को भी धमका जाते हैं, कहीं पर कोई शराब पीकर नशे में किसी पर भी गाड़ी चढ़ा देता है। ऐसा एक अपराध हो तो बताऊं यहां तो हर दिन अनगिनत अपराध होते हैं। ऐसा कौन-सा दिन होगा जिस दिन ऐसी खबरें न आतीं हों या कौन-सी ऐसी जगह है जहां से ये खबरें न आती हों और इसीलिए हर दिन क्या हर घंटे ही कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो बना ही रहता है।

● डॉ. वेद व्यथित

PRISM®
CEMENT
प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस
ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.
PRISM® CHAMPION PLUS
PRISM®
चैम्पियन सीमेंट
प्लस
Portland Pozzolana Cement (Fly Ash Based)
PRISM JOHNSON LIMITED
Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in
दूर की सोच®

Science House Medicals Pvt.Ltd.
Celebrating
25
YEARS EXPERIENCE
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023 GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5
Email : shbpl@rediffmail.com PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687